चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 16 अक्टूबर– 22 अक्टूबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

गड्ढे में सत्याग्रह, थाने में पिटाई, घर में नज़रबन्द, धरना तो कहीं मौत

ये देश है बदहाल किसानों का

“जयपुर में पिछले कई दिनों से किसान खुद को जीते जी गड्ढे में गाड़ कर अपनी जमीन बचाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं. मध्य प्रदेश केटीकमगढ़ में किसानों को पुलिस ने नंगा कर के पीटा. शिरडी में राष्ट्रपति द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केउद्घाटन के मौके पर उन किसानों को घर में नजरबन्द कर रखा गया, जिनकी जमीन इस एयरपोर्ट के लिए ली गई थी. दिल्ली से सटे नोएडा प्रशासनिक कार्यालय में अपनी जमीन के बदले में उचित मुआवजा और अधिकारों की मांग के लिए किसानों ने धरना दिया, तो महाराष्ट्र में खेतों में दवा का छिड़काव करते हुए 18 किसानों की मौत हो गई और 70 अस्पताल में भर्ती हैं. इन चार घटनाओं के जरिए हम आपको देश के किसानों की बदहाल स्थिति बताना चाहते हैं. इस कहानी को पढ़ने के बाद, आप खुद तय करें कि जय जवान, जय किसान का नारा लगाने वाले इस देश में आख़िर किसकी जय है और किसकी पराजय है.”

शशि शेखर

जब प्रधानमंत्री दिल्ली में कंपनी सेक्रेटरी की एक सभा में देश की आर्थिक स्थिति के गुलाबी आंकड़े पेश कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से सटे नोएडा विकास प्राधिकरण में सैकड़ों किसान धरना दे रहे थे और दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर जयपुर में 50 से अधिक किसानों ने खुद को जीते जी गड्ढे में गाड़ कर जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ आन्दोलन की मुनादी कर दी थी. तकरीबन उसी वक्त टीकमगढ़ में सैकड़ों किसानों को पुलिस नंगा कर के पीट रही थी. और इन सब के बीच, दिल्ली में पावर प्वायंट प्रजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंपनी सेक्रेटरीज को और मीडिया के लाइव भाषण के जरिए देश–दुनिया को ये बता रहे थे कि कैसे देश दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है.

ज़मीन समाधि सत्याग्रह

राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे गांव नींदड के सैकड़ों किसानों ने खुद को गड्ढे में गाड़ कर किसान आन्दोलन को एक नया रूप दिया है, वहीं ये तरीका यह भी बताता है कि जब आम आदमी की आवाज सरकारी संस्थाएं नहीं सुनती हैं, तो उन्हें क्या–क्या नहीं करना पड़ता है. इन किसानों ने अपने इस आन्दोलन को जमीन समाधि आंदोलन का नाम दिया है. किसानों ने उसी जमीन पर गड्ढे खोदकर अपना आन्दोलन शुरू किया, जिस जमीन को जयपुर विकास प्राधिकरण एक आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित कर रही है. करीब 51 खोदे गए गड्ढों में बैठकर पुरुष और महिलाएं अपना विरोध दर्ज कराने लगे. इनलोगों का कहना है कि जब तक जयपुर विकास प्राधिकरण अधिग्रहण के अपने फैसले को नहीं बदलती और इस अधिग्रहण को रद्द नहीं करती, तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा. चौथी दुनिया से बात करते हुए नींदड बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नागेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह आन्दोलन अब थमने वाला नहीं है. अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम इस आन्दोलन को आमरण अनशन में बदल देंगे.

20 ढाणी, 18 कॉलोनी, 12 हज़ार लोग प्रभावित

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने नींदड गांव की 1350 बीघा जमीन पर एक आवासीय योजना डेवलप करने की योजना बनाई है. वहीं, किसानों का कहना है कि एक तो उनके पास जमीन बहुत कम है और ये जमीन ही उनके जीने–कमाने का जरिया है, ऐसे में वे अपनी जमीन नहीं देंगे. किसानों का कहना है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए जो सर्वे किया है, वो सर्वे ही गलत है. इसी वजह से वे इस अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. इस योजना की वजह से नींदड गांव के करीब 20 ढाणी (टोला), 18 कॉलोनी और इस तरह तकरीबन 12 से 15 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं. नगेन्द्र सिंह शेखावत बताते हैं कि यहां के लोगों के पास मुश्किल से आधा बीघा से 1 बीघा जमीन है. यहां के लोग इसी जमीन पर खेती या पशुपालन कर अपना जीवनयापन करते हैं. ऐसे में अगर वह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कपास पर क़ब्रिस्तान बना यवतमाल

किसानों की आत्महत्या को लेकर बदनाम महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह किसानों की आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है. जी हां, ये हत्या ही है कि अच्छी उपज का लालच देकर किसानों को कीटनाशक के प्रयोग के लिए तैयार किया जाए, लेकिन उन्हें

उस कीटनाशक के कुप्रभाव के बारे में जागरूक नहीं किया जाय. कीटनाशक के दुष्प्रभाव के कारण विदर्भ के यवतमाल में पिछले दो हफ्ते में 19 किसानों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और 700 से ज्यादा किसान अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है. दरअसल, यवतमाल में बड़ी संख्या में किसान कपास की खेती करते हैं. कपास की खेती को गुलाबी कीड़े यानि पिंक बोलवर्म से खतरा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नोएडा प्राधिकरण की मनमानी सड़क पर किसान

क्या यह किसी दुर्भाग्य से कम है कि अपनी उन जमीनों के लिए मुआवजा मांगने पर सरकार किसानों पर मुकदमा दायर करा देती है, जिन जमीनों पर प्रोजेक्ट स्थापित कर प्राइवेट कम्पनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं. ये दुर्भाग्य इसी देश में देखने को मिल रहा है, वो भी

देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में. नोएडा प्राधिकरण द्वारा वर्षों पहले ली गई जमीनों का मुआवजा आज तक बाकी है, उल्टा प्रशासन किसानों को प्रताड़ित कर रहा है. किसान पिछले कई वर्षों से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती बनकर रह जाती है. 4 अक्टूबर को एक बार फिर हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे. भारतीय किसान यूनियन के मेरठ

(शेष पृष्ठ 2 पर)

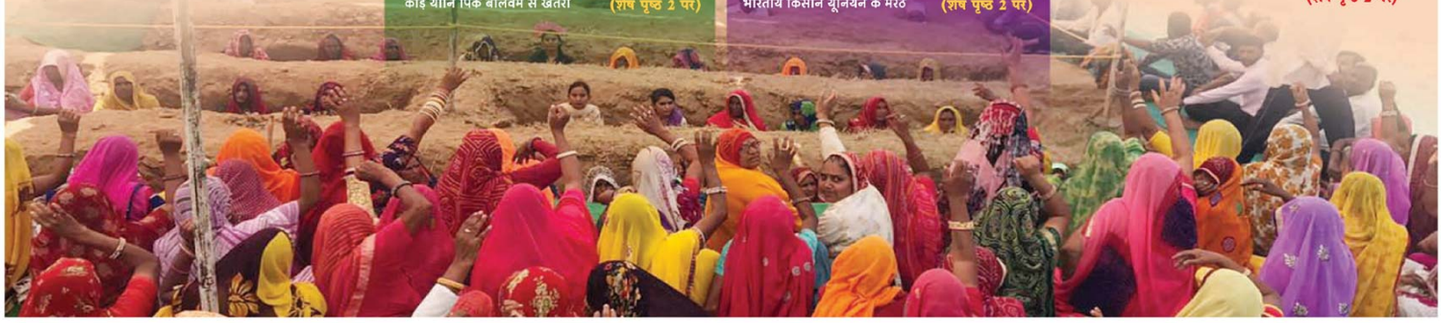

ये देश है बदहाल किसानों का

पृष्ठ 1 का शेष

जमीन भी उनसे छिन जाएगी तो लोगों का जीवन तबाह हो जाएगा. शेखावत बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 274 बीघा जमीन ही किसानों ने सरेंडर किया है. बाकी जमीन पर अभी तक जेडीए का कब्जा नहीं हुआ है. वे बताते हैं कि आन्दोलन शुरू होने के बाद जिन लोगों ने पहले जमीन सरेंडर किया था, वे भी अब जेडीए के विरोध में आ गए हैं. उनका कहना है कि हमारी कोई भी मांग मुआवजे से संबंधित नहीं है, हमें मुआवजा नहीं अपनी जमीन चाहिए. उन्होंने जेडीए पर ये भी आरोप लगाया कि जेडीए ने जमीन अधिग्रहण के लिए जो सर्वे किया है, वो किसानों के दादा–परदादा के नाम से किया है, क्योंकि जमाबन्दी में उनका ही नाम है. असलियत ये है कि परिवार बढ़ने से जमीन का टुकड़ा छोटा होता चला गया. आज तो यहां के किसानों के पास बमुश्किल 1 बीघा जमीन ही है. इतनी कम जमीन होने के बाद भी अगर सरकार उसे अधिग्रहित कर लेती है तो फिर बेचारे किसान कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि ये सभी जमीन खेती की है और खेती की जमीन का अधिग्रहण भी गलत है. इसके लिए कम से कम 80 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी है, जो जेडीए के पास नहीं है. हमारी मांग है कि इस अधिग्रहण को तत्काल निरस्त किया जाए. जमीन समाधि सत्याग्रह में 27 महिलाएं भी शामिल हैं. इस दौरान कुछ महिलाओं और पुरुष आन्दोलनकारियों की तबीयत भी बिगड़ गई, इसके बावजूद लोगों का हौसला बुलन्द है. उनका कहना है कि सरकार उनकी खेती की जमीन जबर्दस्ती ले रही है. वे खेती नहीं करेंगी तो जीएंगी कैसे? उनका ये भी तर्क है कि जेडीए की कई पूर्व योजनाओं में जमीन के प्लॉट अभी तक खाली पड़े हैं, फिर भी उनकी नजर हम गरीब किसानों की जमीन पर है.

किसानों ने नहीं लिया मुआवज़ा, कोर्ट में जमा

16 सितंबर को जब जेडीए ने आवासीय योजना के लिए एंट्री गेट बनाने के लिए सीकर रोड की तरफ 15 बीघा जमीन का कब्जा लेते हुए सड़क बनाई, तभी से इस अधिग्रहण से प्रभावित किसान आन्दोलन करने के लिए जमीन पर आ गए. किसानों ने इस नई सड़क को खोद दिया और गड्ढे बना कर जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दी. जेडीए के मुताबिक, 1350 बीघा जमीन में से करीब 500 बीघा जमीन पर कब्जा हो गया है. लेकिन अब भी 700 बीघा से अधिक जमीन किसानों के पास ही है. इन किसानों ने जेडीए द्वारा दिया गया मुआवजा अभी तक नहीं लिया है. आवासीय स्कीम के एंट्री प्वाइंट की 15 बीघा जमीन का मुआवजा भी किसानों ने नहीं लिया है. इसके बाद जेडीए ने मुआवजा राशि कोर्ट में जमा करा दिया. किसानों का मानना है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है. जेडीए तानाशाही कर रही है. नींदड बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान की भाजपा सरकार हमसे जमीन लेकर पूंजीपतियों को देना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे.

पूर्व की योजना अविकसित, नई की ज़रूरत क्यों

आन्दोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने नींदड के पास पहले भी किसानों एवं लोगों की जमीन अधिग्रहित कर आनंद लोक, स्वप्न लोक तथा रजत विहार जैसी आवासीय योजनाएं बनाई थी. आज भी वहां बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े हैं और वहां कोई परिवार नहीं रह रहा है. इनका कहना है कि पूर्व की उन योजनाओं का समुचित विकास आज तक नहीं हो पाया है. नींदड आवासीय योजना, जिसके लिए 1350 बीघा जमीन लेने की बात है, के मामले में, यहां के लोग पिछले सात वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन जब जेडीए ने सड़क आदि बनाकर कब्जे की कार्रवाई शुरू की, तब किसानों ने अपना आन्दोलन तेज कर दिया. ये अनिश्चितकालीन जमीन समाधि सत्याग्रह है. किसानों ने सुंदरकांड का पाठ एवं सद्बुद्धि यज्ञ भी किए, ताकि सरकार और जेडीए को सद्बुद्धि आए और वे किसानों की जमीन जबरन छीनने से बाज आएं. किसानों का मानना है कि इस आन्दोलन की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. महिलाएं भी ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही हैं. लेकिन सरकार और जेडीए को इसकी कोई चिंता नहीं है.

कपास पर क़ब्रिस्तान बना यवतमाल

पृष्ठ 1 का शेष

होता है. इन कीड़ों से कपास की फसल को बचाने के लिए किसानों को प्रोफेनोफॉस जैसे कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर कीड़े पूरी फसल को बर्बाद कर देते. कीड़ों की बर्बादी होगी या नहीं, ये तो बाद की बात है, अभी तो यह कीटनाशक किसानों की ही बर्बादी का कारण बन गया है. कीटनाशक का छिड़काव करने वाले किसान उसके जहर के प्रकोप में आ गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चाहता, तो शायद मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन किसानों पर अस्पतालों की कुव्यवस्था की दोहरी मार पड़ी और देखते-देखते 19 किसानों ने दम तोड़ दिया. गौर करने वाली बात है कि यवतमाल में कीटनाशक के दुष्प्रभाव के कारण पहली मौत 19 अगस्त को हुई थी. लेकिन उसके बाद भी इसे लेकर प्रशासन के स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, तो सरकार और प्रशासन की तंद्रा भंग हुई. राज्य सरकार ने आनन-फानन में सचिव स्तरीय जांच का आदेश दिया. किसानों द्वारा आवाज उठाने पर भी नदारद रहने वाले भाजपा विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मदन येरावार किसानों की मौत के बाद सामने आए और कहा कि किसानों और खेतिहर मज़दूरों को छिड़काव के लिए मास्क और दस्तानों का मुफ्त वितरण शुरू हो चुका है. गौरतलब है कि ये मास्क और दस्ताने अगर पहले वितरित किए गए होते तो किसानों के घर में यूं मातम न मनता.

टीकमगढ़: हक़ मांगा तो नंगा कर पीटा

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों को थाने में नंगाकर पीटा. सरकार तर्क दे रही है कि ये आंदोलनकारी किसान नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जो किसानों को भड़का रहे थे. हालांकि, यह सच है कि किसानों के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल था. कांग्रेस पार्टी के कई नेता 'किसान बचाओ-खेत बचाओ' आंदोलन में शरीक थे. किसान टीकमगढ़ जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के अलावा खराब फसलों का मुआवजा, बिजली बिल माफ करने और फसल बीमा राशि खातों में डाले जाने की मांग कर रहे थे. किसान 3 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे. वे चाहते थे कि कलक्टर अभिजीत अग्रवाल उनकी बात सुनें. आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक वे कलेक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे. तभी अचानक पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए. इस दौरान पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी. किसानों का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद जब वे अपने घर लौट रहे थे, तब पुलिस उन्हें जबरन उठाकर थाने ले गई. थाने में सबके सामने उन्हें नंगाकर पीटा गया और हवालात में बंद कर दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शन से लौट रहे किसानों की दो ट्रालियों को पुलिस ने जबरन रोक लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गई. जब पूर्व मंत्री बादवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, तब किसानों को छोड़ा गया. वहीं, एसपी कुमार प्रतीक बता रहे हैं कि किसानों को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया था, जिन्हें एक घंटे बाद छोड़ दिया गया. प्रशासन का ये भी कहना है कि पहले आंदोलन कर रहे किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी. किसान कलेक्टर के रवैये से बेहद नाराज हैं और उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले की जांच कर तीन दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के लिए केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी हालात जस-के-तस हैं. हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने फसल की लागत और बिक्री पर विचार करने के लिए एक आयोग का भी गठन किया है. लेकिन अगर वाजिब मांगों को लेकर किसानों की बेरहमी से पिटाई की जाए, तो क्या इससे सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े होते. अगर आंकड़ों पर गौर करें तो, पिछले 16 साल में मध्यप्रदेश में 21 हजार किसान खुदकुशी कर चुके हैं.

नोएडा प्राधिकरण की मनमानी सड़क पर किसान

पृष्ठ 1 का शेष

मंडल के अध्यक्ष बेगराज गुर्जर ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि 'नोएडा अथॉरिटी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, जैसे कि हम इनसे इनकी जमीनों के लिए पैसा मांग रहे हैं. अथॉरिटी ने आज तक आबादियों का निस्तारण नहीं किया है, उल्टे किसानों को भूमाफिया बताकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया. हमारे मकानों को तोड़कर जमीनों को छीना जा रहा है. हद तो ये है कि नोएडा अथॉरिटी के वर्तमान अधिकारी न तो पूर्व अधिकारियों का निर्णय मान रहे हैं और न ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को. बेगराज गुर्जर ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे चुका है. कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द जमीनों को अन-लीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.' इसमें एक तथ्य ये भी है कि कोर्ट ने 1976 में ही किसानों को 297 रुपए प्रतिगज के हिसाब से मुआवजा देने को कहा था, लेकिन सैकड़ों किसानों को आजतक मुआवजा नहीं मिला है. इनकी मांग है कि नोएडा के किसानों की आबादी को 'जहां है जैसी' के आधार पर छोड़ा जाय और जमीनों पर चल रहे सभी मुकदमों को वापस लिया जाय. जमीन लेते समय इन किसानों से नोएडा प्रधिकरण ने वादा किया था कि इन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब इन किसानों की मांग है कि चूंकि नोएडा प्राधिकरण उनकी जमीनों पर बसा है और नौकरियों पर पहला अवसर इन किसानों के बच्चों का है. इसलिए नोएडा प्राधिकरण और मेट्रो में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाय. इसके अलावा कई मांगों को लेकर आंदोलनरत इन किसानों से नोएडा अथॉरिटी के चैयरमैन ने मुलाकात की और समस्याओं पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया. इधर इन किसानों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें नहीं मानी गईं और हमें हमारा हक नहीं मिला, तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे.

क्या सरकार प्रॉपर्टी डीलर है

जाहिर है, जमीन एक ऐसी संपत्ति है, जिसे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है. यह ज़मीन ही है, जो इस देश की अस्सी फ़ीसदी आबादी को रोजी-रोटी-कपड़ा-मकान मुहैया कराती है. लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण और निजीकरण की आंधी आने के साथ ही किसानों से जमीन छिनने का प्रयास किया जाने लगा. यह सरकार, नौकरशाहों और उद्योगपतियों की साठ-गांठ की वजह से ही संभव हो पाता है. कभी सेज के नाम पर, कभी औद्योगिक विकास के नाम पर, टाउनशिप के नाम पर, यहां तक कि सड़क बनाने के नाम पर और अब नए जमाने में पीपीपी मॉडल और आवासीय योजना के नाम पर सरकार, किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगी. इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एक ही तरीके से काम करती है. सरकारें पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर बन गई हैं. गरीब किसानों से सरकार कौड़ियों के भाव जमीन खरीदती है और फिर उसे पूंजीपतियों के हाथ सौंप देती है. अतीत में, इसी वजह से हमने भट्टा पारसौल, सिंगुर और नंदीग्राम की घटना देखी है. आज, जयपुर की घटना भी उसी की पुनरावृत्ति है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 33
16 अक्टूबर– 22 अक्टूबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–65500786, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16++ (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यूनिवर्सल बेसिक इनकम बनाम वोटरशिप योजना

भरत गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही विदेशों से काला धन लाएंगे और देश के सभी नागरिकों के खाते में 1500000(15 लाख) रुपए जमा कराएंगे. सत्ता में आते ही उन्होंने जीरो बैलेंस पर देश के नागरिकों से खाता खोलने को कहा. करोड़ों की संख्या में जनधन के नाम से लोगों ने खाता खोला भी, इस उम्मीद में कि शायद उनके खाते में पैसा आएगा, लेकिन 3 साल तक पैसा नहीं आया. उत्तर प्रदेश के गत चुनाव अप्रैल 2017 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार जनता को भरोसा दिलाया कि वे 15 लाख तो जमा नहीं करेंगे, लेकिन देश के गरीबों के खाते में 15 सौ रुपए हर महीने पेंशन जमा कराएंगे. इस पैसे को उन्होंने यूरोप की एक शब्दावली दी, जिसको कहा जाता है 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' यूबीआई.

उत्तर प्रदेश चुनाव जीत लेने के बाद उन्होंने मुकरते हुए यह कहा, 'देश की जनता को पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को देश से प्रेम है.' लेकिन मेनस्ट्रीम की मीडिया द्वारा लोगों को सही जानकारी नहीं पहुंचाये जाने के कारण देश में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की बेसिक इनकम की कल्पना इन पंक्तियों के लेखक की एक योजना, वोटरशिप योजना से पैदा हुई है. अन्यथा गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए वे जनधन जैसी कोई योजना अपने प्रदेश में लागू करते. इन पंक्तियों के लेखक 1998 से लगातार यह आवाज उठाते रहे हैं विदेश में मशीनों के परिश्रम से जो पैदावार हो रही है और उस पैदावार के बदले जो नोट छप रहे हैं, उसमें वोटरों को हिस्सा दिया जाए. वेतन और पेंशन के माध्यम से देश में सरकार चलाने वाले लोगों को खजाने में हिस्सा मिलता है, तो वोट देकर सरकार बनाने वालों को भी खजाने में हिस्सा दिया जाए. देश के प्राकृतिक संसाधनों- पानी, धूप, कोयला, लोहा, बालू, अभ्रक, सोना, चांदी, हीरा... आदि-आदि चीजों के बदले सरकार नोट छापती है. इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक उत्पादों के बदले छपे हुए नोट में देश के वोटरों को हिस्सा दिया जाए.

अन्ना आंदोलन से रची साज़िश

यह बात 137 सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में सन 2005-2008 के बीच उठाया. सैकड़ों अन्य सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, जिसमें से कई आजकल मोदी सरकार में मंत्री हैं और कई कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं. वोटरशिप के प्रस्ताव पर राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी कायम हुई और 2 दिसंबर 2011 को वोटरशिप का प्रस्ताव संसद की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूर कर लिया. उस समय यह मांग की गई थी कि देश की औसत आमदनी की आधी रकम वोटरों को दी जाए. यह रकम उस समय 3500 बनती थी, लेकिन अब यह रकम बढ़कर 5896 रुपए हो गई है. वोटरशिप योजना को अमल में लाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने चुपके-चुपके मन बनाया, इसीलिए उसने लोगों का बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड योजना चलाई. सब्सिडी नगद देने की योजना चलाई, जिसके तहत गैस सिलेंडर रखने वालों को आज उनके खाते में पैसा मिल रहा है. किसानों को फ़र्टिलाइज़र के बदले सीधे जमीन के अनुपात में नकद देने की भी आवश्यकता है. सरकार इसपर भी काम कर रही है. लेकिन कांग्रेस चुपके-चुपके जो काम कर रही थी, उसे देश के धनवान लोग समझ गए और उन्हें मालूम हो गया कि देश के वोटरों का जो पैसा उनके पास पहुंचा है, कांग्रेस उसे वसूल कर वोटरों के पास पहुंचा देगी, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से हटाना जरूरी हो गया. अन्ना आंदोलन इसी साजिश के तहत रचा गया था, जिसमें सैकड़ों टीवी चैनल पैसा देकर लगाए गए. जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले, तो यह लोभ उनके मन में भी रहा कि जिस तरह कांग्रेस ने देश में वोटरशिप योजना लागू करने का मन बनाया था, उसी तरह वो भी वोटरशिप योजना को लागू करें. उन्होंने इसके लिए लोगों को बैंक खाता खोलने को कहा, जिसको जनधन योजना कहा गया और उन्होंने 15 सौ रुपए लोगों के बैंक खाते में बिना कुछ काम किए और बिना किसी परीक्षा के देने की घोषणा की. लेकिन यह श्रेय कहीं वोटरशिप योजना के जनक यानि इन पंक्तियों के लेखक (भरत गांधी) को ना मिल जाए और उनके समर्थक सांसदों को यह श्रेय मिल जाए, इसलिए उन्होंने इसके लिए यूरोप से आयातित एक नया नाम रखा, जिस को कहा गया 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' यूबीआई. आज देश के लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि वोटरशिप सही है या नरेंद्र मोदी जी की 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' सही है. इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देश के नागरिकों के सामने रखा जाना चाहिए. वास्तव में यूनिवर्सल बेसिक इनकम कल्याणकारी राज्य और समाजवादियों द्वारा जनता पर की गई दया है और उनको भीख स्वरूप एक डॉलर रोज देने का प्रस्ताव है. लेकिन वोटरशिप सरकार द्वारा जनता पर की गई दया नहीं है, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों से पैदा हुआ विचार है. यह जनता का अधिकार है, जिसमें वह सरकार बनाने की फीस ले सकता है, मशीनों की मेहनत में हिस्सा ले सकता है और प्राकृतिक संसाधनों में नकद हिस्सा ले सकता है.

वोटर्स को मिलना चाहिए समृद्धि में हिस्सा

यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन तीन बातों में से केवल एक बात की वकालत करती है कि 'प्राकृतिक संसाधनों में सबका हिस्सा है.'

यह बात 137 सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में सन 2005-2008 के बीच उठाया. सैकड़ों अन्य सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, जिसमें से कई आजकल मोदी सरकार में मंत्री हैं और कई कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं. वोटरशिप के प्रस्ताव पर राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी कायम हुई और 2 दिसंबर 2011 को वोटरशिप का प्रस्ताव संसद की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूर कर लिया.

यूनिवर्सल बेसिक इनकम यह नहीं बताती है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में वोटर राज्य रूपी कंपनी का मूल स्वामी और शेयर होल्डर होता है, इसलिए कंपनी के लाभ में जिस तरह शेयर होल्डरों को हिस्सा मिलता है, उसी तरह एक लोकतांत्रिक राज्य के स्वामियों को यानि वोटरों को देश की समृद्धि में हिस्सा मिलना चाहिए. यदि देश की अमीरी बढ़े, तो हर एक वोटर की अमीरी बढ़नी चाहिए और देश की अमीरी घटे तो हर एक वोटर की अमीरी घटनी चाहिए. वोटरशिप देश के विकास से वोटरों का रिश्ता जोड़ता है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसा नहीं करता. वह केवल इतना करता है कि नागरिकों को खाने-पीने व जीने के लिए न्यूनतम जितने पैसे की जरूरत है, वह उनके खाते में बिना काम के और बिना परीक्षा के भेजा जाए. वोटरशिप भी यही चाहता है कि बिना काम के और बिना परिश्रम के वोटरों के खाते में वोटरशिप की रकम लगभग 5896 रुपए भेजी जाए. क्योंकि यह प्राकृतिक संपत्तियों का किराया है, यह मशीनों द्वारा पैदा किए गए धन दौलत में वोटरों का हिस्सा है और यह सरकार बनाने की फीस और सरकार रूपी बिल्डिंग का इस बिल्डिंग के मालिक को मिलने वाला किराया है. जितना तार्किक वोटरशिप है, उतना तार्किक और उतना लोकतांत्रिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम नागरिकों के स्वाभिमान को बढ़ाता नहीं है, लेकिन वोटरशिप नागरिकों के स्वाभिमान को भी बढ़ाता है. नागरिकों में यह एहसास कराता है कि यह देश उनका अपना है और उनकी अपनी सरकार का लाभांश उनको मिल रहा है. यह देश के प्रति बहुत अंतरतम अटैचमेंट पैदा करता है, जो बेसिक इनकम नहीं करता. बेसिक इनकम की रकम भी इतनी छोटी है कि उससे इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन इतनी रकम से वह कुछ कर नहीं सकता. बेसिक इनकम की समस्या यह भी है कि यह सब को नहीं मिलेगी. इसलिए बेसिक इनकम कार्यक्रम के पात्रता और अपात्रता करने का अधिकार प्रशासन को होगा और प्रशासन बेसिक इनकम का प्रमाण पत्र केवल उसी को देगा जिससे रिश्वत पाएगा. इस प्रकार जरूरतमंद आदमी रिश्वत देने में नाकाम हो जाएगा और बेसिक इनकम की रकम उन लोगों के खाते में चली जाएगी जिनको वह मिलनी नहीं चाहिए. वोटरशिप वास्तव में यूनिवर्सल है, वास्तव में बेसिक है और वास्तव में इनकम है, क्योंकि यह हर वोटर को दी जानी है. इसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना है. इसमें प्रशासन के रिश्वत लेने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है और जरूरतमंद तक यह रकम पहुंच सकती है. वोटरशिप योजना लागू करने में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना लागू करने में भ्रष्टाचार रोका नहीं जा सकता. ब्राज़ील सरकार ने यह गलती की है. उसने डेमोग्रेंट के नाम से वोटरशिप योजना को 2003 में लागू किया, लेकिन आज इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है. इसीलिए मैंने (लेखक) संसद में जो प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा गया था कि आयकर देने वालों को इस योजना से भले अलग रखा जाए, बाकी अन्य किसी को अलग नहीं रखा जाना चाहिए.

वोटरशिप से मिटेगी आर्थिक असमानता

अगर वोटरशिप योजना लागू हो जाए, तो देश का हर बच्चा पढ़ेगा, हर लड़की पढ़ेगी, चाहे वह अमीर की हो चाहे गरीब की. जब लड़कियां उच्च शिक्षा लेंगी तो शादी के बाद अधिक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होंगी. इससे जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा. आज जो बेरोजगार लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ बंद हो गया है और दिमाग भी बुझता जा रहा है, वोटरशिप मिलते ही उनके दिमाग सक्रिय हो जाएंगे और हाथ का काम भले ही ना मिले लेकिन दिमाग काम करने लगेगा और आज के करोड़ों बेरोजगार लोग उत्पादन करने लगेंगे. बुजुर्गों को जब पैसा मिलेगा तो उनका हर बच्चा चाहेगा कि उनके मां-बाप उनके अपने घर में रहें. गरिमा और इज्जत के साथ जीने वाले लोग गरिमा और इज्जत के साथ ही अपनी अंतिम सांस लेंगे. वोटरशिप मिलेगी तो आर्थिक विषमता पर नियंत्रण भी लग जाएगा. अब खरबपतियों के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद विधायक की मंडी चलाएं. उनकी खरीद-बिक्री करें और किसी सरकार को गिराने का और कठपुतली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ले पाएं. लोकतंत्र वास्तव में जनता का तंत्र बन जाएगा. इस प्रस्ताव के सैकड़ों फायदे हैं, जिनको देखकर संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप और अर्थशास्त्र के जाने माने जानकार डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने राज्य सभा सचिवालय में वोटरशिप के पक्ष में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया और वित्त मंत्रालय के आईएएस अधिकारियों का विरोध नाकाम कर दिया. परिणामस्वरूप वोटरशिप का प्रस्ताव राज्य सभा सचिवालय में 2 दिसंबर 2011 को मंजूर हो गया, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने वोटरशिप के लिए कोई कानून नहीं बनाया. न तो कांग्रेस ने बनाया, न ही मोदी सरकार ने. वास्तव में 2019 का चुनाव वोटरशिप के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और सभी पार्टियों को अपना मत खुलकर व्यक्त करना चाहिए कि वह देश के नागरिकों को वोटरशिप का अधिकार देंगे या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का झुनझुना? ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं, वोटरशिप स्कीम ज़रूरी है : भरत गांधी

चौथी दुनिया के संवाददाता *शफ़ीक आलम* ने प्रख्यात राजनीतिक सुधारक श्री भरत गांधी से वोटरशिप स्कीम पर लंबी बातचीत की. प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश...

सबसे पहले ये बताएं कि वोटरशिप स्कीम और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या फर्क है?

देखिए, प्रोफेसर जेएस मिल और कार्ल मार्क्स ये दोनों समकालीन थे. दोनों एक बात पर राजी थे कि राज्य गरीबों पर जुल्म ढा रहा है. मार्क्स कहते थे कि इस जुल्म को रोकने का तरीका ये है कि गरीबों को संगठित होकर राज्य पर कब्जा कर लेना चाहिए, लेकिन मिल ये कहते थे कि राज्य पर गरीब कब्जा कर लेंगे तो जुल्म दूसरों पर होने लगेगा. तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सोच है या हमारी वोटरशिप की सोच है ये जॉन स्टूअर्ट मिल की परंपरा से अलग है. इसके जो दुनिया के सबसे बड़े वकील हुए, वो ब्राजील के एक सांसद सकलेसी थे. उन्होंने संसद में ताउम्र इसकी लड़ाई लड़ी. अंत में ब्राजील दुनिया का सबसे पहला देश बना, जिसने सन् 2003 में इसे लागू किया.

ब्राजील में ये प्रयोग कितना सफल रहा है

ब्राजील में ये प्रयोग सफल रहा, लेकिन उन्होंने ये अधिकार अमीरों को नहीं दिया. वोटरशिप और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में यही अंतर है. हम ये कहते हैं कि वोटरशिप का अधिकार सबको है, चाहे वो टाटा हो चाहे बिड़ला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो. यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो ब्राजील में लागू हुआ, उससे वहां भ्रष्टाचार बढ़ा. लेकिन भ्रष्टाचार के बाद भी जनता का जीवन सुखमय हुआ. आज ब्राजील सरकार उसको खत्म करने की स्थिति में नहीं है. वहां उत्पादन बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े. मार्केट में जो मंदी की समस्या दुनिया झेल रही थी, वह ब्राजील में छू तक नहीं गई, क्योंकि पैसा पब्लिक के पास था. ब्राजील मंदी का शिकार नहीं हुआ. वहां दरअसल उसका नाम वोटरशिप नहीं है. उसका नाम है डीमोग्रांट, यानि पब्लिक का ग्रांट. डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल ग्रांट होनी चाहिए.

आपने अपनी स्कीम का नाम वोटरशिप रखा है. ये सिर्फ वोटर से ही रिलेटेड क्यों है, ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है, सबके लिए क्यों नहीं?

वास्तव में ये बात मेरे दिमाग में आई थी, जब हम मशीनों के पैसे को बांटने की बात करेंगे तो पैसा बच्चे को जन्म लेते ही देना होगा. बच्चा पैसा लेगा कैसे? उसका पैसा मां-बाप के पास जाएगा. मां-बाप के पास जाएगा तो भारत जैसे अशिक्षित देश में यहां कुछ मां-बाप ये सोचेंगे कि ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो ज्यादा वोटरशिप आएगी, तो उन्हें बच्चा पैदा करने का इंसेटिव मिल जाएगा. इसलिए मैंने वोटरशिप को वोटर से लिंक किया, नागरिक और बच्चे से नहीं.

वोटरशिप स्कीम कितना व्यावहारिक है? क्या ये संभव है? सरकार अगर करना चाहती है तो उसका जो भार होगा, व्यय कर पाएगी या नहीं कर पाएगी?

1965 में लालबहादुर शास्त्री जी ने जिला पंचायत के चेयरमैन को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक फंड का हिस्सा दिया कि आप मिलकर विकास का काम करो. जब इंदिरा गांधी जी 1972 में आयीं तो इंदिरा जी ने कहा कि पैसा और नीचे जाना चाहिए. उन्होंने देशभर में ब्लॉक बनवाया. पैसा सीधे बीडीओ को और ब्लॉक प्रमुख के खाते में भेजा गया. जब राजीव गांधी जी 1985 में आए तो पंचायती राज कानून बना. पैसा गांव के प्रधान तक पहुंच गया. अब मैं ये कह रहा हूं कि पैसा सीधे परिवार तक दे दीजिए. वोटरशिप आंदोलन के कारण सिद्धांत रूप में मनमोहन सिंह सरकार ने माना कि जो सब्सिडी का पैसा हम लोगों को देंगे, बेनिफिशियरी के खाते में देंगे. फिर गैस सिलेंडर का पैसा लोगों के एकाउंट में जाने लगा. इसके बाद अब किसानों को फर्टिलाइजर का पैसा देने की भी बात चल रही है. राशन का पैसा अब लोगों के एकाउंट में दिया जाएगा. अगर मैं 2001-02 में ये आवाज देश में नहीं उठाता तो आज भी पुराने ढर्रे पर देश चल रहा होता.

आपके वोटरशिप स्कीम को सुभाष कश्यप और अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला ने कैसे देखा था और क्या बातें की थीं?

दरअसल 2005-06 में सैकड़ों सांसदों ने वोटरशिप स्कीम पर लिखित नोटिस दे दी तो सरकार के कान खड़े हुए. सरकार ने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को, वित्त मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को. इलेक्शन कमीशन ने ये लिखकर भेज दिया कि वोट का अधिकार आर्टिकल 26, 27, 28 में बेशर्त है. उसको शर्तों से जोड़ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 326, 327, 328 का उल्लंघन है. अब चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो लिखकर दे रही है कि अगर वोटरों को वोटरशिप मिलेगा तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है. तब राज्यसभा सचिवालय के लिए जरूरी हो गया कि संविधान विशेषज्ञ से रिपोर्ट मंगाई जाए. इसके बाद डॉ. सुभाष कश्यप की रिपोर्ट मंगाई गई. डॉ. सुभाष कश्यप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वोटरशिप का जो पैसा देना है, वो वोटर के अधिकार को कम नहीं कर रहा है, वोटर के अधिकार को बढ़ा रहा है. भरत झुनझुनवाला ने अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से उसकी विवेचना की. उन्होंने ये लिखा कि विश्व अर्थव्यवस्था और उदारीकरण की मजबूरी में काम मशीनें कर रही हैं. बाजार के वैश्वीकरण के कारण हम मशीनों को नहीं हटा सकते. जब मशीन रहेगी तब बेरोजगारी भी रहेगी. अगर बेरोजगारी रहेगी, तो पैसा सीमित लोगों के हाथ में आ जाएगा तो मंदी आ जाएगी. भरत गांधी जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. उनका कहना था कि अगर 6000 रुपया लोगों को मिलने लगा, तो गांव में पान या चाय की दुकान करने वाला, जो आज एक दिन में 100 रुपया कमा रहा है, वो एक दिन में 1000 रुपया कमाएगा. तो इस तरीके से किसान का फायदा, मजदूर का फायदा, दुकानदार का फायदा, व्यापारी का फायदा होगा.

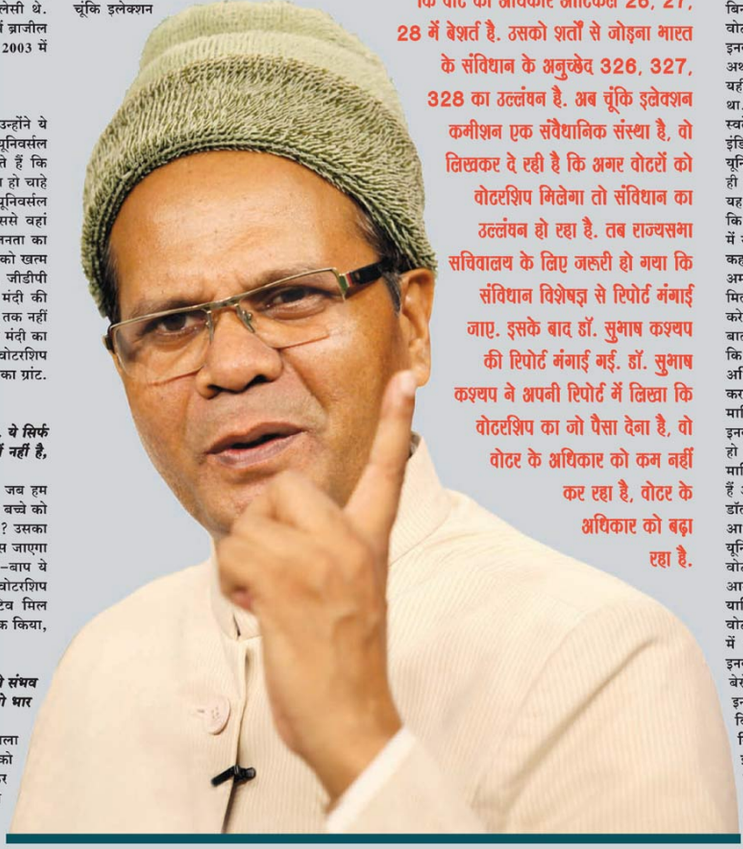

> दरअसल 2005-06 में सैकड़ों सांसदों ने वोटरशिप स्कीम पर लिखित नोटिस दे दी तो सरकार के कान खड़े हुए. सरकार ने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को, वित्त मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को. इलेक्शन कमीशन ने ये लिखकर भेज दिया कि वोट का अधिकार आर्टिकल 26, 27, 28 में बेशर्त है. उसको शर्तों से जोड़ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 326, 327, 328 का उल्लंघन है. अब चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो लिखकर दे रही है कि अगर वोटरों को वोटरशिप मिलेगा तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है. तब राज्यसभा सचिवालय के लिए जरूरी हो गया कि संविधान विशेषज्ञ से रिपोर्ट मंगाई जाए. इसके बाद डॉ. सुभाष कश्यप की रिपोर्ट मंगाई गई. डॉ. सुभाष कश्यप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वोटरशिप का जो पैसा देना है, वो वोटर के अधिकार को कम नहीं कर रहा है, वोटर के अधिकार को बढ़ा रहा है.

इसपर एक बड़ा सवाल उठ सकता है कि अगर हम किसी को फ्री में पैसा देंगे, तो कोई काम नहीं करना चाहेगा.

ये सवाल मुझे बहुत फेस करना पड़ता है. मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वोटरशिप का पैसा अगर पांच हजार, छह हजार लोगों के खाते में डाल दिया जाए तो इसके दो तरीके हैं. एक तो करके देखो. पहले देखो कि वो निकम्मा होता है या नहीं होता है. पहले देकर देखो. लेकिन आप कहें कि हम इतने पैसों का क्यों नुकसान करें, तो ब्राजील में देखो. ब्राजील में लोग निकम्मे हो गए क्या? ब्राजील की इकोनॉमी और बूम कर गई. नामीबिया में देखो, नामीबिया में तो 100 में 100 आदमी शराबी है. लेकिन, नामीबिया में चमत्कार हुआ. जब वोटरशिप का पैसा वहां मिलने लगा, तब वहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में बैलों का रेट आसमान छूने लगा. मतलब बैलों की कीमत बारह से पंद्रह गुना बढ़ गई और गाय दूंहनी मुश्किल हो गई. बेचारे कुदाल फावड़ा से खेती करते थे, जब उन्हें पैसा मिला तो उन्होंने सबसे पहले सोचा हल और बैल से खेती करें. वहां लोग निकम्मे नहीं हुए, बल्कि ज्यादा उत्पादक हो गए.

आपने बताया कि संसद में अच्छे खासे सदस्यों का आपको समर्थन मिला. कांग्रेस पार्टी की नीयत भी इसमें साफ है, भाजपा की नीयत भी साफ है. मोदी सरकार ने एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रस्ताव पेश किया है. उसमें और वोटरशिप में जो आपने प्रस्ताव रखा है, दोनों में क्या फर्क है? 1500 रुपए की प्रस्तावित राशि है यूनिवर्सल इनकम में.

पहले तो मैं शब्दों का फर्क बता दूं कि वोटरशिप स्वदेशी है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम विदेशी है. ये विदेश से लाया हुआ शब्द है. दोनों में समानता ये है कि जरूरतमंद लोगों को कुछ नगद पैसा देना है, कैसे देना है, बिना काम के देना है और बिना किसी परीक्षा के देना है. वोटरशिप का भी यही मतलब है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी यही मतलब है. इसको कुछ लोग बीआई अर्थात बेसिक इनकम ही बोलते हैं. दोनों का मतलब यही है. मोदी जी के पास पहले से वोटरशिप शब्द था. चूंकि उनको विदेश से ज्यादा प्यार है, वे शुरू से स्वदेशी के विरोधी हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं मेक इन इंडिया. अब अर्थ देखिए, अर्थ ये है कि वोटरशिप और यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये दोनों ही चीजें समानता में एक ही हैं कि लोगों को पैसा मिलने वाला है. लेकिन अंतर यह है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में सरकार तय करेगी कि किसको दें और किसको नहीं दें. वोटरशिप के मामले में सरकार का ये अधिकार समाप्त कर दिया गया है. ये कहा गया है कि वोटरशिप हर वोटर को मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब. यूनिवर्सल बेसिक इनकम में किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह जिले का कलेक्टर तय करेगा. ऐसे में वह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेगा. दूसरी बात, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का यूरोपियन कंसेप्ट है कि एक डॉलर रोज दिया जाए. हम ये पूछते हैं कि किस अधिकार से एक डॉलर? लोकतंत्र में जनता चीजें तय करती है, सरकार तो प्रबंधक है. जनता मालिक है. हमें मालिक की भूमिका में छोड़िए. तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है. इसमें सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि मैं मालिक हूं और देश के गरीब, परेशान व बेबस लोग प्रजा हैं और प्रजा की जरूरत राजा तय करने जा रहा है एक डॉलर रोज. एक डॉलर रोज क्यों, दो डॉलर क्यों नहीं, आधा डॉलर क्यों नहीं? इस बात का कोई जवाब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सिद्धांतकारों के पास नहीं है. वोटरशिप के सिद्धांतकार कहते हैं कि देश में औसत आमदनी का शत प्रतिशत लोगों के पास जाना चाहिए यानि मालिकों के पास. वोटरशिप भ्रष्टाचार मुक्त है, वोटरशिप सैद्धांतिक है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से गरीबी नहीं जाएगी, वोटरशिप से गरीबी और बेरोजगारी गारंटी से चली जाएगी. यूनिवर्सल बेसिक इनकम से गरीबी और बेरोजगारी नहीं जाएगी. आर्थिक विषमता कंट्रोल होगी वोटरशिप से और आर्थिक विषमता यूनिवर्सल बेसिक इनकम से कंट्रोल नहीं होगी. इसलिए जो स्वदेशी प्रस्ताव है, वो विदेशी प्रस्ताव से सौ गुना अच्छा है.

देश की जीडीपी पर नजर डालें तो उसमें सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा सबसे ज्यादा है. आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर इंसेंटिव है. तो क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि वोटरशिप तथा बेसिक इनकम जैसी स्कीम को अब लागू करना अनिवार्य हो गया है?

इस पर मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है. इसमें रत्ती भर कंफ्यूजन नहीं है. एक मशीन आती है. मोबाइल आया, उसने रोजगार दिया. आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल ने रोजगार नहीं दिया. आज गली-गली मोबाइल बनाने वाले हैं, लेकिन मोबाइल ने जो टेलीफोन तार वाला सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया. आप एक सर्वे करिए कि कितने लोगों को मोबाइल से रोजगार मिला और लैंडलाइन से जिनका फोन चलता था, कितने लोग टेलीफोन सेक्टर में काम करते थे, उन सब लोगों के काम खत्म हो गए. आप पाएंगे कि पांच लोगों को मोबाइल में रोजगार मिला, तो 95 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों का रोजगार चला गया. हर सेक्टर में यही हुआ है. आज जुलाहे हैं, पहले कपड़ा बनाते थे. कई करोड़ जुलाहों का कपड़े से रोजगार चलता था. आज मशीन आ गई तो कई करोड़ जुलाहों का काम खत्म करके 10 हजार लोगों को नौकरी मिली. मेरा कहना है दोनों के बीच बैलेंस बनाइए. मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर मशीनों का इनकम आपने लोगों में नहीं बांटा, तो आनेवाले समय में भारी खून-खराबा होगा. इतना ही नहीं, विश्व बैंक की रिपोर्ट पढ़िए. वर्ल्ड बैंक ने साफ-साफ कहा है कि भारत में दो साल के अंदर 69 प्रतिशत रोजगार समाप्त हो जाएंगे. ये भरत गांधी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि ये अथॉरिटी है वर्ल्ड बैंक. विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम संसार के सभी देशों को तत्काल लागू करना चाहिए, लेकिन भारत में वोटरशिप स्कीम ही अंत में कारगर सिद्ध होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार में डूबा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सत्याग्रह पर बैठे छात्र और शिक्षक

कुलपति की मनमानी से भड़का आंदोलन

कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल के व्यवहार को लेकर कभी नेताओं से तो कभी बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से विवाद होता रहा है. शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बहाली में धांधली और नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियुक्त करने का आरोप लगता रहा. क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने, बिहारियों को खुलेआम विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ने, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग, महिलाकर्मियों से दुर्व्यवहार की शिकायत करवाने का भय दिखाकर इस्तीफा लेने जैसा आरोप कुलपति पर लगता रहा है. लेकिन पावर और राजनैतिक पहुंच की बदौलत ये बातें विश्वविद्यालय परिसर में ही दब के रह जाती थीं. इसके पूर्व भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संदीप कुमार को भयाक्रांत कर उनसे जबरन इस्तीफा लेकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. गौर करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय से निकाले गए तीनों शिक्षक बिहार के ही हैं.

राकेश कुमार

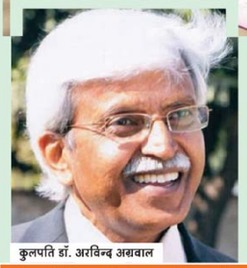

कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल

सूत्रों की मानें तो आन्दोलन से झल्लाए कुलपति डॉ. अग्रवाल ने कार्यरत शिक्षकों को भी अल्टीमेटम दिया है कि जो भी निष्कासित शिक्षकों के साथ दिखेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं होगा. इसके बावजूद आन्दोलन रुकने की बजाय तेज होता जा रहा है. विजयादशमी के दिन छात्र संगठनों ने कुलपति के पुतला का भी दहन किया. वहीं गांधी जयन्ती के दिन छात्र राजद के सदस्यों ने मीनाबाजार चौक स्थित गांधी टावर के समक्ष भूख हड़ताल की. शाम में राजद विधायक राजेन्द्र कुमार ने आन्दोलनकारी छात्रों का अनशन तुड़वाया. छात्रों की मांग है कि कुलपति डॉ. अग्रवाल को अविलम्ब हटाया जाए, ताकि कैम्पस में शैक्षणिक माहौल बन सके.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बाद अब बिहार का महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय सुर्खियों में है. बापू की कर्मभूमि चम्पारण की धरती पर महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक सत्याग्रह पर बैठ गए हैं. दो शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद आन्दोलित शिक्षकों और छात्रों को स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय में हुए घोटालों और मनमानी का राज परत दर परत खुलता जा रहा है.

जहां पूरा देश महात्मा गांधी की जयन्ती मना रहा है, वहीं सत्याग्रह की धरती पर छात्र और शिक्षक न्याय की मांग कर रहे हैं. चम्पारण में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष कार्यक्रम चल रहा है, वैसे में महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल के नादिरशाही रवैये से आतंकित छात्रों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब दो शिक्षकों डॉ. शशिकान्त रे और डॉ. अमित रंजन को एकाएक बर्खास्तगी का पत्र थमा दिया गया. पत्र में कहा गया है कि अधिशाषी समिति द्वारा 27 सितम्बर की बैठक में कार्य की समीक्षा के दौरान महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया है. बाद में बताया गया कि वर्ग में विलम्ब से आने और नियमों के पालन में लापरवाही के आरोप में हटाया गया है.

बोया जा रहा क्षेत्रीयता का ज़हर

वर्षों के संघर्ष के बाद पूर्वी चम्पारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में स्थापित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही विवादों में घिरा रहा है. कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल के व्यवहार को लेकर कभी नेताओं से तो कभी बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से विवाद होता रहा है. शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बहाली में धांधली और नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियुक्त करने का आरोप लगता रहा. क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने, बिहारियों को खुलेआम विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ने, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग, महिलाकर्मियों से दुर्व्यवहार की शिकायत करवाने का भय दिखाकर इस्तीफा लेने जैसा आरोप कुलपति पर लगता रहा है. लेकिन पावर और राजनैतिक पहुंच की बदौलत ये बातें विश्वविद्यालय परिसर में ही दब के रह जाती थीं. इसके पूर्व भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संदीप कुमार को भयाक्रांत कर उनसे जबरन इस्तीफा लेकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. गौर करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय से निकाले गए तीनों शिक्षक बिहार के ही हैं.

परिचितों के लिए नियमों का उल्लंघन

वस्तुत: केविवि में व्याप्त भ्रष्टाचार को दबाने के लिये सोची-समझी रणनीति के तहत स्थानीय लोगों को हटाने की साजिश चल रही है. केविवि के भ्रष्टाचार और तीन शिक्षकों को हटाने में कुलपति डॉ. अग्रवाल के मुख्य सहयोगी डॉ. आशुतोष प्रधान और डॉ. दिनेश हुड्डा बताए जाते हैं. इन दोनों को कुलपति अपने पूर्व कार्यस्थल हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय से लेकर आए हैं. हिमाचल प्रदेश केविवि में भी डॉ. अग्रवाल के मनमाने निर्णय और कपटी व्यवहार के किस्से आम हैं. ऐसे में कुछ शीर्षस्थ राजनेताओं और केन्द्रीय मंत्रियों की छत्रछाया में डॉ. अग्रवाल निरंकुश होते चले गए.

केविवि में नियुक्त आधे से अधिक लोग डॉ. अग्रवाल के कुलपति बनने से पूर्व सम्पर्क में थे. दरअसल वे सभी मेधावी मान लिए गए, जो कुलपति के नजदीकी थे और यस बॉस की नीति पर चलते थे. डॉ. दिनेश हुड्डा सहित कई लोग तो कुलपति के योगदान के समय भी शास्त्री भवन में मौजूद थे.

सबसे अहम और जांच का विषय यह है कि वीसी सर्च पैनल के दो सदस्यों के पुत्रों को भी विवि में शिक्षक नियुक्त किया गया है. बताते हैं कि साउथ बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हरिश्चन्द्र सिंह राठौर और हिमाचल प्रदेश केविवि के कुलपति कुलदीप अग्निहोत्री वीसी सर्च पैनल के सदस्य थे. दोनों ने ही डॉ. अग्रवाल के चयन पर सहमति जताई और इसके एवज में उनके पुत्रों को नियुक्त किया गया.

कई जांच के घेरे में

डॉ. अग्रवाल के निकटस्थ सहयोगी डॉ. आशुतोष प्रधान की डॉक्टरेट डिग्री की भी जांच चल रही है. उन्होंने लाडनू राजस्थान के निजी संस्थान जैन विश्वभारती संस्थान से पढ़ाने के दौरान पीएचडी की डिग्री हासिल की. यूजीसी के नियमों के विरुद्ध गलत तरीके से डिग्री प्राप्त करने के आरोप हैं. डॉ. प्रधान के सुपरवाइजर प्रो. संजय भट्ट उनके मित्र हैं. उस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग में कार्यरत थे और आज भी कार्यरत हैं. यूजीसी के नियमों की अनदेखी करते हुए निजी संस्थान द्वारा पीएचडी की डिग्री दी गई, क्योंकि नियमानुसार सुपरवाइजर संस्थान के स्थायी शिक्षक ही बनाए जा सकते हैं और डॉ. भट्ट उस संस्था में नहीं थे. डॉ. प्रधान के प्रभाव का आकलन इससे भी किया जा सकता है कि वे विश्वभारती संस्थान के सर्वोच्च बॉडी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य भी हैं. स्नातक में मात्र 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले डॉ. प्रधान ने डॉ. बछराज दुगर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था. उसी संस्थान में डॉ. प्रधान की पत्नी रश्मिता रे को उसी शीर्षक पर दूसरे विभाग अहिंसा एवं शांति विभाग से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई. इतना ही नहीं, कुलपति डॉ. अग्रवाल की कृपा पर ही डॉ. प्रधान को हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया था. वहां भी डॉ. अग्रवाल द्वारा उसी प्रकार के प्रोजेक्ट दिलाए गए. उनकी पत्नी रश्मिता रे को शिक्षा विभाग से जोड़कर एक पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप दिलाया गया और आईसीएसएसआर से अवॉर्ड की गई. डॉ. प्रधान महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में डॉ. अरविन्द अग्रवाल की कृपा से आए, जहां उनकी पत्नी को बिना नेट पास किए और दूसरे विषय में पीएचडी की उपाधि होते हुए भी नियमों के विपरीत सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया. वहीं केविवि के ऐकेडमिक काउंसिल के सदस्य और एमएस कॉलिज के प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार मिश्रा की पत्नी सरिता तिवारी की नियुक्ति पर भी प्रश्नचिन्ह उठ रहा है. बताते हैं कि ऐकेडमिक काउंसिल के सदस्य के सम्बंधी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है.

नियुक्ति परीक्षा में हेराफेरी

इस बार भी नियुक्ति में घालमेल का खेल चला. परीक्षा के पूर्व ही सभी को पता था कि कौन-कौन नियुक्त किए जाएंगे. बताते हैं कि परीक्षा पूर्व ही नियुक्त होने वालों के नाम सहित इसकी शिकायत शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री, सीबीआई और विजिलेंस को दी गई थी. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. नियुक्ति परीक्षा में लिखित पत्र और साक्षात्कार में अंकों का फेरबदल कर अपने लोगों को नियुक्त किया गया.

पुस्तक ख़रीद में घोटाला

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए विगत दिनों लगभग दो करोड़ के पुस्तकों की खरीदारी की गई है, जिसमें कमीशन का खेल जमकर चला है. बताते हैं कि कई विभागों के लिए ऐसी पुस्तकों को मंगाया गया है जो अनावश्यक हैं. अधिकतर पुस्तकों का चयन प्राप्त होने वाले कमीशन के आधार पर किया गया.

भयाक्रांत कर छिपा रहे भ्रष्टाचार

'कैंपस में हमेशा दो कौवों को टंगा रहना चाहिए, ताकि अन्य कौवों को सबक मिले' यह डॉ. अग्रवाल और उनके दोनों सहयोगी डॉ. प्रधान और डॉ. हुड्डा का तकियाकलाम है, जो अक्सर बोलते रहते हैं. इसी से उनलोगों की मानसिकता का पता चलता है. प्रबंध विभाग के पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉ. संदीप कुमार के अनुसार छेड़खानी का आरोप लगवाने की धमकी देकर उनका जबरन त्यागपत्र लिया गया और अब दो सहायक प्राध्यापकों को 28 सितम्बर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इसे लेकर दोनों बर्खास्त शिक्षक और छात्र धरने पर बैठ गए, तब मामले को दबाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का इस्तेमाल किया गया. बर्खास्तगी के दूसरे दिन ही सहायक प्राध्यापक डॉ. शशिकान्त रे को शहर छोड़कर भाग जाने अन्यथा भुगतने तक की धमकी कुलपति के दो चहेतों दिनेश व्यास और शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दिया गया, जिसे लेकर डॉ. रे ने नगर थाना में एक आवेदन देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है. सूत्रों की मानें तो विभिन्न हथकंडा अपनाकर आधा दर्जन लोगों से पूर्व में ही अदिनांकित त्यागपत्र लिया जा चुका है.

इधर आन्दोलन कर रहे छात्रों को कुलपति द्वारा बुलाकर धमकाने और विश्वविद्यालय से निकाल देने की बात कहकर भयाक्रान्त किया जा रहा है. कई छात्रों के अभिभावकों से भी सम्पर्क कर अपने बच्चों को आन्दोलन से दूर रखने की सलाह दी जा रही है. सूत्रों की मानें तो आन्दोलन से झल्लाए कुलपति डॉ. अग्रवाल ने कार्यरत शिक्षकों को भी अल्टीमेटम दिया है कि जो भी निष्कासित शिक्षकों के साथ दिखेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं होगा. इसके बावजूद आन्दोलन रुकने की बजाय तेज होता जा रहा है. विजयदशमी के दिन छात्र संगठनों ने कुलपति के पुतला का भी दहन किया. वहीं गांधी जयन्ती के दिन छात्र राजद के सदस्यों ने मीनाबाजार चौक स्थित गांधी टावर के समक्ष भूख हड़ताल किया. शाम में राजद विधायक राजेन्द्र कुमार ने आन्दोलनकारी छात्रों का अनशन तुड़वाया. छात्रों की मांग है कि कुलपति डॉ. अग्रवाल को अविलम्ब हटाया जाए, ताकि कैम्पस में शैक्षणिक माहौल बन सके.

विदेशों तक पहुंची विरोध की आवाज़

केविवि के कुलपति के खिलाफ दिन-ब-दिन आन्दोलन तेज होता जा रहा है. बर्खास्त दोनों शिक्षकों के पक्ष में छात्र संगठनों के साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य कार्यरत शिक्षक भी आ गये हैं. 3 अक्टूबर को दर्जनों शिक्षक धरने पर बैठ गए. विश्वविद्यालय के 72 शिक्षकों में से 37 शिक्षक खुल कर विरोध में सामने आ गये हैं, जिसमें अतुल त्रिपाठी, ओम प्रकाश गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, संजय कुमार, श्रीधर सत्यपाल, विद्याभूषण मिश्रा, प्रतिभा सिंह, स्वाति मनोहर, बबिता मिश्रा, अभिजीत कुमार, श्यामनन्दन सिंह, विपिन कुमार, आलोक श्रीवास्तव, अनिल कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हैं. धरने पर बैठे शिक्षकों के अनुसार कुलपति के कुछ चहेतों को छोड़कर सभी कुलपति के नादिरशाही रवैये के विरोध में हैं. शिक्षकों का कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय में भय का माहौल है. रोज बाहर निकाल देने की धमकी दी जाती है. तरह-तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है. हम सभी योग्यता के बल पर यहां पहुंचे हैं और पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवि का माहौल कुलपति और उनके कुछ चाटुकारों ने बिगाड़ रखा है. अगर कुलपति अपना गलत फरमान वापस नहीं लेते, तो हम सभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इधर विवि के छात्रों का आन्दोलन भी जारी है. कुलपति को हटाने और तीनों शिक्षकों को पुन: वापस बुलाने की मांग को लेकर अभाविप के सैकड़ों कार्यकर्ता विवि के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार विवि के सीनेट मेम्बर और अभाविप के नेता नीरज कुमार ने बताया कि कुलपति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और अपने घोटालों को छिपाने के लिये भय का माहौल बना रहे हैं और इसके लिए तरह-तरह के हथकण्डे अपना रहे हैं. जबतक ऐसे भ्रष्ट कुलपति को हटाया नहीं जाता है, हमारा आन्दोलन जारी रहेगा. इधर प्रशासन भी आन्दोलन को शांत करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन आन्दोलन उग्र होता जा रहा है. ज्ञात हो कि केविवि की स्थापना को लेकर जिलेवासियों ने वर्षों संघर्ष किया था. केविवि की अराजक स्थिति और कुलपति के भ्रष्टाचार को देख जिले की आम जनता और विभिन्न संगठनों ने भी आन्दोलन का रुख अख्तियार किया है. चम्पारण विकास मोर्चा के संयोजक राय सुन्दरदेव शर्मा ने भी चरणबद्ध आन्दोलन का ऐलान किया है, जिसे अभिभावकों का भी समर्थन प्राप्त है.

केविवि के भ्रष्टाचार की चर्चा अब विदेशों तक पहुंच गई है. बोस्टन के हॉर्वर्ड विवि के हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया है. हॉर्वर्ड के वैज्ञानिक डॉ. अमरेन्द्र कुमार अजय, डॉ. अभिज्ञान सत्यम, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. मनोज गुप्ता, डॉ. प्रेमस्वरूप यादव और डॉ. परमीत तेरेसा ने तख्ती लगाकर विरोध-प्रदर्शन किया. वहीं देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं. इधर कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी केविवि के भ्रष्टाचार से मानव संसाधन विभाग और प्रधानमंत्री को अवगत कराया है और कार्रवाई की मांग की है. पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी चिन्ता जताते हुए कुलपति पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक विस्तृत पत्र प्रधान मंत्री को भेज रहा हूं, ताकि केविवि की गरिमा को बचाया जा सके.■

feedback@chauthiduniya.com

गुजरात विधानसभा चुनाव

पटेलों को पटाने में जुटी पार्टियां

सुरेश त्रिवेदी

गुजरात में रणभेरी बज चुकी है. पक्ष और विपक्ष की सेनाएं आमने-सामने हैं. सत्ता के लिए शुरू हुए इस महासमर में किसकी जय या किसकी पराजय होगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि गुजरात विधानसभा का होने वाला चुनाव कई राजनैतिक दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है. इस चुनाव में भाजपा की हार जहां सीधे मोदी की मात मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस की फतह को राहुल गांधी के पुनर्जागरण के रूप में देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा बन सकता है, तो पाटीदारों के युवा नेता हार्दिक पटेल की सिमटती साख के लिए यह चुनाव संजीवनी बन सकती है. इसीलिए तकरीबन सभी दल पिछले दो सालों से नई राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे पाटीदारों को पटाने में जुट गए हैं.

दरअसल, गुजरात के तकरीबन डेढ़ करोड़ पाटीदार मतदाता वहां किसी भी दल की राजनीतिक बाजी पलटने में सक्षम माने जाते हैं. पिछले लगभग डेढ़ दशक से गुजरात में भाजपा की जीत की रीढ़ समझे जाने वाले ये पाटीदार फिलहाल उससे बुरी तरह नाराज़ हैं. उनकी नाराज़गी की दो वजहें हैं. पाटीदार नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अपने लिए दस फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं. पटेलों में असंतोष की कुलबुलाहट इससे भी है कि पाटीदार यह महसूस कर रहे हैं कि अब वे भाजपा में धीरे-धीरे हाशिए पर धकेले जा रहे हैं. आनंदीबेन पटेल को हटाए जाने के बाद नितिन पटेल को मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे के खेल को भी वे सोची-समझी राजनीतिक साज़िश मानते हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लगातार गुजरात दौरों और पाटीदारों को मनाने की हर चंद कोशिशों के बावजूद उनके तेवर अभी नरम नहीं हुए हैं.

गुजरात में पाटीदारों की नाराज़गी की आग भाजपा की पूंछ में लग गई है. इससे भाजपा के क्षत्रपों की बेचैनी बढ़ गई है. इसीलिए पाटीदारों के आंदोलन की धार कुंद करने के इरादे से विजय रुपाणी की सरकार ने हाल में एक नया पासा फेंका है. मुख्यमंत्री ने आन्दोलनकारी पाटीदारों से बातचीत के लिए तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया. समिति में उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल के अलावा काबीना मंत्री चिमन सपारिया और राज्यमंत्री नानूभाई बनानी शामिल थे. इस समिति ने पाटीदार अमानत आंदोलन तथा दूसरे ताकतवर संगठन 'सरदार पटेल ग्रुप' समेत 6 संगठनों के प्रतिनिधियों से 26 सितम्बर को लम्बी बातचीत की. बातचीत में हार्दिक पटेल और एसपीजी के कद्दावर नेता लालजी भाई पटेल भी शामिल हुए, पर नतीज़ा ठन-ठन गोपाल ही रहा. पाटीदारों के युवा नेता हार्दिक पटेल ने बैठक के बाद साफ़ कहा कि सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही. लेकिन इस मुद्दे पर पहली बार बैकफुट पर आई गुजरात सरकार ने आनन-फानन में तीन फैसलों का ऐलान कर दिया. रूपाणी सरकार ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2015 को जीएनडीसी मैदान पर हुई पाटीदारों की ऐतिहासिक रैली के दौरान पाटीदारों के खिलाफ दर्ज़ हुए सभी मुकदमे सरकार वापस ले लेगी. साथ ही सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी तथा वित्तीय सहायता भी मुहैया कराएगी. मालूम हो कि पाटीदार-आंदोलन के दौरान 13 लोगों की जान गई थी. गुजरात सरकार ने दो आयोगों के गठन को भी मंज़ूरी दे दी है. इनमें एक आयोग आरक्षण के दायरे में न आने वाले सभी वर्गों के कल्याण के लिए ज़रूरी उपायों पर अपने सुझाव देगा. यह 'गैर आरक्षित जाति आयोग' उन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा, जो फिलहाल कृषि, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं.

दूसरा आयोग दो वर्ष पूर्व पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई पुलिस ज़्यादतियों की जांच करेगा. इस आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे. इन फैसलों से साफ़ है कि सरकार जैसे-तैसे गुजरात में पाटीदारों के गुस्से की आंच को जल्दी से जल्दी ठंडा करना चाहती है.

दरअसल पाटीदारों के भाजपा विरोधी तेवरों को भांपकर कांग्रेस ने भी पटेलों को रिझाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं. शायद इसी मंशा से राहुल ने अपने तीन दिनी गुजरात दौरे की शुरुआत तो द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा-अर्चना से की, लेकिन उनकी नज़रें पूरी यात्रा के दौरान पाटीदार समुदाय की हलचलों पर टिकी रही. इसीलिए उन्होंने जहां राजकोट के प्रसिद्ध खोडलधाम मंदिर में माथा टेका, वहीं ऊंझा के उमिया माता मंदिर में आरती की यही नहीं वे चोटिला में चामुंडा माता के दर्शन करने भी गए. ये तीनों मंदिर गुजरात में पाटीदारों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं. उमिया माता कडवा पटेलों की आराध्य देवी हैं. हार्दिक पटेल इसी कडवा पटेल समुदाय से आते हैं. इसी तरह खोडियार माता पाटीदारों के दूसरे बड़े धड़े लेउवा पटेलों की इष्ट देवी हैं. पूरे सौराष्ट्र में लेउवा पटेलों का ही बोलबाला है, जबकि कडवा पटेल प्रमुख रूप से उत्तर गुजरात में बहुतायत में हैं. राहुल ने पूरे गुजरात दौरे में जहां मोदी पर जमकर हमला बोला, वहीं पाटीदारों को खुश करने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी. गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हेमांग वासवदा ने स्वीकार किया कि हमने राहुल गांधी से खोडियार माता के दर्शन कर चुनावी अभियान शुरू करने का आग्रह किया था.

एक हकीकत यह भी है कि बीते कुछ सालों में कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख पाटीदार नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं. पार्टी से तौबा करने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री विट्ठल रदाड़िया नरहरि अमीन आदि शामिल हैं. वे बताते हैं कि कांग्रेस में पाटीदारों की उपेक्षा माधव सिंह सोलंकी के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू हुई थी. तब कांग्रेस ने KHAM यानि क्षत्रिय हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम समीकरण बनाया था. उस दौर में हुई उपेक्षा से आहत पाटीदार धीरे-धीरे भाजपा में शामिल होते गए. पिछले तीन चुनावों में पाटीदार पूरी मजबूती और दमखम से भाजपा के साथ खड़े रहे तब भी वे भाजपा और मोदी के पाले में डटे रहे, जब पाटीदारों के बुजुर्ग नेता केशुभाई पटेल ने भाजपा के खिलाफ शंखनाद कर दिया और इसे अपने अपमान और अस्मिता से जोड़ा. लेकिन इस बार हालात किसी के लिए भी इतने आसान नहीं हैं. पाटीदार भाजपा से बिफरे जरूर हैं, पर वे इस बार अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं. इसीलिए राहुल गांधी के गुजरात दौरे का हार्दिक पटेल ने अपने बयान में स्वागत तो किया किन्तु कांग्रेस नेताओं की मान-मनुहार के बाद भी वह उनकी आगवानी के लिए नहीं गए.

यूं तो गुजरात चुनावों की तासीर को महसूस करने के लिए वहां के सामाजिक ताने-बाने को भी समझना ज़रूरी है. प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों में से 70 पर पाटीदारों का जबरदस्त प्रभाव है. इनमें से ज़्यादातर सीटें सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में हैं. लेउवा और कडवा पटेलों के अलावा पाटीदारों का एक धड़ा गुज्जर पटेलों का भी है. सरदार पटेल इसी गुज्जर पटेल समुदाय से थे. चूंकि लेउवा और कडवा पटेलों का एक बड़ा वर्ग भाजपा से साफ़ दूरी बना चुका है, शायद इसीलिए भाजपा अब सरदार पटेल और गुज्जर पटेलों के सहारे पाटीदारों के बीच नए सिरे से अपनी पैठ बनाने की पहल कर रही है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद से अपनी 'गुजरात गौरव-यात्रा' शुरू करना पार्टी की इसी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है.

गुजरात की लड़ाई राजनैतिक से ज़्यादा सामाजिक होती जा रही है. वहां का पूरा समाज 'द्विज और अद्विज' जातियों के दो खेमों में बट गया है. द्विज जातियों में ब्राह्मण, ठाकुर बनिया जहां भाजपा के पक्ष में हैं, वहीं अद्विज - जाट, मराठा, पाटीदार और दलित वर्गों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसीलिए गुजरात में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा नेता वहां भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं. अल्पेश ठाकुर पिछड़ी जातियों के तथा जिग्नेश दलितों के युवा नेतृत्व के रूप में उभरे हैं. गुजरात में पिछड़ों की हिस्सेदारी कुल आबादी की 60% है जबकि दलित केवल 7% हैं. राज्य की 66 सीटों पर पिछड़ी जातियों के मतदाताओं का अच्छा खासा असर है. भाजपा इस सामाजिक विज्ञान को बखूबी समझ रही है इसीलिए चौथी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद में भाजपा वहां पाटीदारों की नाराज़गी के चलते पिछड़ा कार्ड चलाने का भी दांव खेल सकती है.

इस सबके बीच आप आदमी पार्टी भी गुजरात में पाटीदारों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है. पिछले दिनों केजरीवाल और हार्दिक पटेल के बीच हुई मुलाक़ात के बाद इसे इरादतन राजनीतिक हवा दी गई. हालांकि जल्द ही यह तस्वीर साफ़ हो गई कि आप वहां 'एकला चलो' का राग ही अलापेगी. दूसरी ओर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि पाटीदारों के बीच स्टार बन चुके हार्दिक पटेल से उनकी बातचीत अंतिम मुकाम पर है. सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ पेंच फंसा है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. भाजपा का सिरदर्द यह भी है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के ताबड़तोड़ गुजरात दौरों के बावजूद वहां पाटीदारों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल नहीं रही है. इस बीच प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन, सरदार सरोवर बांध से लेकर आईआईटी कैंपस के लोकार्पण तक का पासा वहां फेंक दिया है. इसके बाद भी अमित शाह के दौरे के दरम्यान पाटीदारों का उनके खिलाफ नारेबाजी- विरोध प्रदर्शन करना कम से कम भाजपा की नींद हराम किये हुए ही है. पाटीदार खुद को भगवान् राम का वंशज मानते हैं. इनमें लेउवा पटेल अपने को 'लव' का तो कडवा पटेल 'कुश' का उत्तराधिकारी बताते हैं. ज़ाहिर है इस बार गुजरात में राम नाम के सहारे सत्ता में आई भाजपा का राम के वंशधरों से ही दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है.■

feedback@chauthiduniya.com

स्वायत्तता कश्मीरियों के लिए भावनात्मक मुद्दा है

हारून रेशी

देश में इस वक्त कश्मीर के हालात पर दो तरह के नजरिए पाए जाते हैं. पहला नजरिया कश्मीर समस्या के समाधान में सख्ती बरतने की बात करता है और दूसरा नरमी अख्तियार करने की. आरएसएस के 92वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये मांग रखी कि कश्मीर को भारत में पूरी तरह शामिल करने के लिए संविधान में संशोधित किया जाए. मोहन भागवत के बयान के दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर में भाजपा के सीनियर लीडर एवं मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि भाजपा धारा 370 को समाप्त करने का पक्का इरादा रखती है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम होती तो आज जम्मू-कश्मीर का नक्शा कुछ और होता. जाहिर है इस नजरिए से कश्मीर में और अधिक बेचैनी बढ़ेगी.

कश्मीर के बारे में दूसरा नजरिया उन लोगों का है, जो चाहते हैं कि राज्य को दिए हुए विशेष अधिकार पूरी तरह से बहाल किए जाएं. उनका ये भी कहना है कि समस्या का समाधान राजनैतिक तौर पर करने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए. इस नजरिये के हामियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं. वे पिछले एक वर्ष में कई बार कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. उन्होंने यहां न सिर्फ सियासी और मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की, बल्कि आम लोगों से भी मिलकर उनके विचार जानने की कोशिश की. यशवंत सिन्हा ने अपने हाल के इंटरव्यू में कहा कि भारत ने भावनात्मक तौर पर कश्मीर को खो दिया है. उनका कहना है कि वादी में मायूसी बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि भारत को फौजी ताकत पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए. भाजपा-पीडीपी के बीच हुए एजेंडा ऑफ एलाइंस का हवाला देते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार बनाते समय दोनों पार्टियों में हुर्रियत से बातचीत करने पर सहमति बनी थी.

बहरहाल, फिलहाल सत्ता पक्ष यशवंत सिन्हा की बात सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आता. मोदी सरकार कश्मीर पर नरमी बरतने का केवल दिखावा करती है. 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान कश्मीरियों को गले लगाने से होगा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कश्मीर में कोई ऐसा सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह हाल में कश्मीर दौरे पर थे. धारा 35 ए को समाप्त किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यकीन दिलाया था कि कश्मीरियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा.

उनकी बात से ये मतलब निकाला जा सकता है कि कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाली धाराओं को संविधान से नहीं हटाया जाएगा. गौरतलब है कि इस धारा को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है. गृह मंत्री के बयान के बाद कश्मीर में ये उम्मीद बनी थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि वो धारा 35 ए को समाप्त नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. कश्मीरियों को डर है कि संविधान के इस प्रावधान को किसी भी वक्त खत्म करके राज्य की रही सही स्वायत्तता भी छीन ली जाएगी.

कश्मीर के प्रति मोदी सरकार की दोहरी नीति की वजह से दिल्ली और कश्मीर के दरमियान खाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. शायद इसी वजह से यशवंत सिन्हा ने कहा है कि भारत ने भावनात्मक तौर पर कश्मीर को खो दिया है. संवैधानिक स्वायत्तता पर कश्मीरी जनता की संवेदनशीलता का अंदाजा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयानों से भी लगाया जा सकता है. 35 ए पर राजनाथ सिंह के आश्वासन के फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुला ने ये मांग रख दी कि अगर राजनाथ सिंह सच कह रहे हैं तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये राय रखनी चाहिए. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि अगर 35 ए को खत्म किया गया तो कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा. इन दो नेताओं के बयानों से ये जाहिर हो जाता है कि कश्मीरी आवाम स्वायत्तता को लेकर कितनी संवेदनशील है.

13 अक्टूबर को श्रीनगर में बीएसएफ कैंप पर आत्मघाती हमला और एलओसी पर लगातार गोलाबारी इस बात के सबूत हैं कि तीन दशक बीत जाने के बाद भी नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही है. अगर मिलिटेंसी की शुरुआत के 27 साल गुजरने के बाद भी श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित सुरक्षा बलों के कैंप पर आत्मघाती हमला हो सकता है तो इसका साफ मतलब है कि लाखों की तादाद में सैनिक और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी राज्य में मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकती है. कश्मीर मसले के हल के लिए नई दिल्ली को बातचीत के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

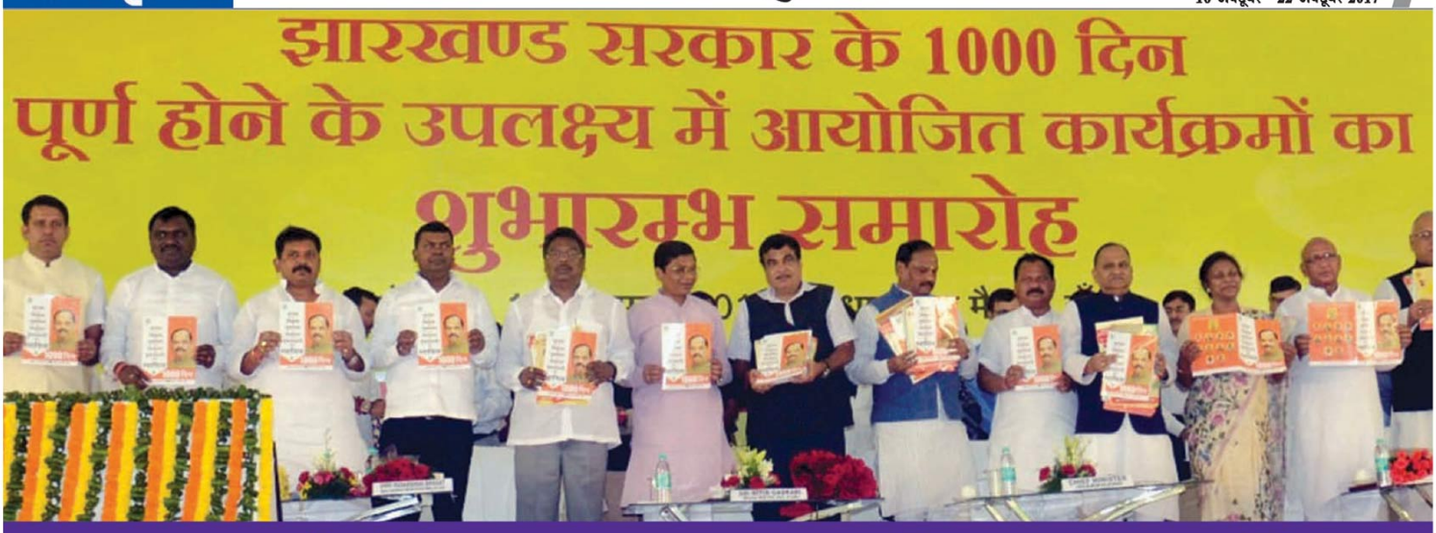

मुख्यमंत्री रघुवर दास के हज़ार दिन उपलब्धियों या घोषणाओं के

प्रशान्त शरण

झारखंड गठन के बाद रघुवर दास ऐसे पहले मुख्यमंत्री है, जिन्होंने एक हजार दिन पूरा किया. वैसे यह रघुवर दास की कोई उपलब्धि नहीं मानी जाएगी. राज्य गठन के बाद पहली बार भाजपा बहुमत में आई और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने. इस पद पर अपने को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों को तोड़ कर भाजपा में मिला लिया. एक हजार दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से पांच वर्षों तक शासन करने का आशीर्वाद भी ले लिया. एक हजार दिन की अपनी उपलब्धियां बताते हुए रघुवर दास ने कहा कि जब उन्होंने संभाली, उस समय राज्य आर्थिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था. हमने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है. उनका ये भी कहना था कि मैं मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं. जनता ने राज नहीं काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है. उन्होंने कहा कि 2020 तक हम ऐसा झारखंड बनाएंगे, जिसे देखकर दुनिया सराहेगी. हमारा राज्य विकास के मामले में तो शीर्ष पर होगा ही, डर, भय, भुख नाम की भी कोई चीज यहां नहीं होगी.

दावों से दूर है वास्तविकता

ऐसा लगता है कि अपने एक हजार दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री पूरी तरह से जमीनी हकीकत से बेखबर हैं. प्रदेश में 67 प्रतिशत लड़कियां एवं महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, पर स्वस्थ झारखंड का दावा किया जा रहा है. एक माह में लगभग तीन सौ बच्चों की मौत कुपोषण से हो गई. अभी भी राज्य में निरक्षरों की संख्या लगभग चालीस प्रतिशत है. आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है, लेकिन पूरे राज्य से गरीबी दूर करने की बात की जा रही है. बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. लोग पेयजल, बिजली, मकान, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें विकसित झारखंड का हसीन सपना दिखाया जा रहा है. 3 लाख 10 हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन एक भी बड़ा उद्योग झारखंड में अभी तक स्थापित नहीं हो सका. सरकार ने केवल छोटे-छोटे उद्यमियों से निवेश कराकर वाहवाही लूटने का काम किया है. मुख्यमंत्री ने लाखों लोगों को नौकरी देने की बात कही, लेकिन किसे कहां नियुक्त किया गया, किसी को पता नहीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य के किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन एक माह के अंदर कर्ज में फंसे आधा दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली. किसानों के कल्याण के लिए दर्जनों योजना शुरू की गई, लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं. उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी राज्य की एक प्रमुख सड़क रांची-टाटा हाइवे का काम पूरा नहीं हो सका है. वहीं राज्य की लगभग एक सौ से भी ज्यादा स्वीकृत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य अधर में है. हाल के बरसात में प्रदेश के 100 से ज्यादा पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि इनका निर्माण दो-तीन वर्ष पूर्व ही हुआ था. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 2018 तक अगर सभी गांवों में बिजली नहीं दे सका, तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा, साथ ही उन्होंने जीरो पावर कट की भी बात कही थी. लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी में ही घंटो तक पावर कट होता रहता है, गांवों की बात तो दूर है. ग्रामीण इलाकों में तो बिजली अभी भी एक सपना ही है. मुख्यमंत्री का ये दावा भी हकीकत से दूर है कि सभी पंचायतों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है. एक बड़ी आबादी अब भी मीलों दूर से पानी का पानी ढो कर लाती है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा तो हकीकत से पूर्णत: विपरीत है. अव्वल तो ज्यादातर शौचालयों का निर्माण कागजों में ही हुआ, लेकिन जो बने वे भी निर्माण के कुछ देर समय बाद ही टूट गए. एक तरह से कहा जा सकता है कि सारी उपलब्धियां कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास भ्रष्टाचार के मामले में जीरों टालरेंस की बात करते हैं, लेकिन यहां भ्रष्टाचार चरम पर है. विकास के नाम पर धड़ल्ले से लूट-खसोट और पैसों का बंदरबांट जारी है.

काम से ज्यादा उपलब्धियां गिनाने पर जोर

झारखंड में जब जमीनी स्तर पर जनता को विकास नहीं दिखा, तब मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपनी उपलब्धियां गिनाने का निर्देश दिया. विभागीय मंत्रियों ने प्रेस के माध्यम से जमकर उपलब्धियां गिनाई. समाचार पत्रों एवं चैनलों में बड़े-बड़े विज्ञापन आए, लेकिन जब जनता उससे संतुष्ट नहीं हुई, तो विभागीय सचिवों को भी विभाग से सम्बन्धित उपलब्धि बताने का फरमान सुनाया गया. लेकिन उपलब्धियां गढ़ी तो नहीं जा सकतीं, जब जमीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं दिख रहा, तो मंत्री या सचिव जनता को क्या बताएंगे. इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास यह दावा कर रहे हैं कि एक हजार दिनों में 16 लाख लोगों को रोजगार मिला, लेकिन किसे मिला ये पता नहीं. उन्होंने कहा कि आदिम जनजातीय की स्थिति में सुधार हो रहा है और उन लोगों के घर पीजीटी डाकिया योजना के तहत राशना पहुंचाया जा रहा है. दरअसल, मुख्यमंत्री घोषणाओं को भी उपलब्धियां बताने लगे. जैसे, 289 सेवाओं को राईट टू सर्विस में शामिल करना, मोमेंटम झारखंड में 3.10 लाख करोड़ का निवेश, 2022 तक सभी को आवास, सभी को शुद्ध पेयजल और शौचालय आदि सरकार की घोषणाएं हैं, जिसे कई बार दोहराया जा चुका है.

हालांकि सरकार ने जहां काम करने की कोशिश की, वहां भी वांछित सफलता नहीं दिख रही है. बेघरों को घर देने का काम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी काम देखने वाली हजारों सहिया की नियुक्ति, छोटे-मोटे उद्योगों की स्थापना और वर्षों से लटकी हुई स्थानीय नीति को लागू करने जैसे काम किए गए, लेकिन इनका परिणाम वैसा नहीं निकला, जो होना चाहिए था. बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से लाखों स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल सकी. कई नीतियां को लागू करने को लेकर भी मुख्यमंत्री की काफी किरकिरी हुई, जैसे सीएनटी-एसपीटी संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा. विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सता पक्ष के लोगों ने भी उसका पुरजोर विरोध किया. अंतत: मुख्यमंत्री को इस संशोधन विधेयक को वापस लेना पड़ा. इधर तीन नए मेडिकल कॉलेज सहित देवघर में एम्स खोलने की सराहनीय पहल मुख्यमंत्री ने की है. अगर यह काम पूरा होता है, तो इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सकेगी.

औद्योगिक विकास, और इज आर्फ डूइंग बिजनेस के मामले में गुजरात के बाद झारखंड दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहां न तो औद्योगिक विकास दिखता है और न न ही उद्योग-धंधों के लिए माकूल माहौल. झारखंड में निवेश के लिए 3 लाख 10 हजार करोड़ के 290 एमओयू हुए, पर कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो सका. नक्सल समस्या भी सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है. झारखंड के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हैं. सरकार के लाख दावों के बाद भी नक्सली घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का काम कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. राजधानी से सटे खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा जिले के कई गांवों में तो ये हाल है कि वहां पुलिए भी जाने से बचती है. अन्य कई जिलों में भी नक्सलियों ने लेवी के नाम पर विकास के पहिए को लगभग रोक दिया है. जाहिर है, ये जिले न सिर्फ पिछड़े हैं, बल्कि वहां अशिक्षा, बेरोजगारी और अपराध चरम पर है. नक्सलियों की शह पर वहां व्यापक स्तर पर नशीले पौधों की खेती भी धड़ल्ले से हो रही है. इसके साथ-साथ इन इलाकों में मानव तस्करी भी जोरो पर है. इस सभी से निजात पाना और इन इलाकों को भी विकास से जोड़ना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है.

सरकार के जश्न पर विपक्ष का सवाल

एक तरफ सरकार एक हजार दिनों के जश्न में डूबी है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं झाविमों सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़ा कर दिया. उनका कहना है कि सरकार ये बताए कि उन्होंने कौन सा विकास का काम किया है. इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि ये सरकार जमीनी स्तर पर कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं कर सकी है. केवल मीडिया के विज्ञापनों के जरिए विकास का ढिढ़ोरा पीटा जा रहा है. वे दावे किए जा रहे हैं, जिनका कोई जमीनी वास्ता ही नहीं है. सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार की इस प्रचार नीति पर सवाल उठाने लगे हैं. रघुवर मंत्रिमंडल के ही एक वरिष्ठ मंत्री सरयू राय का कहना है कि सरकार ने जब काम किया है, तो जनता उसे देखेगी ही, उपलब्धियों गिनाने की जरूरत क्या है. गौर करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों से इतर, सरयू राय ने विभागीय उपलब्धियां बताने के लिए प्रेस कांफ्रेंस नहीं किया. इन्होने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण सरकार एवं पार्टी को नुकसान ही हुआ है. सरयू राय का ये भी मानना है कि सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या से बयान पैदा होता है बयान से कोई समस्या नहीं है

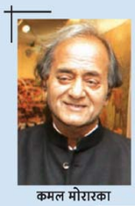

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

वरिष्ठ नेता और अटल जी के कैबिनेट में मंत्री रह चुके अरुण शौरी ने प्रहार कर दिया कि ये सरकार जिस ढंग से चल रही है, वो तरीका ही सही नहीं है. निर्णय लेने के जो तरीके होते हैं, सामूहिक तौर पर और एक्सपर्ट से सलाह लेना, इस पूरे तरीके को ये सरकार बाईपास कर रही है. उन्होंने एक शब्द यूज किया कि ये इल्हाम की सरकार है. इन्हें ऊपर से इल्हाम हो जाता है. इस सरकार को ऊपर से भगवान ने ये सुझा दिया कि ये करना चाहिए और अगले दिन ये वही काम कर देते हैं, बिना किसी आंकड़ों के, तकनीक के. गंभीर आरोप है ये. दिन के बारह बजे हैं. इस पर हम बहस कर सकते हैं कि 12 बजे चाय का समय है या नाश्ते का या खाने का, लेकिन इस पर तो बहस नहीं हो सकती कि दिन के 12 बजे हैं. ग्रोथ रेट जो है, वो है. आरबीआई कहता है कि डिमोनेटाइजेशन का 99 प्रतिशत पैसा गया और हमने चेंज भी कर लिया. ये तथ्य तो साबित बात है न. इसमें किसी राय का सवाल नहीं है.

देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है. इसके दो-तीन मूल कारण हैं. एक तो अब ये सर्वविदित हो गया है कि लोगों को नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि लगी हुई नौकरियां छूट रही हैं. बड़ी-बड़ी बैंक जैसे यस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने हजारों की तादाद में लोगों को हटा दिया. शहरी क्षेत्रों में घबराहट का एक वातावरण पैदा हो गया है. गांव की बात तो अलग है. अगर देश में ये हालत हो जाए कि लगी-लगाई नौकरियां लोगों की छूटती हैं, जिसे डिसएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो ये चिंता का विषय है. पिछले दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक दैनिक अखबार में लेख लिखा. उसमें उन्होंने चिंता जताई कि जीडीपी छह तिमाहियों से लगातार गिर रही है और आर्थिक स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि अर्थव्यवस्था ठप होने का खतरा है. उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, दोनों की बुद्धिमत्ता और लागू करने के तरीकों पर सवाल उठाया. वरिष्ठ नेता और अटल जी के कैबिनेट में मंत्री रह चुके अरुण शौरी ने प्रहार कर दिया कि ये सरकार जिस ढंग से चल रही है, वो तरीका ही सही नहीं है. निर्णय लेने के जो तरीके होते हैं, सामूहिक तौर पर और एक्सपर्ट से सलाह लेना, इस पूरे तरीके को ये सरकार बाईपास कर रही है. उन्होंने एक शब्द यूज किया कि ये इल्हाम की सरकार है. इन्हें ऊपर से इल्हाम हो जाता है. इस सरकार को ऊपर से भगवान ने ये सुझा दिया कि ये करना चाहिए और अगले दिन ये वही काम कर देते हैं, बिना किसी आंकड़ों के, तकनीक के. गंभीर आरोप है ये. दिन के बारह बजे हैं. इस पर हम बहस कर सकते हैं कि 12 बजे चाय का समय है या नाश्ते का या खाने का, लेकिन इस पर तो बहस नहीं हो सकती कि दिन के 12 बजे हैं. ग्रोथ रेट जो है, वो है. आरबीआई कहता है कि डिमोनेटाइजेशन का 99 प्रतिशत पैसा गया और हमने चेंज भी कर लिया. ये तथ्य तो साबित बात है न. इसमें किसी राय का सवाल नहीं है.

ऐसे ही जीडीपी का फिगर है. अभी प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के बीच बहुत सारे जवाब दिए. क्या जवाब दिया? पहली बात, मैं जो समझता हूं वो ये कि प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है, उसको वापस पटरी पर लाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराशा का माहौल पैदा कर रहे हैं और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आएगी. ये तो ठीक है. ये तो राजनीतिक जुमला है. यह प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता. उनका प्रहार यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी पर था, लेकिन उन्होंने दो बातें कहीं. एक ये कि उन्होंने स्वीकार किया कि जीडीपी गिरी है, लेकिन पहली बार नहीं गिरी है, पिछली सरकार में भी तीन तिमाहियों में गिरी थी. मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कांग्रेस अब हमलोगों का मापदंड हो गई है? कांग्रेस में गिरी, तो हमारी में भी गिरनी चाहिए. हम तो ये सोचते हैं कि आप ये बोल कर पावर में आए हैं कि कांग्रेस ने दस साल कुशासन किया, हम सुशासन करेंगे. अब आप इसी बात पर संतोष कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय तीन बार गिरी तो हमारे समय में छह बार गिरी है. ये कोई जवाब नहीं है. प्रधानमंत्री शायद समझे नहीं कि उलझ गई बात. दूसरा, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जीएसटी में जो छोटे व्यापारी को दिक्कत हो रही है, उसे हम देखने को तैयार हैं. पहली बार उन्होंने स्वीकार किया है जो मुझे बहुत संतोष पहुंचाता है. उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं कहते कि सब ज्ञान हमारे ही पास है. सब स्टेट की अलग-अलग सरकारें हैं, अलग-अलग पार्टियां हैं, मिल कर बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे. यह लोकतंत्र का दस्तूर है.

लोकतंत्र में चुनाव होता है. 272 चाहिए था, भाजपा को 282 सीट मिल गई. भाजपा को ये संतोष हुआ कि कांग्रेस कमजोर हो गई, लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने से आप ताकतवर नहीं हो गए. और ताकतें आ गई हैं. ये देश के लिए अच्छा नहीं है कि छोटी-छोटी पार्टी ताकतवर हो जाए. इससे सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती. लेकिन, इनका मानना यही है. नरेन्द्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा. खुद का रिकॉर्ड भी देखिए. 2014 का जो चुनाव

मैं समझता हूं कि जीएसटी का थ्रेसहोल्ड, 20 लाख से बढ़ा कर 2 करोड़ रुपए कर देना चाहिए. 2 करोड़ से कम वालों को इसके दायरे से बाहर निकालिए. उसको पुराने सिस्टम से चलने दीजिए. ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दो खतरे हैं. एक बिजनेस गिरेगा, दूसरा कैश ट्रांजेक्शन में बिजनेस शुरू होने लगेगा. छोटा आदमी क्या करेगा? भूखा तो नहीं मरेगा. अर्थशास्त्र बहुत जटिल चीज है, राजनीति आसान है. जुमलेबाजी आसान है. हमलोग राजनीति करते आए हैं. कोई कुछ बोलेगा, जवाब दे देंगे. जवाब देने से कुछ नहीं होगा. एक किलो गेहूं है तो मेरे भाषण से वो दो किलो नहीं हो जाएगा. वो एक किलो ही रहेगा. भाषण देने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी. कारगर कदम उठाने पड़ेंगे. रोजगार देना पड़ेगा. रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा. एक बहुत पुरानी बात कह रहा हूं. मुंबई में एक बार टेक्सटाइल मिलें बन्द हो गईं तो मुंबई में क्राइम रेट बढ़ गया. क्यों? टेक्सटाइल में हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मिला था. बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे? कितनी पुलिस है आपके पास इसे रोकने के लिए? अराजकता जब फैलती है, तो सरकारें चली जाती हैं. पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती. एक तो समस्या अर्थशास्त्र है.

हुआ, वो फ्री एंड फेयर चुनाव था. वो चुनाव कांग्रेस के राज में हुआ था. भाजपा चुन कर आ गई. उसके बाद क्या हुआ? इनके राज (भाजपा के) में जितने चुनाव हुए हैं, कहीं जीते नहीं हैं ये. महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिला. बिहार में नहीं मिला. हरियाणा में एक एमएलए ज्यादा है. यूपी और उत्तराखंड में सफलता मिली. इस पर लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं. मान लीजिए वो सही हैं. यूपी में जीत गए. उत्तराखंड में क्या किया? कांग्रेस मुक्त भारत की जगह कांग्रेसयुक्त बीजेपी बना दिया. सारे कांग्रेसियों को ले लिया. उनका लेबल चेंज हो गया. वही लोग राज कर रहे हैं. कल तक वे भ्रष्ट थे, विकास के खिलाफ थे, आज वो साधु हो गए. यही अगर बीजेपी का पैटर्न है तो ये संविधान के लिए तो ठीक नहीं है. जब अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा को बहुत झुंझलाहट हुई. इनके नाक के नीचे सिर्फ तीन एमएलए आना, शर्म की बात थी. लेकिन, इन्होंने क्या किया? एक पुलिस कमिश्नर था दिल्ली में. एक छोटा सा अफसर, बस्सी. भाजपा ने बस्सी को चढ़ा दिया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ बात करो. क्या एक पुलिस कमिश्नर एक मुख्यमंत्री से लड़ेगा. अगर कमिश्नर को दिक्कत है तो गृह मंत्रालय से शिकायत करे. वह पब्लिकली प्रेस में कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर से डिबेट करने के लिए तैयार हूं. इसी ग्राउंड पर उस कमिश्नर को बर्खास्त कर देना चाहिए था. अगर पुरानी सरकारें होती, इंदिरा गान्धी की सरकार होती, ये कभी बर्दाश्त नहीं करती. कौम हमारे खिलाफ है, ये हम देखेंगे, लेकिन नौकरशाही का काम है अपना काम करना. तीन साल में संविधान में जो त्रुटियां इस सरकार ने पैदा की हैं, कल मुझे प्रधानमंत्री के बयान को सुन कर आशा हुई है कि वे शायद इन सब को ठीक करेंगे. उन्होंने कहा कि भाई सब ज्ञान हमारे पास नहीं है और कोई हमसे असहमत है तो हमारा दुश्मन नहीं है.

इनका मानना है कि इनके खिलाफ जो बोलता है, वो कांग्रेसी है. राहुल गान्धी का नाम पप्पू रखा हुआ है. मैं बोल रहा हूं. अरे भाई मैं जनता दल का हूं. हम मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, उनकी धरोहर लेकर बैठे हैं. हम कांग्रेस में कभी नहीं थे. तो ये जो है कि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो कांग्रेसी हैं. तो आपने देश को दो हिस्सों में बांट दिया. ये काम पब्लिक को हर्गिज बर्दाश्त नहीं है. खतरा आप समझ नहीं रहे हैं. आपके जाने के बाद भी देश रहेगा, सबका रहेगा. मैं नहीं कहता हूं कि जीएसटी आपने गलत मंशा से किया होगा. लेकिन लोग परेशान हैं. इसे सुधारने का मौका है आपके पास. इसलिए, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को शायद पहली बार महसूस हुआ कि भाई देश इस तरह नहीं चलता. उन्होंने अच्छी बात कही कि सभी राज्यों से बात करेंगे. मैं समझता हूं कि जीएसटी का थ्रेसहोल्ड, 20 लाख से बढ़ा कर 2 करोड़ रुपए कर देना चाहिए. 2 करोड़ से कम वालों को इसके दायरे से बाहर निकालिए. उसको पुराने सिस्टम से चलने दीजिए. ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दो खतरे हैं. एक बिजनेस गिरेगा, दूसरा कैश ट्रांजेक्शन में बिजनेस शुरू होने लगेगा. छोटा आदमी क्या करेगा? भूखा तो नहीं मरेगा. अर्थशास्त्र बहुत जटिल चीज है, राजनीति आसान है. जुमलेबाजी आसान है. हमलोग राजनीति करते आए हैं. कोई कुछ बोलेगा, जवाब दे देंगे. जवाब देने से कुछ नहीं होगा. एक किलो गेहूं है तो मेरे भाषण से वो दो किलो नहीं हो जाएगा. वो एक किलो ही रहेगा. भाषण देने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी. कारगर कदम उठाने पड़ेंगे. रोजगार देना पड़ेगा. रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा. एक बहुत पुरानी बात कह रहा हूं. मुंबई में एक बार टेक्सटाइल मिलें बन्द हो गईं तो मुंबई में क्राइम रेट बढ़ गया. क्यों? टेक्सटाइल में हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मिला था. बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे? कितनी पुलिस है आपके पास इसे रोकने के लिए? अराजकता जब फैलती है, तो सरकारें चली जाती हैं. पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती. एक तो समस्या अर्थशास्त्र है.

यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ. बहुत बड़ा राज्य है. काम इतना है कि आपको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी. फिर भी आप केरल जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? अगर आपको हिन्दुत्व का उत्थान करना है तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ें. दौरा करें पूरे हिन्दुस्तान का कि हिन्दुत्व का सिर ऊंचा करिए और मुसलमान को दबाइए. ये यूपी का मुख्यमंत्री हो कर आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह वहां जा रहे हैं. वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनका ये काम है. वो अपनी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं. आप अपनी सीमा को समझिए. दुनिया में बुद्धिमान आदमी वो होता है, जिसे अपनी सीमा का ज्ञान हो. मुझे अफसोस है ये कहने में कि बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है. इसलिए मुझे तब खुशी हुई, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि सब ज्ञान हमारे पास है. यही बात वो अपने सहयोगियों, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर को भी समझा दें. मुझे पक्का विश्वास है कि साल भर में हालात सुधर सकते हैं. जो कठिनाई है, मैं व्यापारी वर्ग के बहुत पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं समझता कि वे देश की समस्या का हल कर सकते हैं. लेकिन जो व्यवसाय चलाते हैं, खास कर छोटे और मध्यम वर्ग के, उनके बिना भी देश का विकास नहीं हो सकता. छोटे व्यापारियों को भी आपने लाइन में खड़ा कर दिया, उससे देश का भला नहीं होगा. जल्दी से जल्दी बेहतर कदम उठाएं, लोगों को साथ लेकर चलें, मैं नहीं समझता कि अरुण शौरी या यशवंत सिन्हा के बयानों से कोई समस्या पैदा हुई है. मैं समझता हूं कि जो समस्याएं हैं, उनसे ये बयान पैदा हुए हैं. समस्याएं हटा दीजिए, अपने आप इनके बयान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. समस्या रहेगी, आज एक यशवंत सिन्हा, एक अरुण शौरी हैं, कल को दस और आएंगे. आपकी पार्टी में लोगों की हिम्मत नहीं है आपके खिलाफ बोलने की. आपने दहशत का वातावरण पैदा कर दिया है. लोकतंत्र में ये कब तक चलेगा. जितनी जल्दी मालए को समेटें, लोकतंत्र को पटरी पर लाएं, उतना अच्छा होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार काम से ज्यादा प्रचार पर ख़र्च कर रही है

भारत सरकार एक निश्चित तरीके से काम कर रही है. उसका मानना है कि उसका ये तरीका ही सही है, यानि योजना बनाई, योजना की शुरुआत हुई, फिर कितना काम हुआ, ये नहीं बताते हैं. सभी योजना के पूरा होने में क्या नतीजा निकला, इसके प्रचार में ज्यादा समय लगाते हैं. अब देश में मीडिया पर प्रचार खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि पूरे 11 अरब से ज्यादा रुपए खर्च किए गए. मीडिया को बिकाऊ कहने वाले एक पार्टी विशेष के समर्थकों के लिए यह खबर परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन जो जानकारी आई है, वह बिल्कुल सत्य है. ये जानकारी सरकारी कागजों से निकलकर सामने आई है. नोटबंदी को लेकर विपक्ष के कटघरे में खड़ी केंद्र सरकार इस खुलासे के बाद शायद और घिर सकती है. हालांकि ये नहीं मानना चाहिए कि विपक्ष, जिसने नोटबंदी को लेकर ही सशक्त अभियान नहीं चलाया, वो अब नोटबंदी के अंतर्विरोध को लेकर कौन सा अभियान चलाएगा, इसका किसी को विश्वास नहीं है. पर हम जरूर इस छिपे तथ्य को आपके सामने रख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले साल में अपने प्रचार-प्रसार पर 11 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं. एक सूचना अभियान के संतरी रामबीर तंवर ने 29 अगस्त 2016 से इस बात की तलाश शुरू की. उनका उद्देश्य ये जानना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने से लेकर अगस्त 2016 तक विज्ञापन पर कितना सरकारी पैसा खर्च किया है? जब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ढाई साल में केंद्र सरकार ने विज्ञापन पर 11 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, तो वो चौंक गए और उन्होंने ये जानकारी हमारे पास भेजी. हमने इस जानकारी की पुष्टि की, तब आपके सामने रख रहे हैं.

नोटबंदी को लेकर विपक्ष के कटघरे में खड़ी केंद्र सरकार इस खुलासे के बाद शायद और घिर सकती है. हालांकि ये नहीं मानना चाहिए कि विपक्ष, जिसने नोटबंदी को लेकर ही सशक्त अभियान नहीं चलाया, वो अब नोटबंदी के अंतर्विरोध को लेकर कौन सा अभियान चलाएगा, इसका किसी को विश्वास नहीं है. पर हम जरूर इस छिपे तथ्य को आपके सामने रख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले साल में अपने प्रचार-प्रसार पर 11 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं. एक सूचना अभियान के संतरी रामबीर तंवर ने 29 अगस्त 2016 से इस बात की तलाश शुरू की. उनका उद्देश्य ये जानना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने से लेकर अगस्त 2016 तक विज्ञापन पर कितना सरकारी पैसा खर्च किया है? जब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ढाई साल में केंद्र सरकार ने विज्ञापन पर 11 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, तो वो चौंक गए और उन्होंने ये जानकारी हमारे पास भेजी. हमने इस जानकारी की पुष्टि की, तब आपके सामने रख रहे हैं.

अब हम आपको इस विज्ञापन या प्रचार अभियान के कुछ और तथ्यों से परिचित कराते हैं. ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी रेडियो, इंटरनेट, दूरदर्शन, डिजिटल सिनेमा, प्रोडक्शन, टेलीकास्ट, एसएमएस के अलावा कुछ अन्य रकम भी इस पूरी रकम में शामिल हैं. अब आप देखिए, एसएमएस पर 2014 में 9.07 करोड़ खर्च किए गए. 2015 में 5.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए. अगस्त 2016 तक 3.86 करोड़ रुपए एसएमएस पर खर्च किए गए. इंटरनेट पर 2014 में 6.6 करोड़ और 2015 में 14.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए. अगस्त 2016 तक कुल 1.99 करोड़ रुपए खर्च किए गए. ब्रॉडकास्ट में 2014 में 64.39 करोड़, 2015 में 94.54 करोड़ और उसके बाद अगस्त 2016 तक 40.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए. कम्युनिटी रेडियो पर 2014 में 88.4 लाख, 2015 में 2.27 करोड़ और अगस्त 2016 तक 81.45 लाख खर्च हुए. डिजिटल सिनेमा पर 2014 में 77 करोड़, 2015 में 1 अरब, अगस्त 2016 तक 6.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए. टेलीकास्ट में 2014 में 2.36 अरब, 2015 में 2.45 अरब और अगस्त 2016 तक 38.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए. प्रोडक्शन में 2014 में 8.20 करोड़, 2015 में 13.90 करोड़ और अगस्त 2016 तक 1.29 करोड़ रुपए खर्च हुए.

तीन साल में हर साल कितना खर्च किया गया. 1 जून 2014 से 31 मार्च 2015 तक करीब 4.48 अरब रुपए खर्च किए गए. 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 5.42 अरब रुपए. 1 अप्रैल 2016 से 11 अगस्त 2016 तक 1.20 अरब रुपए.

अब सवाल ये है कि हमारी भारत सरकार कहती है कि हमारी सरकार के सबसे वरिष्ठ लोग अपने चाय के पैसे भी खुद दिया करते हैं. अब सवाल ये आया कि अगर ये जानकारी सही है, जो कि हमारा कहना है कि सही है, 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च किया होगा, ये मोटा अंदाज होता है. लेकिन ढाई साल में 1100 करोड़ रुपए खर्च करने का पता लगने पर जो मन में निराशा उत्पन्न होती है, वो कहती है कि कम से कम इसका भी तो ऑडिट होना चाहिए कि जिन चीजों पर प्रचार का इतना पैसा लगा है, उन चीजों पर आखिर काम कितना हुआ? पर उसकी ऑडिट न कोई मीडिया कर रहा है यानि न टेलीविजन कर रहा है, न अखबार कर रहे हैं. जब ढाई साल में केवल विज्ञापन पर 1100 करोड़ का खर्च आया है, तो पूरे पांच साल में सरकार पर और सरकार के प्रमुख के विज्ञापनों पर तीन हजार करोड़ का अनुमानित खर्च आ सकता है.

अब अगर इसकी तुलना अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प से भी की जाए, तो कहा जा सकता है कि वहां की सरकार ने चुनाव प्रचार में 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. हमारे देश में एक केंद्र सरकार इतना पैसा खर्च कर दे, तो ये चिंतनीय तो है ही. अब ये तथ्य मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये तथ्य उनकी समझ में नहीं आएंगे, जो अंधभक्त हैं. लेकिन जो देशभक्त हैं, उन्हें ये जरूर समझ में आएगा कि ये तथ्य चिंतनीय हैं. चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि जो आलोचना करते हैं, वो निराशा फैलाने वाले लोग हैं. उन्होंने ये भी कह दिया है कि महंगाई हर साल बढ़ती है, क्या पहले महंगाई नहीं बढ़ी. विकास दर गिरती है, तो गिरा करे, क्या पहले विकास दर नहीं गिरी. उन्होंने कह भी दिया कि पांच बार विकास दर गिरी है. सवाल ये है कि आप फिर दूसरों से बेहतर अपने को कैसे कह सकते हैं? आपकी योजनाओं का जो परिणाम लोगों के सामने आना चाहिए, वो परिणाम तो सामने नहीं आ रहा है. और वो परिणाम सामने नहीं आ रहा है, यही चिंता की बात है. हमारा सिर्फ ये कहना है कि निराशा फैलाने वाले लोग, जिन्हें आप चिन्हित कर रहे हैं, वो लोग निराशा नहीं फैला रहे हैं. वो आपके सामने वो तथ्य रख रहे हैं, जिन तथ्यों को भारत सरकार अनदेखा करती रही है. हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत गर्व से कहा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की गति कमजोर हुई है या हम मंदी के दरवाजे पर खड़े हैं. विकास दर कम हुई है. दोनों ने ये कहा था कि हमारी विकास दर बढ़ी है. ये अलग बात है कि उस समय भी हमने लिखा था और कहा था कि सारी दुनिया हमारे आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण को देखकर ये कह रही है कि हम विकसित नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारी विकास दर गिर सकती है. पर सरकार ने तेज-तेज बोलकर ये कहा कि विकास दर बिल्कुल नहीं गिरेगी. विकास दर बढ़ी है, लोग झूठ बोल रहे हैं. अब प्रधानमंत्री स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि विकास दर बाधित हुई है, गिरी है. पर उसे ये निराश लोगों की मन की खीज कहकर अपने को सही साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर विकास दर गिरी? विकास दर गिरती नहीं है क्या? गिरती है, बिल्कुल गिरती है, पर आप फिर एक बार ये विश्लेषण करें, अन्यथा ऐसा न हो कि आपको कभी ये कहना पड़े कि क्या मंदी के दौर आते नहीं हैं? क्या पहले कभी मंदी के दौर नहीं आए? क्या दुनिया मंदी के दौर में नहीं गई? अगर ऐसा है तो मंदी के दौर में दुनिया गई और हम यही तर्क लें कि हम भी इसीलिए मंदी के दौर में हैं. लेकिन, देश चलाने वाले राजनीतिक लोग नहीं, देश चलाने वाले जो अधिकारी हैं, उन पर ये सवाल उठेगा कि इस सरकार के जाने के बाद, ये अधिकारी देश को किस भंवरजाल में छोड़ जाएंगे.■

editor@chauthiduniya.com

भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टेरॉयड्स की ज़रूरत है

असित रंजन मिश्रा, गिरीश चन्द्र प्रसाद

विकास दर में उछाल लाने और नई नौकरियां सृजित करने के वादे के साथ एनडीए 2014 के आम चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई. एनडीए ने भ्रष्टाचार, घोटालों और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध के आरोपों में घिरी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का स्थान लिया. तीन साल बाद एक बार फिर अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है.

वर्ष 2017-18 की जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि तीन साल के निम्नतम स्तर 5.7 प्रतिशत तक गिर गई. वित्तीय स्थिति को संभालने में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट ने सरकार की काफी मदद की, इसके बावजूद चालू खाते का घाटा (सीएडी) इसी तिमाही में पिछले चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया. यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत रहा. हालांकि जब एनडीए ने सत्ता संभाला था, तब निवेश की मांग कमजोर थी, लेकिन नोटबंदी ने निजी खपत (आम खपत) को भी प्रभावित किया और उसमें भी कमी आई. हाल में निर्यात में तेज़ी आई है, लेकिन निर्यात पहले की तरह अब अर्थव्यवस्था का संचालक नहीं रहा. रुपए की बढ़ती कीमतों ने निर्यातकों को मुश्किल में डाल दिया है. जीएसटी (माल और सेवा कर) पूरे देश को एक कर प्रणाली में एकीकृत करती है. इस प्रणाली की जटिलता ने भी आर्थिक संकट में इजाफा किया है. पिछले दिनों आर्थिक ख़बरें प्रमुखता के साथ सुर्ख़ियों में थीं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार कर रही है.

गलती कहां हुई?

भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् और पिछले 25 सालों से सरकारी सेवा में रहे प्रणव सेन ने कहा कि समस्या की शुरुआत ग्रामीण विकास में बदलाव के कारण हुई. वर्ष 2004-2012 की अवधि के दौरान उच्च स्तर पर रही और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया. उनका कहना था कि कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत के दर से बढ़ोतरी हो रही थी जबकि कृषि आय में 7.5 प्रतिशत के दर से वृद्धि हो रही थी. देश के सबसे गरीब तबके की आय में तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से विकास और मुद्रास्फीति दोनों में बढ़ोतरी हो रही थी.

समस्या 2013-14 में शुरू हुई, जब चीजें उलटने लगीं. वैश्विक बाज़ार में खाद्य कीमतों में गिरावट आई, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अब भी एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अपनाए रखा. चयनित कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वृद्धि में नाटकीय कमी आई, जो पहले की औसत 8 फीसदी से गिर कर केवल 3.5 फीसदी प्रति वर्ष रह गई. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों के काम का आश्वासन देता है. 2014 के बाद मनरेगा मांग-संचालित होने के बजाय संसाधन-संचालित योजना बन गई.

2014-15 और 2015-16 के दो सूखाग्रस्त वर्षों में मनरेगा पर ध्यान कम कर देने के कारण ग्रामीण मांग की स्थिति में वृद्धि हुई और ग्रामीण विकास दर को नुकसान हुआ. जब विकास दर घट रहा था, उसी समय नोटबंदी और जीएसटी जैसे संरचनात्मक परिवर्तन ने असंगठित और संगठित क्षेत्रों को करारा झटका दिया.

सरकार द्वारा 9 नवंबर को रातों-रात 86 फीसदी मूल्य की मुद्रा वापस लेने के फैसले के कारण नकदी पर आधारित असंगठित क्षेत्र के उपक्रम ठप हो गए. गौरतलब है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40 फीसदी हिस्सा इन्हीं असंगठित क्षेत्रों से आता है. उस दौरान खरीदारों के अभाव में किसानों ने अपने उत्पाद मजबूरन सड़कों पर फेंक दिए और छोटे दुकानदारों को अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी पड़ी. जीएसटी के क्रियान्वयन ने आपूर्ति नेटवर्क को अस्थिर कर दिया. डीलरों ने स्टॉक कम कर दिया और कंपनियों ने उत्पादन घटा दी. नतीजतन जून तिमाही में जीडीपी तीन साल के सबसे निचले स्तर 5.7 फीसदी पर आ गई. जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तकनीकी खामियों और निर्यातकों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी में असामान्य विलम्ब ने व्यापार की भावना को चोट पहुंचाया.

प्रणव सेन का कहना है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी से सम्बंधित चिंताओं को जल्दी हल नहीं किया गया, तो कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी की मांग में भारी उछाल आएगा, जिसे बैंक संभाल नहीं पाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि फ़िलहाल हम मांग-पक्ष की समस्या से जूझ रहे हैं. यदि आपूर्ति की समस्या को भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो वह अगले दो तिमाहियों के लिए हमारी जीडीपी को नीचे ले आएगा.

हालांकि मोदी सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) सहित कई मौजूदा समस्याएं विरासत में मिली थीं, लेकिन प्रणव सेन के मुताबिक समस्याओं के निदान को समझने में गलती हुई और नोटबंदी व जीएसटी ने संकट को और बढ़ा दिया.

बैंकों के कुल ऋण में कार्यशील पूंजी ऋण का हिस्सा 2002 में 76 फीसदी था, जो वर्तमान में घटकर 48 फीसदी रह गया है. आवास और अचल पूंजी के लिए ऋण, कुल उधार के 24 फीसदी से बढ़कर 52 फीसदी हो गई है. यह सब दिवालियापन जैसे कानून के तंत्र के बिना हुआ है. सेन का कहना है कि यह कानून सात-आठ साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था. उन्होंने बैंकिंग प्रणाली की गड़बड़ी के लिए यूपीए सरकार को दोषी ठहराया है.

सरकारी बैंकों का एनपीए या बुरा ऋण 31 मार्च 2017 तक 6.41 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया. यह ऋण 31 मार्च 2013 तक 1.56 ट्रिलियन डॉलर था. इसमें पुनर्गठन ऋण शामिल नहीं है.

प्रणव सेन ने कहा कि मवेशी व्यापार पर प्रतिबंध ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को और क्षति पहुंचाई है. ग्रामीण भारत में पशु संकट के समय में बीमा की तरह होते हैं. ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बेचे जा सकते हैं. 2017-18 की जून तिमाही में पशुपालन की वृद्धि में कमी का एक कारण मवेशियों की बिक्री पर रोक है. लिहाज़ा इस कारण कृषि विकास भी प्रभावित होता है.

अब क्या करना चाहिए?

ऐसे समय में जब निजी निवेश का अभाव है और सरकारी व्यय ही आर्थिक विकास का एकमात्र प्रेरक है, तो आर्थिक गिरावट की समस्या से निपटना एक कठिन काम होगा. प्रणव सेन कहते हैं कि यहां मौद्रिक नीति-आधारित समाधान कारगर नहीं साबित होगा, क्योंकि बैंक वर्तमान परिदृश्य में ऋण क्षमता में कोई बड़ी वृद्धि नहीं करेंगे. केवल निर्धारित समय सीमा और आक्रामक राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ ही अर्थव्यवस्था को मौजूदा मंदी के दौर से बाहर निकाला जा सकता है.

इस संकट से उबरने का सेन का नुस्खा है, बड़ा नहीं बल्कि छोटा सोचो और अभी से शुरुआत करो. उन्होंने कहा कि फिलहाल बुलेट ट्रेन और आठ लेन के राजमार्ग को भूल जाना चाहिए और ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं जहां जल्द नतीजे हासिल किये जा सकते हैं, पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए.

सेन का कहना है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ावा देने के लिए, राजकोषीय घाटे को फिलहाल 3.5 फीसदी (वर्ष 2017-18 के बजट में इसके लिए 3.2 फीसदी का प्रावधान था) तक और फिर अगले दो वर्षों के लिए 4 फीसदी तक गिरने दिया जा सकता है. मौजूदा आर्थिक संकट में अर्थव्यवस्था के लिए होम्योपैथिक उपचार नहीं, बल्कि स्टेरॉयड्स की ज़रूरत है.■

साभार: मिन्ट

feedback@chauthiduniya.com

स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार का रोड़ा, हर तरफ गंदगी का घाव और फोड़ा

फोटो-सेशन से गंदगी साफ़ नहीं होती

दीनबंधु कबीर

सरकार के स्वच्छता अभियान से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ही कहते हैं कि जब बिना सफाई के ही स्मार्ट सिटी का खिताब और ऊंचा नंबर मिल जाता है, तो सफाई पर अधिक माथा खपाने की क्या जरूरत है! बनारस का प्रसंग आपने देख ही लिया. जब राजनीतिक कारणों से ही किसी क्षेत्र को अव्वल स्थान मिलना है, तो फिर सफाई की जरूरत क्या है! देशभर में स्वच्छता में वाराणसी को 32वां स्थान मिलने से वाराणसी के ही लोग हैरान हैं. लोग पूछते हैं कि काशी में गंदगी तो वैसी ही है, फिर रैंकिंग में तिकड़म कैसे हो गई! आप याद करते चलें कि बनारस देश के 10 सबसे गंदे शहरों में शुमार था. अब वह यूपी का सबसे साफ शहर है. उसे देश के 50 सबसे साफ शहरों में 32वें स्थान पर खड़ा कर दिया गया है. देशभर में सफाई का निरीक्षण-सर्वेक्षण क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने किया. इस संस्था पर घूस लेकर रैंकिंग घटाने-बढ़ाने के गंभीर आरोप हैं. 2014 में पहली बार हुए सर्वे में बनारस सफाई के मामले में 418वें स्थान पर था. वर्ष 2015 में दूसरी बार सर्वे हुआ, तो सौ सबसे साफ शहरों में वाराणसी 69वें स्थान पर आ गया और इस साल उसे 32वां स्थान मिल गया. सफाई की इस घटिया राजनीति के कारण सफाई के काम में लगे विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों का अपने मूल काम से मन हट गया है. अब वे कहते हैं कि जिस नेता की जितनी औकात होगी, वह अपने क्षेत्र को उतने ऊपर की रैंकिंग दिला लेगा. यूपी की राजधानी लखनऊ पर ही इसका बुरा असर पड़ा है. जो लोग बनारस और लखनऊ में सफाई का फर्क जानते हैं, वे रैंकिंग निर्धारण के तौर-तरीके पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं. सफाई के इस तथाकथित सर्वेक्षण में लखनऊ को 269वां स्थान मिलने पर नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा था, 'भई बनारस को मोदी की कृपा से 32वां स्थान मिला और लखनऊ को राजनाथ की औकात से 269वां स्थान मिला, ये तो औकात-औकात की बात है!'

राजधानी लखनऊ की सफाई इसी 'औकात' पर आ गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के साथ सड़क पर झाड़ू लगाते अपना फोटो सेशन भले ही करा लें, लेकिन लखनऊ की सफाई की दशा अत्यंत घटिया स्तर पर आ गई है. जिन दिनों मुख्यमंत्री का फिल्मी हीरो-हिरोइन के साथ झाड़ू फोटो सेशन हो रहा था, उसके कुछ ही दिन पहले नगर निगम सदन की बैठक में यह अधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया कि लखनऊ की सफाई और स्वच्छता का ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो शहर में दिखे. न कूड़ा प्रबंधन योजना आई और न शहर अतिक्रमण से मुक्त हो पाया. शहर सीवर, पेयजल और सफाई समस्या से जूझता रह गया. आवारा पशुओं के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हो पाया. लखनऊ की सड़कों और गलियों में आवारा गायों और खतरनाक कुत्तों की भरमार है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है. हर दिन लोगों के कुत्तों से काटे जाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शहर कुत्तों और उनके प्रेमियों से परेशान है. नगर निगम ने खुद ही यह माना है कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत ट्रांसगोमती में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हो पाया. शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सका. पार्षद निधि से लगे सब-मर्सिबल पंप समय से पहले ही खराब हो गए. अतिक्रमण हटाने और पटरी दुकानदारों के लिए फेरी नीति लागू कराने की दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ. अनियोजित कॉलोनियों का विस्तार रोकने के बजाय नेताओं और पार्षदों ने ऐसी कॉलोनियों में अपनी विकास निधि लगाकर उसे बढ़ावा देने का काम किया. शहर में नई कैटल कॉलोनी बनाने की दिशा में भी कोई योजना नहीं बनी. राजधानी की सफाई का हाल यह है लेकिन मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को झाड़ू के साथ फोटो खिंचाने और अखबार में छपवाने में कोई झेंप भी नहीं होती.

लखनऊ में करीब नौ सौ करोड़ रुपए खर्च कर विभिन्न इलाकों में सीवर लाइन डालने का काम हुआ था. लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ. सात साल से सीवर का काम ही चल रहा है. दरअसल, यह भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है. नेता से लेकर नौकरशाह और ठेकेदार तक सीवर का गंदा पैसा खाने से भी हिचक नहीं रहे हैं. जल निगम के परियोजना प्रबंधक (अस्थायी गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई) की ताजा रिपोर्ट को लेकर सफाई पसंद नागरिक हतप्रभ हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि नालियों को सीवर लाइन से जोड़ना बंद नहीं किया गया, तो सीवर योजना ध्वस्त हो जाएगी. लखनऊ के दौलतगंज, दुबग्गा, बालागंज की 369 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भीषण मुश्किलों में है. इस इलाके में सीवर कनेक्शन देने के लिए 7682.57 लाख की योजना मंजूर की गई थी. इसी तरह अलीगंज, जानकीपुरम, कल्यापापुर, विकासनगर, रहीमनगर, खुर्रमनगर, महानगर, निरालानगर, डालीगंज और निशातगंज इलाकों में जेएनयूआरएम के तहत पांच सौ किलोमीटर सीवर लाइन डाली गई थी. इन इलाकों में 50 हजार से अधिक घरों में सीवर का कनेक्शन करने के लिए 13933.27 लाख मंजूर किए गए थे. इंदिरा नगर, गोमती नगर और फैजाबाद रोड से जुड़े इलाकों में भी 350 किलोमीटर सीवर लाइन डाली गई थी. यहां साढ़े 24 हजार घरों में सीवर का कनेक्शन होना है. जिस पर 7920.50 लाख की योजना को मंजूरी मिली. लेकिन यह सब घपले-घोटाले की भेंट चढ़ गई. वर्ष 2008 से शुरू हुए सीवर लाइन के काम में जल निगम ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की. बसपा सरकार और सपा सरकार के अलमबरदारों ने भी इस गंदगी में खूब मुंह मारा. इसका असर यह पड़ा कि ठेकेदारों ने सीवर लाइन तो डाल दी, लेकिन मैनहोल बनाने के दौरान डाली गई बोरियां और मलबे वहीं छोड़ दिए. सीमेंट और कंकरीट के मलबों की सफाई न होने से सीवर लाइनें शुरू होने के पहले ही जाम हो गईं. विडंबना यह है कि जलकल महकमे ने कागज पर सीवर लाइनों का हैंड-ओवर दिखा दिया, जबकि सीवर लाइन आज तक चालू ही नहीं हो पाई.

विकास जन कल्याण सेवा समिति इंदिरा नगर के मुख्य संरक्षक समाजसेवी विजय गुप्ता कहते हैं कि यह राजधानी लखनऊ का दुर्भाग्य है कि 900 करोड़ रुपए फूंकने के बाद भी आज तक सीवर लाइन शुरू नहीं की जा सकी. अकेले इंदिरा नगर के ही करीब 12 लाख उपभोक्ताओं को सीवर लाइन की सुविधा नहीं मिल रही. शहर में गंदगी से बजबजाती नालियों और जलभराव की समस्या आम है. स्वच्छ भारत के राजनीतिक नारे की यही जमीनी असलियत है. विजय गुप्ता ने दीनदयालपुरम तकरोही का हवाला देते हुए बताया कि वहां जब सीवर लाइन बिछाने काम शुरू हुआ, तो सीवर लाइन की निकासी के लिए उचित गहराई नहीं मिल पाई. इसके बावजूद लाइन डालकर मिट्टी डाल दी गई. अब वहां सीवर लाइन दोबारा उखाड़ने की नौबत है, या उसे छोड़ कर दूसरी सीवर लाइन निर्धारित गहराई में फिर से लगाई जाएगी. झाड़ लगा कर फोटो खिंचवाने वाले नेताओं को यह गंदगी नहीं दिखती. गुप्ता कहते हैं कि सीवर लाइन शुरू भी नहीं हुई, लेकिन सीवर लाइन के चैंबर्स के प्लास्टर झड़ कर दीवार को नंगा कर चुके हैं. कई जगह इस सीवर लाइन में स्थानीय लोगों ने अनधिकृत रूप से सीवर जोड़कर चैंबर्स को जाम कर दिया है. कई इलाकों में सीवर लाइन बिछने से पहले ही नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण कर दिया गया. फिर नई बनी सड़कों को खोद कर सीवर लाइन डाली गई. यह गड़बड़झाला करोड़ों रुपए खाने के लिए किया गया.

स्वच्छता के महा-अभियान का यह हाल है. जेएनयूआरएम योजना के तहत तकरीबन डेढ़ हजार किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने का काम जल निगम ने वर्ष 2007 में ही शुरू किया था. इसे 2014 तक पूरा कर देना था. लेकिन जल निगम ने इस काम में घोर लापरवाही बरती. इस लापरवाही के कारण डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में ही करीब 50 हजार कनेक्टिंग चैंबर्स का प्रावधान नहीं हो सका. जल निगम द्वारा डीपीआर में लापरवाही बरतने के कारण सीवर लाइन का बजट गड़बड़ हो गया. एक आला अधिकारी ने कहा कि जल निगम ने उसी समय सरकार से कनेक्टिंग चैंबर्स का बजट मांग लिया होता, तो यह समस्या नहीं आती. उक्त अधिकारी का कहना था कि परियोजना में तकनीकी खामियों के साथ-साथ लापरवाहियों के कारण योजना के पूरे होने का समय बढ़ता चला गया और देरी के कारण बजट में प्रस्तावित लागत भी बढ़ती रही.

मामला केवल सीवर से फैल रही गंदगी का ही नहीं है. राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के किसी भी शहर में जाएं, सड़कों पर कूड़े के अंबार मिलेंगे और गलियां गंदगी से बजबजाती मिलेंगी. जहां नेता झाड़ू लगाने जाते हैं, वहां पर पहले से सफाई कर दी जाती है. अखबार वालों को बुला लिया जाता है और झाड़ू लेकर स्माइल-प्लीज के साथ फोटो खिंच जाती है. जिस तरह आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को बेचने की सियासत की उसी तरह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और स्वच्छता को बेचने की सियासत कर रही है. आम आदमी को भी खुद को बिकवाने और गंदगी में ही मजा लेते रहने की आदत पड़ चुकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

वाह ताज नहीं, दाद खाज बोलिए...

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने आगरा को पर्यटन की सूची में शामिल नहीं करने की चूक तो की, लेकिन उससे ताजमहल का महत्व कम नहीं हो गया. पर्यटन की दृष्टि से आगरा का महत्व बना रहेगा. लेकिन स्वच्छता की दृष्टि से आगरा की बदनुमा तस्वीर ही सामने है. भ्रष्टाचारी नेताओं-नौकरशाहों और ठेकेदारों ने पूरे स्वच्छता अभियान को अपना चारा बना लिया है. आगरा शहर के कई हिस्सों में सीवर लाइन नहीं बिछने से भीषण गंदगी फैल रही है. बड़ी मात्रा में दूषित जल भूगर्भ में समा रहा है. करोड़ों रुपए खर्च कर जहां सीवर लाइन डाली भी गई, वह सब ध्वस्त और नाकाम हो चुकी है. सीवर लाइन से कनेक्शन ही नहीं किए गए. सीवर का गंदा पानी भूगर्भ में जा रहा है या सड़कों पर बह रहा है. वर्ष 2008 में ही यहां की भीम नगरी और देवरी रोड पर सीवर लाइन बिछाने के लिए 53.36 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था. जल निगम ने 63 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाकर जल संस्थान को सौंप भी दी, लेकिन यह सब कागजों पर हो गया. जमीनी असलियत यही है कि अभी तक सीवर लाइन का निस्तारण नहीं हो सका है. जगह-जगह काम अधूरा होने से सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं.

सीवेज मास्टर प्लान में आगरा शहर को आठ जोन में बांटा गया था. यमुना एक्शन प्लान और जेएनएनयूआरएम के तहत सीवर लाइनें बनीं. जल संस्थान ने सीवर लाइन जल निगम को हस्तांतरित भी कर दी, लेकिन इन सीवर लाइनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग चैंबर ही नहीं बनाए गए. लिहाजा, ये चालू ही नहीं हुए. आगरा सीवेज स्कीम फेज-वन में सेंट्रल और ताजगंज जोन में सीवर लाइन, पंपिंग स्टेशन और एसटीपी के लिए 195 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था. सेंट्रल सीवर लाइन के लिए शाहजहां पार्क से पुरानी मंडी मार्ग के बीच कॉमन चैंबर प्रस्तावित हैं. लेकिन ये सीवर चैंबर नौकरशाही के चैंबर में फंस गए हैं. ताजनगरी में यमुना किनारे बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फेल पड़े हैं. सीवर लाइन नहीं होने से कई इलाकों से गंदगी नालों के जरिए बहती हुई सीधे यमुना नदी में गिर रही है. यह सत्ताधारियों को नहीं दिखता. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि आगरा क्षेत्र का भूगर्भ जल भयानक रूप से प्रदूषित हो चुका है. इससे डेंटल फ्लोरोसिस के साथ-साथ अन्य कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं. यमुना सूखती जा रही है. तालाबों पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं. सीवर और औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी भूगर्भ जल को दूषित कर रहा है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा के 15 ब्लॉकों में 46 जगह से पानी के सैंपल लिए थे. उसकी जांच में अलग-अलग क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 से 12.8 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. मानसून बाद लिए गए 27.4 प्रतिशत नमूनों में यह अधिकतम सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी अधिक मिली. आगरा के नगला तल्फी, देवरी की गढ़ी, जारुआ कटरा, मुहम्मदाबाद और नगला प्रताप सिंह में डेंटल फ्लोरोसिस के गंभीर लक्षण देखे गए. पट्टी पचगाई में प्रदूषित भूगर्भ जल के चलते हड्डियों की विकृति के कई मामले सामने आए. 46 प्रतिशत नमूनों में क्लोराइड जरूरत से अधिक पाया गया. 11.6 प्रतिशत नमूनों में यह अंतिम सीमा 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी अधिक पाया गया. 28 प्रतिशत नमूनों में कैल्शियम जरूरत से अधिक पाया गया. 80 प्रतिशत नमूनों में आयरन की उच्च मात्रा पाई गई. 92 प्रतिशत नमूनों में मैग्नीशियम जरूरत से अधिक पाया गया, यहां तक कि 31.3 प्रतिशत नमूनों में यह अधिकतम सीमा से भी अधिक मिला. 15.7 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा अधिकतम सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मिली और 49 प्रतिशत से अधिक नमूनों में सोडियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई. पेट की बीमारियां बढ़ाने वाले टीडीएस की मात्रा भी आगरा के पानी में खतरनाक स्तर पर पाई गई है. मानक के अनुसार एक लीटर पानी में 500 माइक्रोग्राम टीडीएस ही होना चाहिए, जबकि आगरा शहर के पानी में टीडीएस की मात्रा प्रति लीटर पानी में 722 से 1910 माइक्रोग्राम पाई गई है. ■

पर्यटन बुकलेट से ताजमहल का नाम ग़ायब, मची चिल्लपों

विवाद को तो मौक़ा चाहिए

रामभरोसे दास

उत्तर प्रदेश के नौकरशाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कबाड़ा निकालने पर आमादा हैं. पहले से कई विवादों में बेवजह उलझा दिए जाने के बाद अब नया मामला पर्यटन विभाग के बुकलेट-विवाद का है. पर्यटन विभाग के बुकलेट में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आगरा का नाम शुमार नहीं है. इस वजह से विवाद भड़का और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर सपा नेता अखिलेश यादव और बात-बहादुर नेता आजम खान तक को बोलने का मौका मिल गया. राहुल ने ट्वीट किया, 'अंधेर नगरी, चौपट राजा'. अखिलेश ने कहा कि ताजमहल देश की पहचान है और बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया भी है. आजम खान ने कहा कि ताजमहल, लालकिला, राष्ट्रपति भवन, संसद, कुतुबमीनार सब गुलामी की निशानी हैं. फिर कहा ताजमहल को ध्वस्त ही कर देना चाहिए. इसमें वे सरकार का सहयोग करेंगे. रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन योगी सरकार ताजमहल को भी साम्प्रदायिकता के चश्मे से देख रही है. रालोद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल दुबे ने भी पर्यटन विभाग के बुकलेट से ताजमहल गायब के जाने को निंदनीय कृत्य बताया. पर्यटन विभाग की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी हैं. लेकिन इस भूल का ठीकरा योगी के मत्थे ही फूटा. सचिवालय में आसीन एक आला अधिकारी ने सवाल उठाया कि पर्यटन विभाग के बुकलेट में आगरा को शामिल नहीं किया जाना तकनीकी भूल है या नौकरशाहों की तिकड़म, इसकी जांच होनी चाहिए. विभागीय मंत्री ने इसे टालने की ही कोशिश की, लिहाजा तिकड़म वाला पक्ष संरक्षण-छाया में चला गया. इसका खामियाजा आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही भुगतना होगा. अन्य नेता और नौकरशाह भी यही चाहते हैं.

इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से विश्व पर्यटन दिवस पर जारी की गई बुकलेट 'उत्तर प्रदेश पर्यटन-अपार संभावनाएं' में ताजमहल को जगह नहीं दी गई. बुकलेट में प्रदेश के तकरीबन सभी पर्यटन स्थलों को शामिल किया

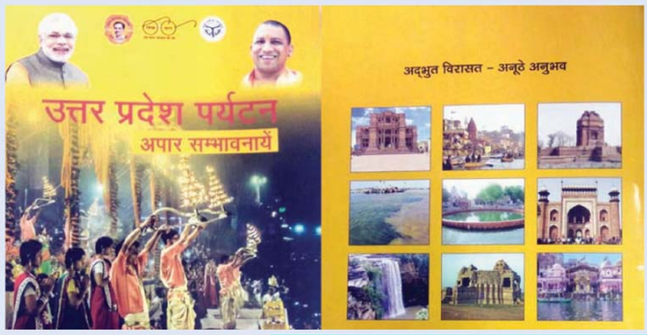

गया, लेकिन इसमें ताजमहल कहीं नहीं है. बुकलेट में वाराणसी की गंगा आरती, गोरखपुर की गोरक्षधाम पीठ, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को जगह दी गई, लेकिन ताजमहल का जिक्र नहीं किया गया. यह प्रथम दृष्टया ही नौकरशाही की करतूत की तरफ इंगित करता है, क्योंकि पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ताजमहल और आगरा का जिक्र प्रमुखता से है. बुकलेट के कवर पर गंगा आरती की तस्वीर है. कवर पर बाईं तरफ मोदी और दाईं तरफ योगी की फोटो लगी है. अंदर पर्यटन विभाग की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की भी फोटो लगी है. बुकलेट के पहले पेज पर भूमिका है और पर्यटन विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र है. वाराणसी की गंगा आरती का वर्णन काफी महत्व देकर किया गया है. मथुरा के लिए भी बुकलेट के दो पन्ने दिए गए हैं. एक पृष्ठ पर रामायण परिपथ और बौद्ध परिपथ का जिक्र है. इसके बाद अयोध्या की जानकारी दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरयू की आरती की तस्वीर भी अंदर लगी हुई है. बुकलेट में गोरक्षपीठ और देवीपाटन शक्ति पीठ के साथ-साथ शाकम्बरी माता मंदिर और चुनार के ऐतिहासिक किले की भी चर्चा है. एक अधिकारी ने बुकलेट से ताजमहल को गायब किए जाने के पीछे किसी तिकड़म की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजमहल को यूपी की सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल नहीं किया था. कई भाजपाई ही कहते हैं कि ताजमहल को लेकर योगी आदित्यनाथ की अलग राय रही है. बिहार के दरभंगा में हुई रैली में योगी ने कहा भी था कि उनकी नजर में ताजमहल एक इमारत के सिवा और कुछ नहीं है. योगी यह भी बोल चुके हैं कि यूपी की पहचान ताजमहल से नहीं, बल्कि राम-कृष्ण से है. योगी के करीबी सूत्रों का कहना है कि पर्यटन बुकलेट के प्रकाशन में मुख्यमंत्री से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया और न योगी ने ताजमहल का जिक्र हटाने का कोई निर्देश दिया था. इसकी जिम्मेदारी विभागीय मंत्री और अधिकारियों की थी.

बहरहाल, इस मामले के तूल पकड़ने पर प्रदेश सरकार ने इसके पीछे किसी गलत मंशा से इंकार किया और कहा कि पर्यटन विकास को लेकर आगरा में तमाम योजनाएं चल रही हैं. ताजमहल और उससे जुड़े क्षेत्र में 156 करोड़ रुपए की विकास-योजना पर काम चल रहा है. इसके अलावा ताजमहल के पश्चिमी गेट पर 107.49 करोड़ रुपए की लागत से रिसेप्शन सेंटर का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा ताजमहल और आगरा किले के बीच शाहजहां पार्क और वॉक-वे के पुनरुद्धार के लिए 22 करोड़ 66 लाख रुपए की परियोजना भी शामिल की गई है. पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ताजमहल और आगरा का विकास केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की प्राथमिकता में है. उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के बुकलेट में अगले एक वर्ष में जो काम होने हैं, उनके बारे में दर्शाया गया है. बुकलेट में चित्र न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. उल्लेखनीय है कि 28 सितम्बर को विभाग की छहमाह की उपलब्धियां बताने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे गए बुकलेट 'उत्तर प्रदेश पर्यटन: अपार संभावनाएं' में ताजमहल का कोई जिक्र नहीं पाया गया, जबकि बुकलेट में आगरा की विकास योजनाओं का जिक्र जरूर था. इसके बाद ही विवाद ने तूल पकड़ा. ■

feedback@chauthiduniya.com

उन्हें यह भी नहीं पता कि कबीर का जन्मस्थल कहां

पर्यटन स्थलों को लेकर इसके पहले भी विवाद होते रहे हैं. निवर्तमान सपा सरकार के कार्यकाल में भी ऐसा ही विवाद कबीर जन्मस्थली को लेकर हुआ था. इस पर देशभर के कबीरपंथियों में भीषण नाराजगी फैली थी, लेकिन मीडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. मीडिया का एंगल भी साम्प्रदायिक ही रहता है. अखिलेश यादव के शासनकाल में कबीर के जन्मस्थल को लेकर प्रकाशित साहित्य में गड़मड्ड तथ्य छप गए थे. तत्कालीन सरकार को यही नहीं पता था कि संत कबीर का जन्मस्थल कहां है और निर्वाण स्थल कहां. पर्यटन योजनाओं को लेकर सरकार का जो साहित्य प्रकाशित हुआ था, उसमें मगहर को संत कबीर का जन्मस्थान लिखा गया था. इतना ही नहीं मगहर को वाराणसी में दिखा दिया गया था. जबकि मगहर संत कबीर नगर जिले में स्थित है और वह कबीरदास की निर्वाणस्थली है.

खतरे में आल्हा-ऊदल की निशानी पुरातत्व विभाग ख़ामोश!

संजीव गुप्ता/आशीष शुक्ला

सीतापुर के बेरिहागढ़ का डीह आल्हा-ऊदल की ऐतिहासिक निशानी है, जो सरकारी उपेक्षा के कारण खतरे में है. शासन या पुरातत्व विभाग इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. खुदाई के दौरान सोने-चांदी के सिक्के मिलने से लोभ में आए यहां के लोग चोरी छुपे डीह को खोदने में लगे रहते हैं. बेरिहागढ़ में खुदाई के दौरान एक विष्णु भगवान की मूर्ति मिली, जो पुरातात्विक दृष्टि से बेशकीमती बताई जाती है. मूर्ति के सिर पर शेषनाग बना हुआ है. खुदाई के दौरान वह टूट गया था. इतिहासकार इसे गांधार अथवा मथुरा शैली की बताते हैं. पाई गई मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और 'थ्री-डायमेंशनल' सिलवटें भी दिखती हैं. लोगों को वहां से यक्ष और यक्षणी की मूर्तियां भी मिली हैं. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि करीब बीस साल पहले तकिया गांव के एक व्यक्ति को खुदाई में एक तलवार मिली थी. लोहारों की लाख कोशिश के बाद भी वह तलवार कट नहीं पाई, आखिरकार उसे गड़ी के सूखे कुएं में डाल दिया गया था. स्थानीय लोगों की मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थली को पुरातत्व विभाग अपने अधीन ले और दुर्लभ मूर्तियों को संग्रहालय में सुरक्षित कराने की पुख्ता व्यवस्था हो.

महोली तहसील मुख्यालय से करीब दस किलोमीटर उत्तर-पश्चिम की ओर बसे सीलहट गांव में मां सिलहट देवी का मंदिर है. जनश्रुतियों के मुताबिक वीर योद्धा आल्हा के आवाहन पर मां सिलहट देवी प्रकट हुई थीं. सिलहट देवी मैहर वाली शारदा माई का ही दूसरा रूप हैं. शारदा माई का मुख्य मंदिर मैहर तहसील इलाके में मिर्जापुर गांव में त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है. बात गांजर की लड़ाई के समय की है. आल्हा माड़ौगढ़ के राजा देशराज के पुत्र थे. इनकी माता का नाम देवल और भाई का नाम उदल था. दोनों भाइयों की वीरता का कोई सानी न था. स्वाभिमान के चलते जब आल्हा-ऊदल ने महोबा छोड़ा तो कन्नौज के राजा जयचंद ने उन्हें अपना सेनापति बनाया. उस वक्त कन्नौज की रियासत नेपाल की सीमा तक फैली थी. यह इलाका गांजर कहलाता था. इस इलाके में करीब नब्बे गढ़ आते थे. पिसावां थाना क्षेत्र का रेतुहागढ़ वर्तमान में सेरवाडीह के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि बेरिहागढ़ वर्तमान में महोली के बेरिहा और मितौली के हिन्दूनगर व सहिबानगर के नाम से जाने जाते हैं. ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए बुद्धिजीवी बताते हैं कि रेतुहागढ़ के राजा अरसिंदसेन और बेरिहागढ़ के राजा हीर सिंह और बीर सिंह थे. इन गढ़ के राजाओं ने करीब बारह वर्ष से लगान नहीं दिया था. जयचन्द्र ने अपने गोद लिए बेटे लाखन के साथ आल्हा-ऊदल को लगान वसूलने के लिए भेजा था. रेतुहागढ़ फतह करने के बाद आल्हा की सेना ने कठिना नदी के किनारे डेरा डाल दिया. हीर सिंह और बीर सिंह ने लगान न देकर युद्ध का ऐलान किया. बेरिहागढ़ जीतने के लिए आल्हा की सेना ने हीर सिंह से भयानक युद्ध किया. यह गिरधरपुर और जमुनिया गांव के बीच हुआ था. युद्ध तीन माह तेरह दिन चला, जिसमें आल्हा की सेना की भारी क्षति हुई. आल्हा ने अल्हना से पांच किलोमीटर पूरब एक जंगल में आकर पुत्रजयी के वृक्ष के नीचे अपनी आराध्य देवी शारदा माई का आह्वान किया. आल्हा की पूजा पर शारदा देवी जीवधारी शिला के रूप में प्रकट हुईं और आल्हा को जीत का वरदान दिया. वे वहीं विराजमान हो गईं. आल्हा ने उन्हें सिलहट देवी का नाम दिया था. इसी शिला में बीचे पांच मन वजन सोने की जंजीर भी बंधी हुई है. स्थानीय लोग बताते हैं कि सिलहट देवी के मंदिर में आज भी चमत्कार हुआ करते हैं. यहां प्रतिदिन पहली पूजा कोई रहस्यमयी अदृश्य शक्ति करती है. सिलहट देवी के नाम पर सीलहापुर गांव बसा हुआ है. गांजर की लड़ाई में बेरिहागढ़ जीतने के बाद आल्हा की सेना आगे बढ़ी. सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर आगे का इलाका आज भी गांजर कहलाता है. यहां के रेउसा इलाके के सेउता गांव में युद्ध के दौरान आल्हा की पत्नी मछला उर्फ सोनवा ने शारदा देवी की आराधना की थी. उनके आदेशानुसार सोनवा ने वहां एक शिला (पिंडी) स्थापित की थी. इस पिंडी पर सोनवा की उंगलियों के तीन गहरे निशान आज भी मौजूद हैं. यह मंदिर सोनासरि देवी के नाम से विख्यात है. अमावस्या को यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

गांजर युद्ध के दौरान जिस जगह आल्हा की सेना ठहरी थी, वह गांव आज महोली कोतवाली क्षेत्र में अल्हना के नाम से प्रसिद्ध है. गांव के पश्चिम नदी के करीब तीस फिट ऊंचा एक टीला है, जो आज भी दुर्गन के नाम से प्रसिद्ध है. बताया जाता है कि आल्हा की सेना इसी टीले पर तोप रखकर बेरिहागढ़ पर गोले दागती थी. बताया जाता है कि इस टीले में खजाना गड़ा है. यही खजाना पाने की लालसा में यहां खुदाई की कोशिशें होती रहती हैं. इसी कोशिश में रहमतुल्ला को सुरंग दिखी थी. लेकिन डर के कारण उन्होंने उसे नहीं खोदा. वे बीमार पड़ गए. इससे भय और फैला. अब लोग वहां खुदाई नहीं करते. बुजुर्ग सदानन्द बताते हैं कि इसी टीले के पास एक काला सांप है. जब वह बाहर निकलता है, तो आस-पास की घास जल जाती है. सुभान बताते हैं कि सिद्धन तालाब में करीब पचास वर्ष पहले मगरमच्छ आ जाते थे. अल्हना गांव से करीब चार किलोमीटर पहले बेरिहा गांव है. नदी के उस पार बेरिहा के राजा हीर सिंह और बीर सिंह का गढ़ था. इसलिए इसका नाम बेरिहागढ़ पड़ा. जनश्रुतियों और आल्हाखंड की पुष्टि के लिए 'चौथी दुनिया' की टीम नदी के उस पार गई और कामतादास गद्दी में बने भगवती मंदिर के वयोवृद्ध पुजारी बाबा कामतादास से मुलाकात की. उन्होंने कई एकड़ तक मिट्टी में धंसे ईंट के अवशेष और गहराई में बनी नींव की श्रृंखला दिखाई, जो वहां भव्य भवन होने की गवाही देते हैं. पुरातत्व विभाग इसे अग्रिगृहीत कर शोध को आगे बढ़ा सकता है. नदी के जीर्ण-शीर्ण पुल के सामने घुड़साल के ध्वसावशेष हैं. नदी के किनारे ही बेरिहागढ़ के राजाओं की कुलदेवी नकटी देवी का स्थान है. यहां खुदाई करने पर जो ईंटें मिलीं हैं, उनकी लम्बाई एक फुट और चौड़ाई नौ इंच है. बुजुर्ग भी बताते हैं कि उस तरह की ईंटें बनते हुए उन्होंने कभी नहीं देखी. खुदाई में मिले नर कंकाल भी अभी की मानवाकृति के विपरीत काफी बड़े और विशाल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

योगी आदित्यनाथ के मुख्य ट्रस्टी बनने के बाद भी नहीं हो सका जीर्णोद्धार

कायाकल्प की राह देख रहा कपिल धारा आश्रम

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार के प्रमुख आध्यात्मिक शहर गया में स्थित प्रसिद्ध ऋषि कपिल मुनि का आश्रम प्राचीन काल से ही एक तपस्थली के रूप में विख्यात रहा है. धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कई संत-महात्मा इस आश्रम में आकर तप-सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं. लेकिन ब्रह्मयोनी पहाड़ी की तलहटी में स्थित यह आश्रम आज अपने हाल पर आंसू बहा रहा है. कपिल धारा आश्रम की 12.50 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ पर भूमि पर अभी भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है. इस आश्रम के मुख्य ट्रस्टी योगी आदित्यनाथ जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने, तो यह संभावना जगी थी कि अब इस आश्रम का भी उद्धार हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा.

कहा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता ऋषि कपिल मुनि जब श्राद्ध करने गया आए थे, तब इस आश्रम के निकट स्थित रुक्मिणी सरोवर से पश्चिम ब्रह्मयोनी पहाड़ की तलहटी में उन्होंने अंजलि से पितृ तर्पण किया था. उनकी अंजलि से गिरे जल ने धारा का रूप ले लिया, जिसे आज कपिल धारा कहा जाता है. यह धारा आज भी पहाड़ से सालो भर अविरल प्रवाहित होती है. इसके स्त्रोत का आज तक पता नहीं चल सका है. करीब 250 साल पूर्व यहां तपस्या के लिए पहुंचे एक सिद्ध महात्मा ने यहां कपिल धारा आश्रम का निर्माण कराया था. 1905 में यहां के श्रद्धालुओं ने इस आश्रम का जीर्णोद्धार कराया था. बताया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी को कपिल धारा आश्रम में ही कठिन तपस्या के बाद सिद्धी की प्राप्ति हुई थी. पटियालाराज के राजकुमार भी सांसारिक सुख छोड़कर तपस्या के लिए कपिल धारा आश्रम में ही आए थे. तपस्या के बाद वे गया में लंगटा

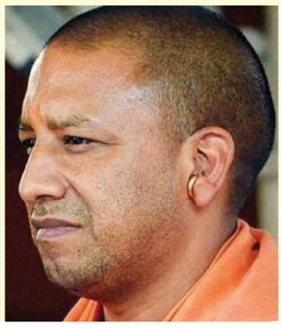

बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए. आज भी कपिल धारा आश्रम में उनकी समाधी है. पहाड़ी बाबा, योगीराज गंभीरनाथ जी महाराज, स्वामी आत्मानंद और स्वामी स्वरूपानंद ने भी इसी आश्रम में तपस्या कर सिद्धी प्राप्त की थी. इस तपोभूमि का महात्म्य इतना है कि चैतन्य महाप्रभु भी यहां दर्शन को आए थे. स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, योगी अवैद्यनाथ जी महाराज समेत कई सिद्धहस्त लोग यहां आ चुके हैं. कपिल धारा की गुफाओं में ऋषि-मुनि कठोर तपस्या और सिद्धी की प्राप्ति करते थे. इनमे से तीन गुफाओं में आज भी नियमित रूप से पूजा-पाठ होता है, लेकिन संकीर्ण रास्ता और अंधेरा होने के कारण चार गुफाओं के अंदर कोई भी जाने का साहस नहीं कर पाता है. कपिल धारा आश्रम की सेवादार इमा गिरी और बंसत गिरी बताते हैं कि आश्रम की चारो गुफाओं में आज भी दैविक और चमत्कारिक शक्तियां है. इनका कहना है कि आश्रम की इन गुफाओं में पंचमुखी

नाग देवता का भी वास है. बताया जाता है कि कपिल धारा आश्रम की इन गुफाओं में तपस्या करने वाले ऋषि-मुनि गुफा के रास्ते से ही ब्रह्मयोनी पर्वत के शिखर पर स्थित शिव मंदिर तक पूजा करने जाते थे. कपिल धारा आश्रम कभी शहर का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक स्थल हुआ करता था. लेकिन आज यह आश्रम अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जद में है. सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भू-मफियाओं ने फर्जी कागजात बनाकर यहां की जमीनों पर कब्जा कर रखा है. यहां पक्के मकान भी बना दिए गए हैं. दो दशक पूर्व गया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमृत लाल मीणा ने यहां की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया था, लेकिन बाद में प्रशासन की उदासिनता से अतिक्रमण और अवैध कब्जे का वही सिलसिला फिर शुरू हो गया. जिस कपिलेश्वर महाराज की पूजा-पाठ से कई संत-महात्माओं ने सिद्धी प्राप्त की, वे आज यहां अवैध निर्माण वाले भवन में कैद हो गए हैं. जिसके कारण यहां पूजा-पाठ भी बंद हो गया है. आश्रम के मंदिरों में स्थापित कई प्राचीन मुर्तियां भी चोरों की भेंट चढ़ गई हैं. इस मंदिर के सेवादार ने बताया कि आश्रम को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए कई बार सरकारी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने आपेक्षिक सहयोग नहीं किया.

कपिल धारा आश्रम योगी आदित्यनाथ के परगुरु और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर रह चुके योगी गंभीरनाथ जी महाराज की तपस्थली रही है. योगी गंभीरनाथ जी महाराज के शिष्य योगी अवैद्यनाथ जी महाराज इस आश्रम के मुख्य ट्रस्टी थे. उनके निधन के बाद योगी आदित्यनाथ कपिल धारा आश्रम के मुख्य ट्रस्टी बने. आश्रम से जुड़े लोगों ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कई बार योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई. उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संभावना जगी थी कि वे अब इस आश्रम के कायाकल्प की दिशा में कुछ काम करेंगे, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई काम होता नहीं दिख रहा है. हालांकि योगी आदित्यनाथ ने गया के कपिल धारा आश्रम आने की इच्छा प्रकट की है. आश्रम के एक ट्रस्टी ने 'चौथी दुनिया' को बताया कि 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां आकर समस्याओं का संज्ञान लेना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है, तो ऐतिहासिक कपिलधारा आश्रम पुनः अपने प्राचीन स्वरूप में लौट आएगा.'■

feedback@chauthiduniya.com

मेडिकल कॉलेज व अस्पताल निर्माण में आड़े आ रही प्रशासन की उदासीनता

अधर में लटकी 155 करोड़ की योजना

सुनील सौरभ

शराबबंदी के बाद से बिहार राजस्व की राह देख रहा है. ऐसे में किसी भी अच्छी परियोजना के प्रस्ताव का स्वागत होना चाहिए. लेकिन सरकारी कर्मियों व उच्चाधिकारियों की नकारात्मक सोच के कारण बिहार इस मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहा है. अधिकारियों की उदासीनता के कारण निवेश के इच्छुक लोग भी हाथ पीछे खींच लेते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, बोधगया में. एक बड़ी परियोजना का प्रस्ताव बिहार के बोधगया में था, जो मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नकारात्मक सोच के कारण अब खटाई में पड़ गया है.

पिछले 35 वर्षों से गरीबों के लिए निःशुल्क आंख ऑपरेशन का कैम्प लगाने वाले देश के बड़े हीरा व्यवसायी और प्रसिद्ध गांधीवादी महेश भाई भंसाली ने बोधगया फाउंडेशन के तहत 155 करोड़ की लागत से अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव मगध विश्वविद्यालय (मविवि) को दिया था. दिसम्बर 2015 में मगध विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए गए इस प्रस्ताव में करीब 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की बात कही गई थी. इसमें कहा गया था कि मविवि प्रशासन अगर अपने परिसर या फिर आसपास कहीं 25 एकड़ जमीन लीज पर भी उपलब्ध कराता है, तो दो चरणों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की योजना को पूरा कर लिया जाएगा. इस योजना का डीपीआर बना कर राज्य सरकार और तत्कालीन कुलाधिपति रामनाथ कोविंद को भी भेजा गया था. तब कुलाधिपति ने इसे बिहार के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था. बोधगया फाउंडेशन के इस प्रस्ताव को तत्कालीन कुलपति डॉ. एम इश्तेयाक ने बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भेजते हुए पीपीपी मोड पर इसके संचालन की अनुमति मांगी थी. लेकिन तत्कालीन कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस योजना को खटाई में डाल दिया गया. 10 सितम्बर 2016 को मविवि के सिंडिकेट में इस प्रस्ताव को रखा गया था. तब सिंडिकेट के सदस्यों ने प्रस्ताव के अध्ययन के लिए समय मांगा था और अगली बैठक में इस प्रस्ताव को उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया था. तब तक तत्कालीन कुलपति के नीतिगत फैसले पर राजभवन द्वारा रोक लगा दी गई. फाउंडेशन की ओर से मविवि के वर्तमान कुलपति प्रो. कमर अहसन को भी इस प्रस्ताव का डीपीआर कुछ महीने पूर्व सौंपा गया है. नव नियुक्त कुलपति को दिए गए प्रस्ताव पर मविवि के कुल सचिव डॉ. नलीन कुमार शास्त्री ने कहा कि प्रस्ताव के अध्ययन के बाद ही कुछ भी कहना श्रेयस्कर होगा. वैसे मामला मविवि की भूमि को लीज पर देने का है, इसलिए इसमें कुलाधिपति व राज्य सरकार के स्तर से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

बोधगया फाउंडेशन द्वारा तैयार प्रस्ताव में 300 बेड के अस्पताल के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज, आई इंस्टीच्यूट, आईटीआई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की स्थापना के अलावा मविवि परिसर स्थित उच्च विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन भी शामिल है. उक्त पूरी व्यवस्था का संचालन चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत किया जाना है. इसमें भंसाली ट्रस्ट, आरती फाउंडेशन व मगध विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है. बोधगया फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित इस मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायो कमेस्ट्री, पैथॉलाजी, माइक्रो बायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन आदि विषयों की पढ़ाई होगी. पहले चरण में पांच वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम के तहत 150 छात्रों के नामांकन का प्रस्ताव है. वहीं नर्सिंग कॉलेज में 60 छात्रों का नामांकन होगा. इसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. अगर यह योजना क्रियान्वित होती है, तो इससे निश्चय ही बिहार-झारखंड के लोगों को लाभ मिलेगा. अस्पताल में कैंसर सहित अन्य रोगों के निदान की भी व्यवस्था होगी. इसमें जरूरतमंदो के लिए निःशुल्क चिकित्सा का भी प्रस्ताव है. बिहार-झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे उच्चस्तरीय सुविधायुक्त अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की कमी है.

गौर करने वाली बात ये भी है कि इससे पहले भी मविवि के समक्ष ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की हीला-हवाली और उदासीनता के कारण कोई भी प्रस्ताव परवान नहीं चढ़ सका. जब देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थान आईआईएम को बोधगया लाया जा रहा था, तब भी मविवि प्रशासन को इससे आपत्ति थी, लेकिन बिहार सरकार के कड़े रुख के कारण बोधगया में आईआईएम की स्थापना संभव हो सकी.■

शरद यादव की बग़ावत के बाद

जदयू के लिए कठिन होगी कोसी की डगर

सूबे में जदयू व भाजपा गठबंधन की सरकार गठन के बाद कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा जदयू के लिए जिला अध्यक्ष विहिन हो गया. साथ ही यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के अभिलाषी कार्यकर्ता शरद यादव के साथ खड़े हो गए. हालांकि अभी कई ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो शरद यादव के साथ खड़े हैं और नीतीश के लिए भी विश्वसनीय बने हुए हैं. ऐसे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे. अब तक भाजपा की ताकत व जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही कोसी क्षेत्र में संगठन का विस्तार किया जाता रहा है. लेकिन अब राजद व कांग्रेस की ताकत व जनाधार को झटकने की रणनीति को लेकर जदयू को अपने संगठन का मुखिया तय करना पड़ेगा. अभी जदयू के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा में मजबूत पकड़ व व्यापक जनाधार वाले जिला कप्तान की नियुक्ति की जाय.

संजय सोनी

गठबंधन के समीकरण में बदलाव और जनता दल (यूनाईटेड) से शरद यादव की बगावत के बाद अब कोसी क्षेत्र में राजग गठबंधन के लिए 2019 का आगामी लोकसभा चुनाव व 2020 का विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल हो गया है. खासकर राजग गठबंधन के बिहार के प्रमुख घटक दल जदयू को कोसी क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को रिऑर्गेनाईज्ड व रिफ्रेस करने की जरूरत है. राज्यसभा सांसद शरद यादव की बगावत के बाद सहरसा जिला अध्यक्ष धनिकलाल मुखिया, प्रखंड कहरा अध्यक्ष सह जिला पार्षद धीरेन्द्र यादव समेत कई अन्य सांगठनिक पदाधिकारियों ने भी नीतीश कुमार के फैसले का विरोध किया था. स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पर नीतीश के खिलाफ और शरद यादव के पक्ष में माहौल बन गया है.

सूबे में जदयू व भाजपा गठबंधन की सरकार गठन के बाद कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा जदयू के लिए जिला अध्यक्ष विहिन हो गया. साथ ही यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के अभिलाषी कार्यकर्ता शरद यादव के साथ खड़े हो गए. हालांकि अभी कई ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो शरद यादव के साथ खड़े हैं और नीतीश के लिए भी विश्वसनीय बने हुए हैं. ऐसे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे. अब तक भाजपा की ताकत व जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही कोसी क्षेत्र में संगठन का विस्तार किया जाता रहा है. लेकिन अब राजद व कांग्रेस की ताकत व जनाधार को झटकने की रणनीति को लेकर जदयू को अपने संगठन का मुखिया तय करना पड़ेगा. अभी जदयू के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा में मजबूत पकड़ व व्यापक जनाधार वाले जिला कप्तान की नियुक्ति की जाय. ऐसे छवि के व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपने की जरूरत है, जिसका सभी वर्गों में मजबूत पकड़ व व्यापक जनाधार हो. जिला अध्यक्ष के मनोनयन को लेकर जो चर्चा स्थानीय राजनीतिक हलकों में छिड़ी है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू की ताकत राजद व भाजपा से ज्यादा हो सकती है. जदयू के नए जिला अध्यक्ष के मनोनयन को लेकर वैश्य समाज के बड़े नेता व महिषी के पूर्व विधायक गुंजेश्वर साह और सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व जदयू विधायक डॉ. अरुण कुमार यादव के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. सहरसा जिला अध्यक्ष पद के लिए गुंजेश्वर साह सूबे के मुखिया सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की पसंद हैं. वहीं नीतीश सरकार के मंत्री दिनेश चन्द्र यादव पूर्व विधायक डॉ. अरुण कुमार यादव के पक्ष में खड़े हैं. कहा जा रहा है कि इनमें से गुंजेश्वर साह का पलड़ा भारी है और उनका जिला अध्यक्ष बनना करीब-करीब तय है. अपनी बेबाकी, बेदाग व ईमानदार छवि, कर्मठता एवं निष्ठा को लेकर गुंजेश्वर साह की एक अलग पहचान रही है. क्षेत्र के विकास के लिए इनके लड़ाकू स्वभाव से हर कोई अवगत है. महिषी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोसी नदी के बलुआहा घाट पर पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ पूर्व विधायक गुंजेश्वर साह भी याद किए जाते हैं. वहीं पूर्व विधायक डॉ. अरुण कुमार यादव की पहचान पूर्व सांसद सह बिहार सरकार के मंत्री दिनेश चन्द्र यादव के चहेते नेता के रूप में रही है. गौरतलब है कि दिनेश चन्द्र यादव के खगड़िया सीट से सांसद बनने के बाद ही सिमरी बख्तियारपुर की खाली सीट से अरुण कुमार यादव विधायक बने थे. लेकिन 2014 में दिनेश चन्द्र यादव के खगड़िया सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद डॉ. अरुण कुमार को फिर से सीट छोड़ना पड़ा था.

डॉ. अरुण कुमार
पूर्व विधायक

गुंजेश्वर साह
पूर्व विधायक

दिनेश चंद्र यादव
पूर्व सांसद

सार्वजनिक रूप से भले ही जदयू ये दिखा रही हो कि उसे राज्यसभा सांसद शरद यादव की बगावत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है. कोसी की राजनीति कब किस करवट लेगी यह कहना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जदयू को कमर कसना पड़ेगा. अब तक राज्यसभा सांसद शरद यादव व पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव के मुताबिक ही कोसी के सहरसा में जदयू का संगठन चलता रहा है. लेकिन शरद यादव अब कोसी में राजद को मजबूत करने में लग गए हैं. वे अब पूरी तरह से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इशारे पर चल रहे हैं. इसके कारण अब जदयू के लिए घर का भेदी लंका ढाए जैसी स्थिति बन गई है. इधर भाजपा भी कोसी में अंदरूनी कलह से परेशान है. नए जिला अध्यक्ष के रूप में नीरज गुप्ता की ताजपोशी के बाद गुटबंदी बढ़ती जा रही है, जिसपर भाजपा को अनुशासनिक लगाम लगाने की जरूरत है.■

feedback@chauthiduniya.com

दिनकर के नाम पर दिए जाने वाले सम्मान में अनियमितता

सुरेश चौहान

यूं तो देशभर में कई महान साहित्यकारों की विरासत खतरे में है. लेकिन इनमें से कई ऐसे भी हैं, जिनके गांव-घर में ही उनके विचारों की सार्थकता सवालों के घेरे में है. ऐसा ही कुछ दिनकर के साथ भी हो रहा है. जिस रामधारी सिंह दिनकर ने समाज और सियासत के हित में अपना कलम चलाकर सुषुप्त सामाजिक चेतना को झकझोरने का काम किया था, उसी दिनकर के अपने लोग आज उनके विचारों की तिलांजलि दे रहे हैं. दिनकर के नाम पर दिए जाने वाले सम्मान की पारदर्शिता और सार्थकता आज सवालों के घेरे में है.

दरअसल, बेगूसराय के ख्यातिप्राप्त विद्वतजन, समाजसेवी एवं साहित्यकारों ने जिलाधिकारी के सहयोग से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से दिनकर सम्मान समारोह समिति का गठन किया था. समिति के गठन के लिए तत्कालीन जिला पदाधिकारी रामेश्वर सिंह ने 1992 में पहल की. लेकिन इसी बीच उनका स्थानान्तरण हो गया. नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी प्रफुल्ल रंजन सिन्हा ने इस कार्य को आगे बढ़ाया. ख्यातिप्राप्त गांधीवादी चिंतक व समाजसेवी स्वर्गीय बैजनाथ चौधरी की अध्यक्षता में नामचीन साहित्यकार डॉ. आनन्द नारायण शर्मा, हिन्दी, उर्दू एवं मैथिली के विद्वान स्वर्गीय फजलुर्रहमान हाशमी, स्वर्गीय अखिलेश्वर कुंवर, स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह आदि ने दिनकर सम्मान समारोह समिति की स्थापना की. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष दिनकर जयंती (23 सितम्बर) के अवसर पर एक राष्ट्रीय फलक के एवं एक बेगूसराय जनपद के चयनित साहित्यकारों को क्रमशः दिनकर राष्ट्रीय सम्मान एवं दिनकर जनपदीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाएगा. लेकिन वर्तमान में अपने ही जनपद में राष्ट्रकवि दिनकर उपेक्षित हैं और उनके नाम पर दिए जाने वाले ये सम्म्मान सवालों के घेरे में हैं. दिनकर की 109वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष भी 23 सितम्बर को कार्यक्रम का आयोजन हुआ. लेकिन असलियत में यह फॉर्मलिटी से ज्यादा नहीं था.

जनपद में कार्यक्रम द्वारा दिनकर को श्रद्धांजलि दिए जाने के मामले में लोग आज भी जिला पदाधिकारी विमल कीर्ति सिंह एवं हरजोत कौर के कार्यालय को याद करते हैं.

1997 में समिति के पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी विमल कीर्ति सिंह के प्रयासों से ही राष्ट्रीय उच्चपथ 31 एवं 28 के मिलन स्थल जीरो माइल पर राष्ट्रकवि की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई और जीरो माइल को दिनकर चौक का नाम दिया गया. उन्होंने ही जन सहयोग से एक स्मारिका प्रकाशित कराई और उसमें विज्ञापनदाताओं के सहयोग से प्राप्त हुई एक बड़ी राशि को बैंक में एफडी कराया गया. उसी राशि के सूद से समारोह का आयोजन होता रहा है. उनके बाद वर्ष 2000 में समिति के पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हरजोत कौर ने दिनकर के नाम पर दिए जाने वाले उक्त दोनों सम्मानों की देय राशि में इजाफा किया. साथ ही पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक चयन प्रक्रिया स्थापित की. जिसके तहत अखबार में विज्ञापन देकर रचना एवं आवेदन (बायोडाटा) आमंत्रित किया गया. इस पहल की काफी सराहना हुई. लेकिन हरजोत कौर के स्थानान्तरण के बाद यह प्रक्रिया बन्द कर दी गई. फलतः चयन की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा. वर्ष 2012 में समिति के पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समिति के सामने यक्षप्रश्न खड़ा कर इसके निबंधन, नियमावली और सरकार से प्राप्त होने वाली राशि आदि के संबंध में जानकारी मांगी. समिति के पदाधिकारी यह जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने समिति के अध्यक्ष पद से अपने को अलग कर लिया. जिला पदाधिकारी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद समिति स्वछन्द हो गई और बिना पारदर्शिता और मापदंड अपनाए पुरस्कार के लिए साहित्यकारों का चयन होने लगा. बुद्धिजीवियों ने चयनित साहित्यकारों पर नहीं वरन् चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया. इन सब का परिणाम ये हुआ कि आम लोग भी इससे अलग होने लगे. यह इससे समझा जा सकता है कि इस साल 23 सितम्बर को दिनकर भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मात्र 67 व्यक्ति ही उपस्थित थे. बुद्धिजीवियों की इस नगण्य उपस्थिति पर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त आलोक धन्वा की टिप्पणी ने माहौल को और हास्यास्पद बना दिया. दूसरी ओर, दिनकर भवन के जीर्णोद्धार के बाद इसे दिनकर कला भवन का नाम मिला. कई बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि 'दिनकर भवन' दिनकर को समर्पित नाम लगता था, लेकिन अब इसका नाम 'दिनकर कला भवन' होने से इसकी व्यापकता सिमट कर सिर्फ कला पर आ गई है, जिससे राष्ट्रकवि के नाम की व्यापकता का अवमूल्यन हुआ है.

राष्ट्रकवि की छवि का अवमूल्यन करने में बिहार सरकार एवं स्थानीय सांसद की भी अहम भूमिका रही है. दिनकर के गांव सिमरिया की घोर अपेक्षा जारी है. इस गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, साथ ही इसे राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम का पुरस्कार भी मिला है. और तो और इसे स्थानीय सांसद डॉ. भोला सिंह ने गोद भी लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद यहां सड़क, नाला, पेयजल, जल निकासी, बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा आदि की स्थिति अत्यन्त जर्जर है. यहां किसी भी तरह से निर्मलग्राम या आदर्श ग्राम की झलक देखने को नहीं मिलती है. सांसद ने तो अपने इस गोद लिए गांव के विकास के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है.■

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178

Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg.: CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

सजग रहकर रोका जा सकता है गिरते बालों को
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. प्रणव कुमार
प्लास्टिक सर्जन, एमबीबीएस, एमसीएच (पीएमसीएच)

जीवन रेखा प्लास्टिक सर्जरी सेन्टर
बोरिंग रोड, विवेकानन्द मार्ग, पटना

डॉ. प्रणव कुमार जिनका बोरिंग रोड पटना स्थित विवेकानन्द मार्ग में जीवन रेखा नाम का क्लिनिक है और खुद पीएमसीएच में कार्यरत है ने बातचीत के दौरान बताया कि सही मार्गदर्शन मिले तो गंजापन से बचा जा सकता है। डॉ. प्रणव कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लान्टेशन, पुरूषों में ब्रेस्ट बढ़ने की समस्या के विशेषज्ञ हैं और बताते है कि सही खान पान हो तो इन सबसे बचा जा सकता है। इनकी एक वजह उन्होंने अनुवांशिकता को तो बताया ही साथ ही साथ विटामिन "ई" की कमी, ड्रैन्ड्रप का सही समय पर ईलाज नहीं करवाना बताया उन्होंने इका पीआरपी तकनीक द्वारा गिरते बालों पर रोक लगाने की बात कही। वहीं डॉ. प्रणव ने बताया कि बाहर में बालों का प्रत्यारोपण संबंधी ईलाज लाख-डेढ़ लाख दो लाख हैं वहीं पटना में यह 50 से 75 हजार के कम दर पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हम इसका इलाज FU तकनीक से करते हैं।

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.

ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets

SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

बालों को झड़ने से रोकने के लिए कुछ उपाय - • बालों को दिन में कम से कम 2-3 बार कंघी करें, इससे आपके बाल कम से कम उलझेंगे और बाल कम टूटेंगे। • जब भी आप बाहर धूप में जाएं तो अपने साथ छाता लेकर जाएं या फिर अपने बालों को कपड़े से पूरी तरह ढक लें। • बहुत गर्म पानी से बाल ना धोएं, वरना आपके बाल अधिक खराब हो जाएंगे और जल्दी टूटने लगेंगे। • बालों को टूटने से बचाने के लिए आपको डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, सल्फर, विटामिन सी, के अलावा विटामिन बी से युक्त खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। • बालों को टाइट बांधना, रोलर्स व ब्लो ड्रायर व आयरन के ज्यादा इस्तेमाल करने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं। •बालों को सही पोषण न मिलने से भी बाल झड़ने लगते हैं, समय-समय पर बालों में मेंहदी लगानी चाहिए या फिर बालों को पोषण देने के लिए दही भी लगा सकते हैं। • बालों को मजबूत बनाने और टूटने से बचाने के लिए आपको सप्ताह में कम से कम दो बार बालों की जड़ों में आंवला, बादाम, आलिव आयल, नारियल का तेल, सरसो का तेल इत्यादि में से कोई एक लगाना चाहिए। इससे बालों का झड़ना, बाल पतले होना, डैंड्रफ, दोमुंहे बाल व उम्र से पहले बालों का सफेद होने जैसी समस्या से निपटा जा सकता है। ■ भारती

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

वरिष्ठ साहित्यकारों को तकनीक से परहेज़ क्यों?

अनंत विजय

पिछले दिनों कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों से बात हो रही थी. उस बातचीत में एक आलोचक और एक कवि-आलोचक भी थे. बातचीत फेसबुक और साहित्य से होते-होते हिंदी में तकनीक के इस्तेमाल तक पहुंच गई. मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये दोनों आलोचक ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते थे. हिंदी के कई स्थापित लेखक ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उन्हें इस बात का मलाल भी नहीं है, बल्कि बात इस तरह से करते हैं कि गोया उन्हें इस बात का फ़ख्र हो कि उनका ईमेल अकाउंट नहीं है. आज जब पूरी दुनिया फिजिकल से वर्चुअल की ओर बढ़ रही है, ऐसे में हिंदी के इन वरिष्ठ लेखकों का तकनीक को लेकर हठ उचित नहीं प्रतीत होता है. इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि वो समय के साथ कदमताल नहीं कर पाएं और पाठकों का मिजाज समझने में पीछे रह जाएं. विदेशों में ई-रीडर्स की बढ़ती तादाद का फायदा उठाने के लिए प्रकाशकों ने बेहतर रणनीति बनाकर काम किया जिनके नतीजे भी उनको मिले. किसी बड़े लेखक की कोई अहम कृति प्रकाशित होने वाली होती है, तो प्रकाशक लेखकों से आग्रह कर प्रकाशन के पहले ई-रीडर्स के लिए छोटी-छोटी कहानियां लिखवाते हैं. जो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होती है. इसका फायदा यह होता है कि छोटी कहानियों की लोकप्रियता से लेखक के पक्ष में एक माहौल बनता है और प्रकाश्य कृति के लिए पाठकों के बीच उत्सुकता पैदा होती है. जब उत्सुकता अपने चरम पर होती है, तो प्रकाशक बाजार में उक्त लेखक की किताब पेश कर देता है. मशहूर और बेहद लोकप्रिय ब्रिटिश थ्रिलर लेखक ली चाइल्ड ने भी अपने उपन्यास के पहले कई छोटी-छोटी कहानियां सिर्फ डिजीटल फॉर्मेट में लिखी. उन्होंने साफ तौर पर माना कि ये कहानियां वो अपने आगामी उपन्यास के लिए पाठकों के बीच एक उत्सुकता का माहौल बनाने के लिए लिख रहे थे. चाइल्ड के मुताबिक दौड़ में बने रहने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था. इन स्थितियों की तुलना में अगर हम हिंदी लेखकों की बात करें, तो वहां एक पिछड़ापन नजर आता है. ज्यादातर लेखकों की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है. दो-चार प्रकाशकों को छोड़ दें, तो हिंदी के प्रकाशकों की भी वेबसाइट नहीं है. नतीजा यह कि हिंदी में लेखकों पर पाठकों की पसंद का दबाव नहीं बन पाता और वो अपनी रफ्तार से लेखन करते हैं. फिर रोना रोते हैं कि पाठक नहीं. इस बात को लक्षित किया जा सकता है कि फोर जी तकनीक के प्रसार, इंटरनेट और स्मार्ट फोन के सस्ता होने से उसके उपभोक्ताओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. फोन बनाने वाली कंपनियां बड़े साइज की स्क्रीन युवाओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर कर रही हैं.

सामाजशास्त्रीय विश्लेषण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इक्कीसवीं सदी के पाठकों की रुचि में सत्तर और अस्सी के दशक के पाठकों की रुचि में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है. सन 1991 को हम इस रुचि का प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं. हमारे देश में 1991 से अर्थव्यस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया और उससे करीब सात साल पहले देश में संचार क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी. हमारे देश के लिए ये दो बेहद अहम पड़ाव थे, जिनका देश की साहित्य संस्कृति पर बेहद गहरा असर पड़ा. संचार क्रांति और उदारीकरण का

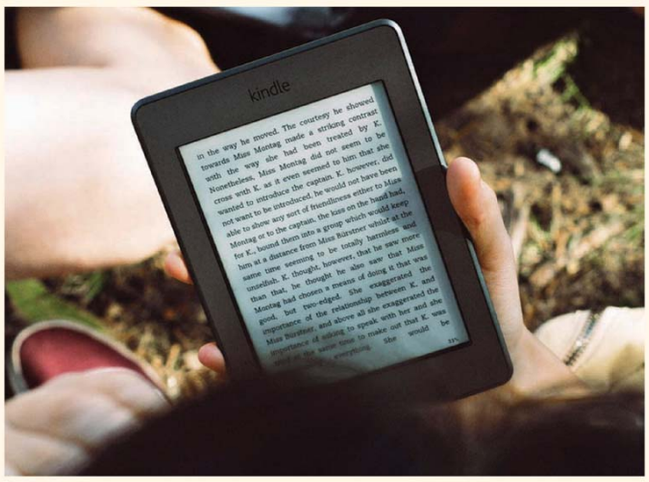

आज के ई-रीडिंग और ई-राइटिंग के दौर के पहले लेखक साल में एक कृति की रचना कर लेते थे, तो उसे बेहद सक्रिय लेखक माना जाता था. हिंदी में भगवानदास मोरवाल लगभग हर साल एक उपन्यास लिख लेते हैं, उनकी सक्रियता से हिंदी जगत चौंकता रहता है. जॉन ग्रीशम जैसा लोकप्रिय लेखक भी साल में एक ही किताब लिखता था. पाठकों को भी साल भर अपने प्रिय लेखकों की कृति का इंतजार रहता था. पुस्तक छपने की प्रक्रिया में भी वक्त लगता था. लेकिन वक्त बदला, स्टाइल बदला, लेखन और प्रकाशन की प्रक्रिया बदली. अब तो हिंदी में भी ई-लेखन का दौर आ गया है. ई-लेखन और ई-पाठक के इस दौर में पाठकों की रुचि में आधारभूत बदलाव देखने को मिल रहा है. इंटरनेट के इस दौर में पाठकों का लेखकों से भावनात्मक सम्बन्ध की जगह सीधे संवाद ने ले ली. ऑनलाइन रहकर लेखक पाठकों से बात करते हैं और उनकी पसंद जानते हैं, ट्वीटर पर सवालों के जवाब देते हैं, फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट कर पाठकों की प्रतिक्रिया हासिल करते हैं.

असर यह हुआ कि संस्कृति और साहित्य भी ग्लोबल और लोकल मिलकर ग्लोकल हो गई. बाजारवाद और नवउदारवाद के प्रभाव में भारत में आम जनता की और खासकर युवा वर्ग की रुचि में बदलाव तो साफ तौर पर रेखांकित किया जा सकता है. युवा वर्ग और इन दशकों में जवान होती पीढ़ी में धैर्य कम होता चला गया और एक तरह से इंस्टैंट का जमाना आ गया चाहे वो कॉफी हो, नूडल्स हो या फिर साहित्यक उपन्यास. यह अधीरता कालांतर में और बढ़ी. यह लगभग वही दौर था जब हमारे देश के आकाश को निजी टेलीविजन के तरंगों के लिए खोल दिया गया. मतलब यह है कि देश में कई देशी-विदेशी मनोरंजन और न्यूज चैनलों ने अपना प्रसारण शुरू किया. यह वही वक्त था जब हिंसा प्रधान फिल्मों की जगह बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों ने ली. मार-धाड़ वाली फिल्मों की बजाय शाहरुख काजोल की रोमांटिक फिल्मों को जबरदस्त सफलता मिली. यह सब बताने का तात्पर्य यह है कि नब्बे के दशक में हमारे देश की लोगों की पसंद बदलने लगी.

आज की युवा पीढ़ी की आदतों को देखें, तो वो ऑन द मूव पढ़ना चाहती है. उसके लिए मोबाइल फोन या फिर किंडल से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है. किंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताबों के ई-वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं. पूरी दुनिया में ई-बुक्स की सफलता के बरक्श अगर हम हिंदी प्रकाशन की तुलना करते हैं, तो वो काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है. हिंदी के कुछ प्रकाशकों ने ई-बुक्स में बेहतर काम किया है, लेकिन ज्यादातर अपने प्रकाशनों को ई-फॉर्मेट में नहीं ला पाए हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अपनी स्थापना के सत्तावन साल बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने पहला ईबुक विवेकानंद पर जारी किया था.

2007 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनी अमेजॉन ने इलेक्ट्रानिक बुक रीडर किंडल लॉंच किया था. शुरुआत में इसकी कीमत तकरीबन पच्चीस हजार रुपए रखी गई थी. ई-बुक्स की लोकप्रियता को बढ़ाने में किंडल का खासा योगदान है. अमेजॉन ने बहुत सोच-समझकर ये रीडिंग डिवाइस लांच किया था. ऑनलाइन कारोबार करने वाली इस कंपनी के पास तकरीबन दस लाख किताबों के इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट के अधिकार थे. कंपनी ने उसको भुनाने के लिए बाजार में किंडल को उतारा, जो काफी लोकप्रिय हुआ. किंडल के साथ-साथ कई किताबें प्री लोडेड आती हैं और बाद में आप चाहें, तो नई से नई किताबें खरीदकर डाउनलोड कर सकते हैं. किंडल पर मौजूद ई बुक्स बाजार से खरीदी गई किताबों से सस्ती होती हैं और इनको रखने में आसानी होती है. हजारों किताबें एक छोटे से टेबलेटनुमा डिवाइस में स्टोर की जा सकती हैं. एक बार डाउनलोड कर लेने के बाद इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है. जब चाहें जहां चाहें पाठक अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं. इस डिवाइस को किसी कंप्यूटर या तार से जोड़ने का झंझट भी नहीं है. इस डिवाइस पर अखबारों का सब्सक्रिप्शन लेकर अखबार भी पढ़े जा सकते हैं. अब तो आंखों को सहूलियत प्रदान करनेवाले डिवाइस भी आ गए हैं.

आज के ई-रीडिंग और ई-राइटिंग के दौर के पहले लेखक साल में एक कृति की रचना कर लेते थे, तो उसे बेहद सक्रिय लेखक माना जाता था. हिंदी में भगवानदास मोरवाल लगभग हर साल एक उपन्यास लिख लेते हैं, उनकी सक्रियता से हिंदी जगत चौंकता रहता है. जॉन ग्रीशम जैसा लोकप्रिय लेखक भी साल में एक ही किताब लिखता था. पाठकों को भी साल भर अपने प्रिय लेखकों की कृति का इंतजार रहता था. पुस्तक छपने की प्रक्रिया में भी वक्त लगता था. लेकिन वक्त बदला, स्टाइल बदला, लेखन और प्रकाशन की प्रक्रिया बदली. अब तो हिंदी में भी ई-लेखन का दौर आ गया है. ई-लेखन और ई-पाठक के इस दौर में पाठकों की रुचि में आधारभूत बदलाव देखने को मिल रहा है. इंटरनेट के इस दौर में पाठकों का लेखकों से भावनात्मक सम्बन्ध की जगह सीधे संवाद ने ले ली. ऑनलाइन रहकर लेखक पाठकों से बात करते हैं और उनकी पसंद जानते हैं, ट्वीटर पर सवालों के जवाब देते हैं, फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट कर पाठकों की प्रतिक्रिया हासिल करते हैं. हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकारों में से कुछ ही फेसबुक पर नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनमें से ज्यादातर फेसबुक का इस्तेमाल अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी विचारधारा के पोषण के लिए या फिर प्रवचन के लिए करते हैं. फेसबुक पर साहित्यकारों की मौजूदगी को लेकर एक दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है. चार साल पहले की बात है, दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला के दौरान एक साथी पत्रकार, जो कवि-कथाकार, आलोचक आदि भी हैं, मेरे यह कहने पर कि लेखकों को फेसबुक और ट्वीटर पर होना चाहिए, भड़क गए थे. उनका तर्क था कि अगर हम फोन उठाकर बात नहीं कर सकते, तो फिर फेसबुक पर संवाद की क्या सार्थकता है. उसके बाद उन्होंने बेहद गंभीरता के साथ यह सवाल भी खड़ा किया कि इन माध्यमों से सामाजिक सरोकार कैसे जुड़ते हैं. उस गोष्ठी को याद करते हुए हंसी भी आती है, क्योंकि इन दिनों उनके कई घंटे फेसबुक पर ही गुजरते हैं. जरूरत किसी माध्यम को खारिज करने की नहीं, बल्कि उसका स्वागत करने की है. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

राशन वितरण में हुई अनियमितता का पता लगाएं

चौथी दुनिया ब्यूरो

ग्रामीण स्तर पर जिस किसी एक विभाग या कार्य में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो है राशन वितरण. लोगों की जागरूकता में कमी और राशन वितरक की मनमानी के कारण लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता और सरकार द्वारा भेजी गई राशन सामग्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. चूंकि इस योजना में भी जिला स्तर से लेकर प्रखंड और पंचायत तक अधिकारियों का चेन शामिल होता है और सभी राशन वितरक से जुड़े होते हैं, इसलिए आम लोगों की आवाज भी अनसुनी रह जाती है. लेकिन हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए, जब सूचना के अधिकार के द्वारा राशन वितरण के मामलों में हुई अनियमितता सामने आई और उनपर कार्रवाई हुई. हम आपको बता रहे हैं उस आरटीआई आवेदन के बारे में, जिसके जरिए आप राशन वितरण में हुए गड़बड़झाले का पता लगा सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं..... का निवासी हूं. मेरा कार्ड नं..... है. यह कार्ड राशन दुकान संख्या..... और किरासन तेल डिपो संख्या..... में रजिस्टर है.

1. विभाग/कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे राशन कार्ड पर प्रत्येक माह में जारी किए गए राशन एवं किरासन तेल का ब्यौरा निम्नलिखित तथ्यों के साथ दें:

क. महीना
ख. जारी राशन एवं किरासन तेल की मात्रा
ग. राशन एवं किरासन तेल दिए जाने की तिथि
घ. प्रत्येक के लिए भुगतान की गई राशि
ड. भुगतान रसीद की छायाप्रति

2. उपरोक्त राशन की दुकान और किरासन तेल डिपो के पिछले छ: माह के निम्नलिखित रिकॉर्डों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं:

क. मास्टर कार्ड रजिस्टर
ख. दैनिक बिक्री रजिस्टर
ग. दैनिक स्टॉक रजिस्टर
घ. मासिक स्टॉक रजिस्टर
ड. निरीक्षण पुस्तिका
च. कैश मेमो

3. उपरोक्त राशन दुकान व किरासन तेल डिपो के खिलाफ पिछले पांच सालों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सभी शिकायतों की सूची निम्नलिखित विवरण के साथ दें:

क. शिकायत करने वाले का नाम
ख. शिकायत का संक्षिप्त विवरण
ग. शिकायत की तारीख
घ. शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
ड. शिकायत पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद व पता

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

जन्मदिन- 22 अक्टूबर, 1900
पुण्यतिथि- 19 दिसम्बर, 1927

जयंती विशेष

देश सेवा के लिए पुनर्जन्म की इच्छा रखने वाला क्रांतिकारी अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान

चौथी दुनिया ब्यूरो

आज़ादी से पहले अंग्रेज हिंदू-मुस्लिम भावनाएं भड़काने का काम करते रहते थे, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें. ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई थी, जहां कुछ मुस्लिम युवक वहां के आर्य समाज मंदिर पर हमला करने के लिए एकत्रित हुए थे. लेकिन वे जैसे ही आगे बढ़े, मंदिर प्रांगण में बैठे एक युवक ने अपना पिस्तौल निकालकर उसे भीड़ के सामने तानते हुए बोला, 'मैं कट्टर मुसलमान हूं, परन्तु इस मन्दिर की एक-एक ईंट मुझे प्राणों से प्यारी है. मेरी नजर में मन्दिर और मस्जिद की प्रतिष्ठा बराबर है. अगर किसी ने भी इस मन्दिर की ओर निगाह उठाई, तो वो गोली का निशाना बनेगा. अगर तुमको लड़ना है, तो बाहर सड़क पर चले जाओ और खूब दिल खोल कर लड़ लो. उस युवक की इस सिंह गर्जना से सबके होश उड़ गए और किसी का साहस नहीं हुआ कि वो आर्य समाज मन्दिर की तरफ बढ़ सके.' उस युवक का नाम था, अशफाक उल्ला खान, जिसे भारत के प्रसिद्ध अमर शहीद क्रांतिकारियों में गिना जाता है. अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान पहले मुस्लिम थे, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी की सज़ा हुई थी.

अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान का जन्म 22 अक्टूबर, 1900 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर ज़िले के शहीदगढ़ नामक स्थान पर एक समृद्ध छीन परिवार में हुआ था. इनके पिता का नाम मोहम्मद शफ़ीक़ उल्ला ख़ान और मां का नाम मजहूरुन्निशां बेगम था. परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे. लेकिन अशफ़ाक़ को विदेशी दासता विद्यार्थी जीवन से ही खलती थी. वे देश के लिए कुछ करने को बेताब रहते थे. अशफाक़ का मन पढ़ने-लिखने में नहीं लगता था. खनौत में तैरने, घोड़े की सवारी करने और भाई की बन्दूक लेकर शिकार करने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था. देश की भलाई और क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी कहानियां वे बहुत ध्यान से सुनते और पढ़ते थे. उन्हें कविता लिखने का भी बहुत शौक़ था. उन्होंने स्वदेशानुराग से सराबोर बहुत सी कविताएं भी लिखी थीं. कविता में वे अपना उपनाम 'हसरत' लिखते थे. उनकी लिखी हुई देशभक्ति कविताएं अदालत आते-जाते समय अक्सर 'काकोरी कांड' के क्रांतिकारी गाया करते थे. हालांकि उन्होंने

कभी भी अपनी कविताओं को प्रकाशित कराने की चेष्टा नहीं की. कविता प्रकाशित न कराने को लेकर सवाल पूछे जाने पर एक बार उन्होंने कहा था, 'हमें नाम पैदा करना तो है नहीं. अगर नाम पैदा करना होता, तो क्रान्तिकारी का काम छोड़ कर लीडरी न करता?'

देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान बहुत प्रभावित हुए. धीरे-धीरे उनमें क्रान्तिकारी भाव पैदा होने लगा. वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे, जो क्रान्तिकारी दल का सदस्य हो. उस समय 'मैनपुरी षड्यंत्र' का मामला चल रहा था. अशफ़ाक़ शाहजहांपुर में ही पढ़ाई कर रहे थे. 'मैनपुरी षड्यंत्र' में शाहजहांपुर के ही रहने वाले एक नवयुवक के नाम का भी वारंट निकला था. वो नवयुवक थे, रामप्रसाद बिस्मिल. उनके बारे में जानकर अशफ़ाक़ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके शहर का लड़का अंग्रेजों से लोहा ले रहा है. अशफ़ाक़ उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं मिल सके. जब शाही एलान द्वारा सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए, तब बिस्मिल भी शाहजहांपुर आ गए. अशफाक़ ने उसने मिलकर षड्यंत्र के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाही, लेकिन पहले तो बिस्मिल ने टालमटोल कर दिया. लेकिन बाद में वे अशफ़ाक़ के व्यवहार और अंग्रेजों के प्रति नफरत से इतने प्रसन्न हुए कि उनको अपना बहुत ही घनिष्ट मित्र बना लिया. इस

अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान की एक प्रसिद्ध कविता

जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जायेगा,
जाने किस दिन हिन्दोस्तान आज़ाद वतन कहलायेगा?
बिस्मिल हिन्दू हैं कहते हैं फिर आऊंगा-फिर आऊंगा,
फिर आकर के ऐ भारत मां तुझको आज़ाद कराऊंगा.
जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं,
मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं,
हां खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा,
और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा.

प्रकार वे क्रान्तिकारी जीवन में आ गए. क्रान्तिकारी जीवन में पदार्पण करने के बाद से अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान सदा प्रयत्न करते रहे कि उनकी भांति और भी मुस्लिम नवयुवक क्रान्तिकारी दल के सदस्य बनें. वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे.

शुरू से ही अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान के जीवन पर महात्मा गांधी का प्रभाव था, लेकिन जब 'चौरी चौरा घटना' के बाद गांधीजी ने 'असहयोग आंदोलन' वापस ले लिया, तो उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंची. रामप्रसाद बिस्मिल और चन्द्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 8 अगस्त, 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी ख़ज़ाने को लूटने की योजना बनाई गई, ताकि अंग्रेजो से लोहा लेने के लिए हथियारों की व्यवस्था की जा सके. क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वह धन अंग्रेज़ों ने भारतीयों से ही हड़पा था. 9 अगस्त, 1925 को अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आज़ाद, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिन्द्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुन्द लाल और मन्मथ लाल गुप्त ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नजदीक 'काकोरी' में ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सरकारी ख़ज़ाने को लूट लिया. यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है. इस घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों ने अपना नाम बदल लिया था. अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान ने अपना नाम 'कुमारजी' रखा था. सरकारी खजाना लूटे जाने की घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पागल हो उठी और उसने बहुत से निर्दोषों को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया. बाद में कुछ अपनों की दगाबाजी के कारण इस घटना में शामिल सभी क्रांतिकारी पकड़े गए. लेकिन उस समय चन्द्रशेखर आज़ाद और अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान पुलिस के हाथ नहीं आए.

इस घटना के बाद अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान शाहजहांपुर छोड़कर बनारस चले गए और वहां दस महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया. उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई, ताकि वहां से कमाए गए पैसों से अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करते रहें. विदेश जाने के लिए उन्होंने दिल्ली के अपने एक पठान मित्र से संपर्क साधा. लेकिन वो दोस्त विश्वासघाती निकला. उसने इनाम के लालच में अंग्रेज़ पुलिस को सूचना दे दी और इस तरह अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान पकड़ लिए गए. जेल में अशफ़ाक़ को कई तरह की यातनाएं दी गईं. लेकिन जब उन पर यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ, तो अंग्रेज़ों ने तरह-तरह की चालें चलकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की. लेकिन अंग्रेज़ अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए. अंततः काकोरी कांड के अभियुक्त के रूप में 19 दिसम्बर, 1927 को फैजाबाद जेल में अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान को फांसी दे दी गई. इस तरह भारत का यह महान सपूत देशहित में कुर्बान हो गया. उनकी शहादत ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिन्दू-मुस्लिम एकता को और भी प्रगाढ़ता प्रदान की. ■

feedback@chauthiduniya.com

पत्रकारों पर हमले के विरोध में देशभर के प्रेस क्लबों में धरना

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली

पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरोध में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश भर के प्रेस कल्बों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. विभिन्न राज्यों की राजधानियों एवं कई शहरों में प्रेस क्लबों के बैनर तले पत्रकारों की हत्या एवं उनपर किए जा रहे हमलों के विरोध में उठी आवाज ने केंद्र व राज्य सराकारों का ध्यान आकर्षित किया. मीटिंग एवं धरना के अलावा कई जगह पत्रकारों ने ह्यूमन चेन बनाकर साकेतिक विरोध किया. इन कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न विचारों के पत्रकारों ने अभिव्यक्ति की आजादी के हक़ में आवाज उठाई. ये धरना-प्रदर्शन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ क्लब्स इन इंडिया, इंडियन वीमेन्स प्रेस कॉर्प्स, प्रेस एसोसिएशन, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस और इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन के द्वारा आयोजित किए गए. नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी ह्यूमन चेन निकाला गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई एवं परंजय गुहा ठाकुरता आदि पत्रकार शामिल हुए. इसके अलावा उर्दू समाचार पत्रों एवं चैनलों के पत्रकारों ने भी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. पत्रकारों ने सरकार से विभिन्न राज्यों में हुए हमलों एवं पत्रकारों की हत्या के संबध में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी. विभिन्न स्थानों पर धरने में पत्रकारों ने मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए और इसे 4 अक्टूबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया. इसे लेकर 5 अक्टूबर को विभिन्न राज्यों के प्रेस क्लबों के अध्यक्ष एवं अन्य पत्रकार नई दिल्ली में जमा हुए एवं भविष्य की रूप रेखा तैयार की.

प्रेस क्लब ऑफ कोलकाता

प्रेस क्लब ऑफ हरिद्वार

प्रेस क्लब ऑफ ओड़ीशा

प्रेस क्लब ऑफ इंदौर

प्रेस क्लब ऑफ जम्मू

प्रेस क्लब ऑफ गोरखपुर

प्रेस क्लब ऑफ त्रिपुरा

प्रेस क्लब ऑफ चेन्नई

प्रेस क्लब ऑफ अरुणाचल प्रदेश

इस दिवाली लॉज़िक नहीं सिर्फ़ मैज़िक होगा!

सीक्रेट सुपरस्टार करेंगे दिवाली पर गोलमाल

प्रवीण कुमार

दिवाली के मौके पर हर साल कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती हैं. जिनमें कुछ तो छप्पर फाड़कर पैसे कमाती हैं, तो किसी का दिवाला भी निकल जाता है. इस बार की दिवाली भी बॉलीवुड के लिए ख़ास होने जा रही है. जी हां, हर बार की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं. जिनमें रोहित शेट्टी–अजय देवगन की सफल फ्रेंचाईज गोलमाल की अगली कड़ी *गोलमाल अगेन* और आमिर खान–ज़ायरा वसीम की *सीक्रेट सुपरस्टार* आमने सामने होंगी.

एक तरफ जहां बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन गोलमाल करने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैं, जो कम बजट की फिल्मों को भी करोड़ो रुपए का फायदा कराने के लिए जाने जाते है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर जोरदार घमासान देखने को मिलेगा.

अगर हम *सीक्रेट सुपरस्टार* की बात करें, तो यह फिल्म आमिर खान और दंगल फेम ज़ायरा वसीम को लेकर काफी लंबे समय से दर्शकों के बीच चर्चा में है. फिल्म का ट्रेलर और गाने बहुत पहले ही रिलीज कर दिए गए थे.

> फिल्म के ट्रेलर से स्पष्ट है कि गोलमाल की यह कड़ी पहले से ज्यादा हंसी का ख़ज़ाना लेकर आ रही है, जिसे देखकर लोग सिनेमाघरों में लोटपोट हो जाएंगे. कई फिल्म समीक्षक अभी से यह अनुमान लगा रहे हैं कि *गोलमाल अगेन* आमिर खान की *सीक्रेट सुपरस्टार* के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है. इस फिल्म का कॉमेडी थीम तो दर्शकों की पसंद का है ही, इसमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है.

इस फिल्म में ज़ायरा वसीम मुख्य भूमिका में होंगी, वहीं आमिर खान एक बड़े कैमियो रोल में नज़र आएंगे. अद्वैत चंदन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म दिवाली के दिन ही यानि 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 20 से 25 करोड़ है. इस फिल्म के साथ ख़ास बात यह है कि इससे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जुड़े हैं, जिन्हें बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्मों का बादशाह कहा जाता है. इस लिहाज से फिल्म के सुपरहिट होने के चांस काफी ज्यादा हैं.

दूसरी ओर हैं, बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टरों में से एक रोहित शेट्टी, जिनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला रहा है. हालांकि पिछली दिवाली पर रिलीज हुई उनकी फिल्म *दिलवाले* उतना कमाल नहीं दिखा पाई, जिसकी उम्मीद थी. लेकिन फिर भी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था. इस बार वे गोलमाल सीरिज की फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो पहले से ही दर्शकों के बीच अपनी एक ख़ास छाप छोड़ चुकी है.

दिवाली के मौके पर कई फिल्में आपस में भिड़ती है. कोई करोड़ो में खेलता है, तो कोई दिवालिया हो जाता है. दिवाली के मौके पर साल 2001 में कोई भी बड़े बैनर की फिल्म रिलीज नहीं हुई. इसके अलावा लगभग हर साल दिवाली के मौके पर फिल्में रिलीज हुईं. आइए जानते हैं, दिवाली के मौके और उसके आस-पास रिलीज हुई फिल्मों और उनके हिट-फ्लॉप होने के बारे में...

दिवाली के किंग हैं शाहरुख़ खान-अजय देवगन

दिवाली के मौके पर हर साल कई बड़ी फिल्मों का बोलबाला होता है. सही मायने में देखा जाए, तो बड़े बैनर की फिल्मों को त्योहारों के सीजन में इसलिए रिलीज किया जाता है, ताकि फिल्म बड़े स्तर पर सुपरहिट होने के साथ-साथ करोड़ो का मुनाफा भी कमा सके. इससे निर्माता–निर्देशक को तो फायदा होता ही है, फिल्म के सभी कलाकारों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है. जाहिर सी बात है, जो हिट है, वही फिल्म इंडस्ट्री में टिक सकता है. दिवाली के मौके पर हिट फिल्में देने वाले कलाकारों की बात करें, तो इसमें शाहरुख खान और अजय देवगन सबसे ऊपर नजर आते हैं.

जी हां, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा किंग खान यानि शाहरुख खान की फिल्में हैं. शाहरुख ने दिवाली के मौके पर लगभग 11 फिल्में दी हैं और ये सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई हैं. इन फिल्मों में *बाज़ीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, वीर–जारा, डॉन, मोहब्बतें, ओम शांति ओम, रा–वन, जब तक है जान* और *हैप्पी न्यू इयर* शामिल हैं. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई हैं.

अजय देवगन का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. *जिगर* दिवाली पर रिलीज हुई अजय देवगन की पहली फिल्म थी. यह फिल्म हिट साबित हुई. इसे मिलाकर दिवाली के मौके पर अजय ने अब तक कुल 8 फिल्में दी हैं. जिनमें से 1993 में आई फिल्म *बेदर्दी* बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. लेकिन बाकी 7 फिल्में हिट रहीं. जिनमें *जिगर, बेदर्दी, सुहाग, ऑल द बेस्ट: फन विगेनस, गोलमाल–3, सन ऑफ सरदार, और शिवाय* शामिल हैं. वहीं इस साल दिवाली पर आने वाली *गोलमाल अगेन* के भी हिट होने की पूरी संभावना है. ■

गोलमाल अगेन के ट्रेलर और उसके गानों के रिलीज होने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों में ख़ासा उत्साह है. इसे लेकर ख़ुद अजय देवगन भी कह चुके हैं कि *इस दिवाली लॉजिक नहीं, सिर्फ उनका मैज़िक होगा.*

फिल्म के ट्रेलर से स्पष्ट हो गया है कि गोलमाल की यह कड़ी पहले से ज्यादा हंसी का ख़ज़ाना लेकर आ रही है, जिसे देखकर लोग सचमुच में सिनेमाघरों में लोटपोट हो जाएंगे. कई फिल्म समीक्षक अभी से यह अनुमान लगा रहे हैं कि *गोलमाल अगेन* आमिर खान की *सीक्रेट सुपरस्टार* के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है. इस फिल्म का कॉमेडी थीम तो दर्शकों की पसंद का है ही, इसमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है. जी हां, *गोलमाल अगेन* में गोलमाल सीरीज की पुरानी टीम के अलावा कुछ नए चहरे भी देखने को मिलेंगे. परिणीति चोपड़ा और तब्बू के अलावा नील नितिन मुकेश भी इसमें दिखाई देंगे. इस फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर भी शामिल किया गया है. फिल्म में एक्शन भी है और हिट गाने भी, जो पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है.

कई फिल्म समीक्षक तो यह भी कह रहे हैं कि *गोलमाल अगेन* अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है. 145 करोड़ की कमाई करने वाली सिंघम रिटर्न अजय देवगन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है. इस फिल्म को भी रोहित शेट्टी ने ही बनाया था. लेकिन रोहित शेट्टी की *गोलमाल अगेन* से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है. फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, परिणीति चोपड़ा, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, अरशद वारसी और कुनाल खेमू मुख्य किरदार में नज़र आएंगे.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली के मौके पर कौन सी फिल्म बाज़ी मारती है. फिलहाल, आप इस दिवाली हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार दिवाली पर होगा अजय–आमिर का टोटल धमाल. ■

feedback@chauthiduniya.com